चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 04 अप्रैल–10 अप्रैल 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

पूंजीपतियों ने लूट लिया देश का धन

असली राष्ट्रद्रोही

बैंकों की मिलीभगत से हड़प लिए पांच लाख करोड़ रुपये

शशि शेखर

मीडिया, राजनीति और कमोबेश पूरा समाज आजकल सांसद व कारोबारी विजय माल्या के 9 हज़ार करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर चर्चा कर रहा है. चर्चा इस बात की भी है कि बैंकों का लाखों करोड़ रुपये का कर्ज डूब चुका है. लेकिन, इस सब के बीच यह जानकारी शायद ही बाहर आ पाती है कि आखिर कौन हैं ये लोग, जिन्होंने बैंकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपये के ऋण को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) यानी डूबा हुआ धन बना दिया है. इससे भी बड़ी बात यह कि आखिर ये विलफुल डिफॉल्टर कौन हैं? दरअसल, बैंकों की शब्दावली में विलफुल डिफॉल्टर उन्हें कहते हैं, जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन वे जानबूझ कर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाते. ऐसे कर्जदारों को बैंक विलफुल डिफॉल्टर मानती है. दरअसल, ये विलफुल डिफॉल्टर ही जनता के पैसों के असली लुटेरे हैं. नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था में विकास के नाम पर, विकास के कथित मॉडल के नाम पर जिस तरीके से बैंकों ने अनाप-शनाप लोन देने शुरू किए, उसी का नतीजा है कि पिछले 25 साल के दौरान बैंकों का करीब 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए बन चुका है. जाहिर है, यह पैसा जनता का है. जनता की गाढ़ी कमाई का है, जो बचत या कर के रूप में बैंकों के पास जमा होता है.

लेकिन, सवाल यह है कि आखिर, सरकार, बैंक, आरबीआई या मीडिया की वह कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ये लोग इन विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम सार्वजनिक करने से हिचकते हैं. सवाल है कि क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि किस राज्य के किस बैंक के किस ब्रांच से किसने कितना पैसा लूटा. चौथी दुनिया आपको इस बार कुछ ऐसे ही विलफुल डिफॉल्टर, बैंकों के नाम, राज्यों के नाम बता रहा है जहां से आम आदमी की जेब से लाखों करोड़ रुपये निकाले गए और जिनका अब वापस मिलना नामुमकिन लगता है. विजय माल्या और उनके 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुर्खियों के बीच आज हम आपको बताते हैं कि माल्या की कम्पनी के अलावा 5,954 अन्य ऐसी विलफुल डिफॉल्टर कम्पनियां हैं, जिनके पास बैंकों का 60 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज बाकी है. करीब-करीब प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक बैंक की प्रत्येक ब्रांच से इन कम्पनियों ने पैसे लिए हैं. यह जानकारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) द्वारा इकट्ठा की गई सूचना से निकल कर सामने आई है. हालांकि, यह लिस्ट भी अधूरी है. इसकी कई वजहें हैं. पहली तो यह कि सिबिल की इस लिस्ट में केवल उन्हीं विलफुल डिफॉल्टरों के नाम शामिल हैं जिनके ऊपर कम से कम 25 लाख रुपये का कर्ज है. इससे कम कर्ज वालों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि विलफुल डिफॉल्टर्स की वास्तविक संख्या और रकम इससे भी ज्यादा हो सकती है.

लेकिन, सिबिल के इतने डाटा भर से भी एनपीए को लेकर एक दृष्टि तो मिल ही जाती है कि आखिर, इस देश में कर्ज के नाम पर जनता के पैसों की लूट का कैसा खेल चल रहा है. हम, इस स्टोरी में आपको सिर्फ विलफुल डिफॉल्टरों के बारे में बताएंगे. इसका मतलब यह है कि हम केवल उन्हीं कर्जों की चर्चा करेंगे जिन्हें कम्पनियां पैसा होने के बाद भी जानबूझ कर नहीं चुका रही हैं. ऐसी ही कम्पनियों के खिलाफ बैंकों ने सूट फाइल किया हुआ है. ऐसी 5,354 कम्पनियां हैं, जिनके ऊपर करीब 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप केंद्रीय बजट में मनरेगा, स्वास्थ्य या शिक्षा के लिए आवंटित किए गए पैसे से तुलना कर लगा सकते हैं. इस बार के बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए करीब 36 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसका अर्थ है कि विलफुल डिफॉल्टरों के पास भारत की पूरी कृषि व्यवस्था के लिए एक बजट में आवंटित पैसे से भी अधिक पैसा बैंकों का कर्ज है.

हम आपको भारतीय बैंकों के कुछ सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टरों के बारे में बताते हैं. इनके नाम हैं, मुम्बई की विनसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, जिसके ऊपर करीब 3 हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक का कर्ज़ है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित ज़ूम डेवलपर्स के ऊपर भी डेढ़ हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का लोन है, किंगफिशर एयरलाइंस का नाम तो है ही,

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दोषी बैंकों पर क्यों नहीं होती कार्रवाई?

पूंजीपतियों को ऋण देकर पांच लाख करोड़ रुपये डुबो देने वाले बैंकों पर कोई क़ानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? यह ऐसा सवाल है जिसका सामना न केंद्र सरकार करना चाहती है, न भारतीय रिजर्व बैंक करना चाहता है और न आर्थिक अपराध की छानबीन करने वाली केंद्रीय एजेंसियां करना चाहती हैं. सारी कार्रवाइयां बैंकों के छोटे अधिकारियों और मैनेजरों पर केंद्रित रहती हैं और बड़े-बड़े मामले इन्हीं छोटी-छोटी कार्रवाइयों के जाल-फ़रेब में दफना दिए जाते हैं.

पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों को ऋण देने की बैंकों की आपाधापी पर गौर करें तो बैंकों के शीर्ष प्रबंधन पर बैठे शीर्ष अधिकारियों की मिलीभगत आपको साफ-साफ दिखेगी. ऋण की राशि गायब करने वाले पूंजीपतियों के साथ बैंकों की आपराधिक साठगांठ है और उन पैसों में बैंकों का हिस्सा है. विजय माल्या को जिस तरह यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सारी मर्यादाएं लांघकर ऋण दिए, उसमें झांकें तो कई दिलचस्प और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आएंगे. इनके बारे में चौथी दुनिया के पूर्व के अंकों में बताया जा चुका है और आगे भी इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे. भारतीय स्टेट बैंक ने करीब दर्जनभर बैंकों का कंसोर्टियम बनाकर विजय माल्या को ऋण दिए. यह गिरोहबंदी नहीं है तो क्या है? पूंजीपतियों को अनाप-शनाप ऋण देने वाले बैंकों के कई शीर्ष अधिकारी अपना काम अंजाम देकर स्वैच्छिक अवकाश लेकर बैंकों की नौकरी छोड़कर पहले ही भाग लिए ताकि उन पर छींटे न आने पाएं. सरकार या जांच एजेंसियां एनपीए घपले में बैंकों की भूमिका तलाशें तो डूबा हुआ धन वापस आ सकता है. लेकिन डूबा धन वापस लाने में दिलचस्पी ही किसकी है..! ■

क़र्ज़ लेने का यह तरीक़ा शातिराना है...

सिबिल वेबसाइट से हमने कुछ स्क्रीन शॉट्स लिए हैं. ये स्क्रीन शॉट्स बताते हैं कि कंपनियां कैसे अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग बैंकों की अलग-अलग शाखाओं से सौ, दो सौ करोड़ का लोन लेती हैं और धीरे-धीरे यह लोन हज़ारों करोड़ का हो जाता है. पथेजा ब्रदर्स नाम की एक कम्पनी है. सिबिल वेबसाइट पर इसके नाम से कर्ज़ की करीब 200 डिटेल हैं. हम आपको यहां सिर्फ एक ही स्क्रीन शॉट दिखा रहे हैं. इस एक स्क्रीन शॉट को देखने से पता चलता है कि इस एक कम्पनी ने अलग-अलग तारीख़ को मुम्बई और पुणे के दो बैंकों से सैकड़ों करोड़ रुपये का लोन लिया है. इसके अलावा, इस कम्पनी ने और भी कई बैंकों की ब्रांच (अधिकतर महाराष्ट्र) से कर्ज़ लिए हैं.

Suit-filed accounts (Willful Defaulters) of Rs. 25 Lacs and above as on 22-Mar-2016
Search details
Borrower Containing - patheja

Bank	Branch	Quarter	D&B D-U-N-S® Number	Borrower Name	Directors Name	OutStanding Amount (Rs. in Lacs)
IFCI FACTORS LIMITED	MUMBAI R.O	31-03-03		PATHEJA FORGINGS & AUTOPARTS LIMITED	G.S.PATHEJA, MANSINGH PATHEJA, P.S.PATHEJA, P.V.S.PATHEJA	11,576.00
IFCI FACTORS LIMITED	MUMBAI R.O	30-09-03		PATHEJA FORGINGS & AUTOPARTS LIMITED	G.S. PATHEJA, MANSINGH PATHEJA, P.S. PATHEJA, V.S. PATHEJA	11,576.00
IFCI FACTORS LIMITED	MUMBAI R.O	31-12-03		PATHEJA FORGINGS & AUTOPARTS LIMITED	G.S. PATHEJA, MANSINGH PATHEJA, P.S. PATHEJA, V.S. PATHEJA	11,576.00
IFCI FACTORS LIMITED	MUMBAI R.O	31-03-04		PATHEJA FORGINGS & AUTOPARTS LIMITED	P.S. PATHEJA, G.S. PATHEJA, MANSINGH PATHEJA, V.S. PATHEJA	11,576.00
IFCI FACTORS LIMITED	MUMBAI R.O	30-06-04		PATHEJA FORGINGS & AUTOPARTS LIMITED	G.S. PATHEJA, V.S. PATHEJA, MANSINGH PATHEJA, P.S. PATHEJA	11,576.00
IFCI FACTORS LIMITED	MUMBAI R.O	30-09-04		PATHEJA FORGINGS & AUTOPARTS LIMITED	V.S. PATHEJA, MANSINGH PATHEJA, G.S. PATHEJA, P.S. PATHEJA	11,576.00
IFCI FACTORS LIMITED	MUMBAI R.O	31-12-04		PATHEJA FORGINGS & AUTOPARTS LIMITED	P.S. PATHEJA, V.S. PATHEJA, G.S. PATHEJA, MANSINGH PATHEJA	11,576.00
IFCI FACTORS LIMITED	MUMBAI R.O.	31-03-02		Patheja Forgings & Autoparts Limited		11,576.00
INDUSIND BANK LTD.	PUNE	31-03-02		Patheja Forgings & Auto Parts Mfgr Limited	G. S. Patheja, M. S. Patheja, P. S. Patheja, V. S. Patheja	1,674.00
INDUSIND BANK LTD.	PUNE	30-09-02		Patheja Forgings & Auto Parts Mfgr. Limited	G. S. Patheja, M. S. Patheja, P. S. Patheja, V. S. Patheja	1,672.00
INDUSIND BANK LTD.	PUNE	31-12-02		Patheja Forgings & Auto Parts Mfgr. Limited	G. S. Patheja, M. S. Patheja, P. S. Patheja, V. S. Patheja	1,672.00
INDUSIND BANK LTD.	PUNE	31-03-03		Patheja Forgings & Auto Parts Mfgr. Limited	Gurminder Singh Path, Mansingh Patheja, Parampreet Singh Pathe, Varenderjeet Patheja Forgings & Auto Parts Mfgr. Limited	1,672.00
INDUSIND BANK LTD.	PUNE	30-06-03		Patheja Forgings & Auto Parts Mfgr. Limited	Gurminder Singh Patheja, Mansingh Patheja, Parampreet Singh Patheja, Varenderjeet Singh Patheja	1,672.27

(शेष पृष्ठ 2 पर)

असली राष्ट्रद्रोही

पृष्ठ 1 का शेष

बीटा नापथाल के ऊपर भी क़रीब 1 हजार करोड़ रुपये का लोन है और ये सब विलफुल डिफॉल्टर हैं. 2002 से लेकर 2016 के बीच भारतीय बैंकों का क़र्ज़ दस गुना से भी अधिक बढ़ गया है. ऐसे में एनपीए बन चुकी इस विशाल राशि के लिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था, किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक सरकार को दोष देना भी ठीक नहीं होगा. दरअसल, एनपीए के इस हम्माम में सब नंगे हैं. यह खेल ऐसा है जिसके खिलाड़ी बदलते रहे, लेकिन खेल बदस्तूर जारी रहा.

सबसे पहले हम आपको 25 लाख रुपये से ज्यादा के विलफुल डिफॉल्टरों के बारे में बताते हैं. अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी बैंकों के खाते में 1,546 विलफुल डिफॉल्टर शामिल हैं और जो रकम डूबी है, वह है 18,576 करोड़ रुपये. इसी तरह प्राइवेट सेक्टर बैंकों के खाते में 792 डिफॉल्टर हैं और इन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंकों का करीब 10,250 करोड़ रुपये जानबूझ कर नहीं चुकाए हैं. अगर बात राष्ट्रीयकृत बैंकों (एसबीआई को छोड़कर) की करें तो इनके खाते में 3,536 विलफुल डिफॉल्टर हैं और इन्होंने करीब 30 हजार करोड़ रुपये डूबोए हैं. इसके साथ ही वित्तीय संस्थानों के 42 और विदेशी बैंकों के 38 विलफुल डिफॉल्टरों ने करीब 1,200 करोड़ रुपये का क़र्ज़ लिया है और उसे अब तक नहीं चुकाया है. दिलचस्प रूप से विदेशी बैंकों और प्राइवेट बैंकों का एनपीए राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुक़ाबले काफी कम है. कुल एनपीए में राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिस्सेदारी 70 फीसदी से भी अधिक है. ज़ाहिर है, इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव भी एक वजह हो सकती है. ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को राजनीतिक दबाव के तहत लोन देना पड़ता है. ध्यान देने की बात है कि किंगफिशर जैसी कम्पनियों की खस्ता हालत को देखते हुए भी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उसे लगातार लोन देना जारी रखा. अब, ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ होगा.

अगर हम राज्यवार इन डिफॉल्टररों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र का नंबर सबसे ऊपर आता है. जाहिर है, देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते यहां सबसे अधिक बिजनेसमैन हैं. इसलिए यहां क़र्ज़ भी अधिक लिया जाता है. महाराष्ट्र में विलफुल डिफॉल्टररों की संख्या 1,200 है, जिन्होंने विभिन्न बैंकों से करीब 21,788 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में लिए हैं और अब तक जानबूझ कर उसे नहीं चुकाया है. आमतौर पर पश्चिम बंगाल को औद्योगिक दृष्टि से रुग्ण राज्य माना जाता है, फिर भी विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या के मामले में यह राज्य दूसरे नंबर पर आता है. पश्चिम बंगाल में विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या 888 है, जिनके पास विभिन्न बैंकों के करीब 5340 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में हैं. दिलचस्प यह है कि दिल्ली में विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या पश्चिम बंगाल से कम है लेकिन कर्ज की रकम ज्यादा है. दिल्ली में विलफुल डिफॉल्टररों की संख्या सिर्फ 426 है, वहीं क़र्ज़ की रकम 7,435 करोड़ रुपये है. इसी तरह, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या आंध्र प्रदेश के 569 के मुकाबले सिर्फ 357 है, वहीं क़र्ज़ की रकम आंध्र प्रदेश के 3,162 करोड़ रुपये के मुक़ाबले 4,324 करोड़ रुपये है.

इसके अलावा, हम आपको ऐसे खातों की संख्या भी बता रहे हैं (देखें बाक्स) जो विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं हैं लेकिन जिनके ऊपर कम से कम एक करोड़ रुपये का क़र्ज़ है और जिनके ख़िलाफ बैंकों ने सूट फाइल किया है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कम से कम एक करोड़ रुपये की बात करते हैं तो यह एक हजार करोड़ या 5 हजार करोड़ रुपये का भी कर्ज़ हो सकता है. ऐसे में, सवाल सिर्फ अकेले विजय माल्या का नहीं है. सवाल सिर्फ 9 हजार करोड़ रुपये का भी नहीं है. सवाल है उन 5 लाख करोड़ रुपये का जो आज एनपीए यानी डूबा हुआ क़र्ज़ बन गया है. सवाल है उन सैकड़ों विजय माल्याओं का, जिनके नाम अब तक सरकार, मीडिया और बैंक सामने नहीं लाना चाहते हैं. आखिर कौन हैं ये लोग? इनकी पहचान जब दस्तावेजों पर है तो उनसे क़र्ज़ वसूलने में समस्या क्या है? दूसरी तरफ इस देश के किसान हैं, बेरोज़गार हैं, आम आदमी हैं, जो खेती के लिए, छोटे-मोटे व्यापार के लिए बैंक से क़र्ज़ लेना चाहते हैं. लेकिन उन्हें बैंक क़र्ज़ नहीं देते. किसान खेती बर्बाद होने की वजह से क़र्ज़ नहीं लौटा पाता तो उस पर इतना दबाव पड़ता है कि वह आत्महत्या तक कर लेता है. आम आदमी कार लोन या होम लोन की तीन किस्तें लगातार नहीं दे पाता तो बैंक कार या घर पर क़ब्ज़ा करने पर उतारू हो जाते हैं. उनके घर बाउंसर भेज दिए जाते हैं. सवाल है कि क्या सरकार और बैंक ऐसे विलफुल डिफाल्टरों के साथ भी ऐसा ही सलूक कर पाने की हिम्मत दिखा सकते हैं? क्या जितने विलफुल डिफॉल्टर हैं उनसे सरकार अपना क़र्ज़ वापस ले सकती है?

कृषि बनाम कॉरपोरेट एनपीए की बात करें तो कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए हमेशा से कॉरपोरेट सेक्टर के मुक़ाबले बहुत ही कम रहा है. कृषि क्षेत्र में एक किसान ट्रैक्टर, खाद, बीज आदि खरीदने के लिए चंद हज़ार या एक-दो लाख रुपये का लोन लेता है, जबकि कॉरपोरेट क्षेत्र में एक कम्पनी पर ही सैकड़ों-हजारों करोड़ का लोन बकाया है. लेकिन, किसान क़र्ज़ पर जहां हर ओर चर्चा होती है, वहीं इस बात पर चर्चा नहीं होती कि किस कम्पनी ने कितने करोड़ का लोन लेकर नहीं चुकाया? क्या इस देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि किस राज्य के किस बैंक की किस ब्रांच से किस कम्पनी ने कितने करोड़ का लोन लिया और फिर उस लोन को नहीं चुकाया? चौथी दुनिया ने अपने पाठकों को ऐसे ही विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या और क़र्ज़ की रक़म की जानकारी देने की कोशिश की है, ताकि आम आदमी यह जान सके कि उसकी जेब का पैसा कहां जा कर सूख गया है.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

क्या-क्या हो सकता है पांच लाख करोड़ के एनपीए से

क्या यह संभव है कि देश के सभी बच्चे विश्वस्तरीय स्कूलों में पढ़ाई कर सकें? क्या यह संभव है कि देश के हर नागरिक का इलाज अपोलो जैसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हो सके? क्या कृषि क्षेत्र में इतनी उन्नति हो सकती है कि किसान अपने क़र्जों के बोझ के कारण आत्महत्या करने को मजबूर न हों? पहली नज़र में ऐसा होना असंभव लगता है. लेकिन यह असंभव नहीं है. भारत के बैंकों का बड़े कॉरपोरेट हाउसेज पर पांच लाख करोड़ रुपये का ऐसा ऋण है जो कि यदि उपरोक्त क्षेत्रों में लगाया जाता है तो इन क्षेत्रों का कायाकल्प हो सकता है. सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर एक नज़र डालते हैं. कृषि प्रधान देश का किसान बदहाल है. इस वर्ष आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए तक़रीबन 36 हज़ार करोड़ की राशि आवंटित की गई है. अब यदि बैंकों के एनपीए की तुलना कृषि के लिए आवंटित बजट से की जाए तो यह उससे 13 गुना अधिक है. कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि एनपीए की यह राशि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित कर दी जाए तो देश में कृषि की तस्वीर बदल जाएगी. उसी तरह शिक्षा क्षेत्र, खास तौर पर उच्च शिक्षा क्षेत्र की यह शिकायत रही है कि उसके लिए आवंटित बजट नाकाफी है. देश में सबके लिए शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू होने के बाद प्राथमिक शिक्षा पर काफी ज़ोर दिया जा रहा है. लेकिन ज़मीनी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा भी महज़ खानापूर्ति ही नज़र आती है. बहरहाल, इस साल आम बजट में शिक्षा के लिए 68,968 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो बैंकों के एनपीए से सात गुना कम है. अगर एनपीए की राशि शिक्षा के लिए आवंटित कर दी जाए तो न सिर्फ अनुबंधित शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जा सकता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को भी काफी ऊंचा उठाया जा सकता है.

इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र उपेक्षित क्षेत्र है. गरीबों के इलाज के लिए उनके आस-पास बेहतर स्वाथ्य सेवाओं का अभाव है, जिसके कारण दिल्ली के एम्स जैसे अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं. देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं. देश में मेडिकल कॉलेजों का भी अभाव है. ऐसे में जबकि इस साल स्वास्थ्य के लिए 38,892 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, यदि एनपीए की राशि स्वास्थ्य क्षेत्र को दे दी जाती तो अपोलो जैसे अस्पताल देश के हर नागरिक की पहुंच में आ जाते. ■

अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी बैंकों के खाते में 1,546 विलफुल डिफॉल्टर शामिल हैं और जो रक़म डूबी है, वह है 18,576 करोड़ रुपये. इसी तरह प्राइवेट सेक्टर बैंकों के खाते में 792 डिफॉल्टर हैं और इन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंकों का करीब 10,250 करोड़ रुपया जानबूझ कर नहीं चुकाया है.

क़र्ज़ लेने का यह तरीक़ा शातिराना है...

पृष्ठ 1 का शेष

इस स्क्रीन शॉट में दिखाया गया है कि किंगफिशर ने एसबीआई और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से कितना क़र्ज़ लिया है.

Suit-filed accounts (Willful Defaulters) of Rs. 25 Lacs and above as on 21-Mar-2016
Search details
Borrower Containing - kingfisher

Bank	Branch	Quarter	D&B D-U-N-S® Number	Borrower Name	Directors Name	OutStanding Amount (Rs. in Lacs)
STATE BANK OF INDIA	SAM BRANCH BANGALORE	31-12-15		KINGFISHER AIRLINES LTD (PREV	VIJAY MALLYA (DR), UNITED BREWERIES (HOLDINGS) LIMITED	120,139.99
UNITED BANK OF INDIA	BANGALORE	30-06-14		KINGFISHER AIRLINES LTD	VIJAY MALLYA, SUBHAS R GUPTE, ANIL KUMAR GANGULY, AYANI KURASSI RAVINDRANATH NEDUNGADI	35,254.00
UNITED BANK OF INDIA	BANGALORE	30-09-14		KINGFISHER AIRLINES LTD	VIJAY MALLYA, SUBHAS R GUPTE, ANIL KUMAR GANGULY, AYANI KURASSI RAVINDRANATH NEDUNGADI	35,254.00

इस स्क्रीन शॉट में दिखाया गया है कि विनसम डायमंड्स कंपनी ने मुम्बई और दिल्ली के बैंकों से क़र्ज़ लिया है.

Suit-filed accounts (Willful Defaulters) of Rs. 25 Lacs and above as on 21-Mar-2016
Search details
Borrower Containing - winsome

Bank	Branch	Quarter	D&B D-U-N-S® Number	Borrower Name	Directors Name	OutStanding Amount (Rs. in Lacs)
BANK OF MAHARASHTRA	Nariman Point, Overseas Mumbai	31-12-14		Winsome Diamonds Jewellery Ltd.	Jatin R. Mehta, Ramesh I. Parikh, R. Ravichandran, Satya Prakash Tanwar (Nom) Nominated by Consortium Banks, Harish R. Mehta, Jaikumar Madanlal Kapoor	27,686.00
BANK OF MAHARASHTRA	Nariman Point, Overseas Mumbai	31-03-15		Winsome Diamonds Jewellery Ltd.	Jatin R. Mehta, Ramesh I. Parikh, R. Ravichandran, Satya Prakash Tanwar (Nom) Nominated by Consortium Banks, Harish R. Mehta, Jaikumar Madanlal Kapoor	27,686.00
BANK OF MAHARASHTRA	Nariman Point, Overseas Mumbai	30-06-15		Winsome Diamonds Jewellery Ltd. Winsome Diamonds Jewellery Ltd.	Jatin R. Mehta, Ramesh I. Parikh, R. Ravichandran, Satya Prakash Tanwar (Nom) Nominated by Consortium Banks, Harish R. Mehta, Jaikumar Madanlal Kapoor, Harimohan Namdev	27,686.00
BANK OF MAHARASHTRA	Nariman Point, Overseas Mumbai	30-09-15		Winsome Diamonds Jewellery Ltd.	Jatin R. Mehta, Ramesh I. Parikh, R. Ravichandran, Satya Prakash Tanwar (Nom) Nominated by Consortium Banks, Harish R. Mehta, Jaikumar Madanlal Kapoor, Harimohan Namdev	27,686.00
BANK OF MAHARASHTRA	Nariman Point, Overseas Mumbai	31-12-15		Winsome Diamonds Jewellery Ltd.	Jatin R. Mehta, Ramesh I. Parikh, R. Ravichandran, Satya Prakash Tanwar (Nom) Nominated by Consortium Banks, Harish R. Mehta, Jaikumar Madanlal Kapoor, Harimohan Namdev	27,686.00
BANK OF RAJASTHAN LTD	DELHI S.E.	30-06-03		WINSOME BREWERIES LIMITED	R.K.BAGRODIA, SNEH BAGRODIA	36.00

इस स्क्रीन शॉट में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की रज़ा टेक्सटाइल कम्पनी ने मुम्बई से लेकर रामपुर तक के बैंकों से क़र्ज़ लिया है.

Suit-filed accounts (Willful Defaulters) of Rs. 25 Lacs and above as on 21-Mar-2016
Search details
Borrower Containing - raza

Bank	Branch	Quarter	D&B D-U-N-S® Number	Borrower Name	Directors Name	OutStanding Amount (Rs. in Lacs)
KOTAK MAHINDRA BANK	MUMBAI	30-09-14		RAZA TEXTILES LIMITED	V K SHRIVASTAV	53,457.23
KOTAK MAHINDRA BANK	MUMBAI	31-12-14		RAZA TEXTILES LIMITED	V K SHRIVASTAV	55,090.48
KOTAK MAHINDRA BANK	MUMBAI	31-03-15		RAZA TEXTILES LIMITED	V K SHRIVASTAV	59,904.72
KOTAK MAHINDRA BANK	MUMBAI	30-06-15		RAZA TEXTILES LIMITED	V K SHRIVASTAV	64,020.43
KOTAK MAHINDRA BANK	MUMBAI	30-09-15		RAZA TEXTILES LIMITED	V K SHRIVASTAV	67,219.60
KOTAK MAHINDRA BANK	MUMBAI	31-12-15		RAZA TEXTILES LIMITED	V K SHRIVASTAV	69,459.51
STATE BANK OF INDIA	RAMPUR	31-03-04		RAZA TEXTILES LIMITED	V.K.SRIVASTAVA, J.K.SRIVASTAVA	404.00
STATE BANK OF INDIA	RAMPUR	30-06-04		RAZA TEXTILES LIMITED	V.K.SRIVASTAVA, J.K.SRIVASTAVA	404.00
STATE BANK OF INDIA	RAMPUR	30-09-04		RAZA TEXTILES LIMITED	V.K.SRIVASTAVA, J.K.SRIVASTAVA	404.00
STATE BANK OF INDIA	RAMPUR	31-12-04		RAZA TEXTILES LIMITED	J.K.SRIVASTAVA, V.K.SRIVASTAVA	404.00
STATE BANK OF INDIA	RAMPUR	30-09-05		RAZA TEXTILES LIMITED	J K SRIVASTAVA, V K SRIVASTAVA	404.00
STATE BANK OF INDIA	RAMPUR	31-12-05		RAZA TEXTILES LIMITED	V.K.SRIVASTAVA, J.K.SRIVASTAVA	403.00
STATE BANK OF INDIA	RAMPUR	30-06-06		RAZA TEXTILES LIMITED	J.K.SRIVASTAVA, V.K.SRIVASTAVA	403.00
STATE BANK OF INDIA	RAMPUR	30-09-06		RAZA TEXTILES LIMITED		403.00
STATE BANK OF INDIA	RARB	30-06-05		RAZA TEXTILES LIMITED	V K SRIVASTAVA, J K SRIVASTAVA	404.00

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 05
04 अप्रैल-10 अप्रैल 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

असली राष्ट्रद्रोही

पृष्ठ 2 का शेष

बैंकवार सूचना, 31 दिसंबर 2015 तक के विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या, जिनके ऊपर 25 लाख रुपये से अधिक का क़र्ज़ है और जिनके ख़िलाफ बैंकों ने सूट फाइल किया है.

बैंकों के नाम	विलफुल डिफॉल्टर्स	रकम (लाख रुपये में)
वित्तीय संस्थाएं		
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	4	22311.12
स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	24	37853.93
यूटीआई म्यूचुअल फंड	14	12628.66
कुल	42	72793.71
विदेशी बैंक		
बैंक ऑफ बहरीन, कुवैत बी.एस.सी	2	2331.00
सिटी बैंक एन.ए	4	1829.80
क्रेडिट एग्रिकोले इन्वेस्टमेंट बैंक	4	1606.15
डॉयचे बैंक	1	3184.00
दोहा बैंक क्यूएससी	2	7205.00
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	25	30141.47
कुल	38	46297.42
राष्ट्रीयकृत बैंक		
इलाहाबाद बैंक	30	48774.05
आंध्रा बैंक	283	242847.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	192	136879.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	92	77555.65
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	639	357409.00
देना बैंक	142	80230.00
इंडियन बैंक	36	120027.69
इंडियन ओवरसीज बैंक	01	1380.09
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	339	354583.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	24	24755.53
पंजाब नेशनल बैंक	698	944505.71
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	611	299087.09
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	344	140838.00
विजया बैंक	105	189491.46
कुल	3536	3018363.27
प्राइवेट सेक्टर बैंक		
एक्सिस बैंक लिमिटेड	126	99388.40
कैथोलिक सीरियन बैंक	30	10873.00
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड	01	20.39
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	67	16463.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	51	24267.41
आईसीआईसी बैंक लिमिटेड	18	39353.63
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	120	89975.18
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	07	6054.00
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	31	37537.28
कोटक महिंद्रा बैंक	61	544219.57
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	31	17854.88
दि फेडरल बैंक लिमिटेड	195	80309.06
दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	02	122.18
दि रत्नाकर बैंक लिमिटेड	08	3017.00
दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	40	52497.00
यस बैंक	04	3023.00
कुल	792	1024974.98
स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक		
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	80	160906.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	197	208871.82
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1034	1209122.59
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	69	102984.67
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	101	84785.43
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	65	90976.00
कुल	1546	1857646.51
कुल	5954	6020075.89

कौन होता है विलफुल डिफॉल्टर

आरबीआई के मुताबिक,

1. कोई कम्पनी या व्यक्ति जो सक्षम होने के बाद भी अपने क़र्ज़ को नहीं चुकाता है, वह विलफुल डिफॉल्टर होता है.
2. यदि कोई व्यक्ति या कम्पनी बैंक क़र्ज़ का भुगतान नहीं करती और जो क़र्ज़ जिस काम के लिए लिया है, उसका इस्तेमाल उस काम में नहीं किया और पैसे को दूसरे काम में लगा दिया.ऐसे में उसे विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा.
3. यदि किसी व्यक्ति या कम्पनी ने क़र्ज़ नहीं चुकाया है और उसने बैंक गारंटी के तौर पर बताई गई चल या अचल संपत्ति को बैंक को बताए बगैर अपनी जगह से ग़ायब कर दिया हो तो उसे भी विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा.

राज्यवार सूचना, 31 दिसंबर 2015 तक के विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या, जिनके ऊपर 25 लाख रुपये से अधिक का क़र्ज़ है और जिनके ख़िलाफ बैंकों ने सूट फाइल किया है.

राज्य	विलफुल डिफाल्टर्स	रकम (लाख रुपये में)
महाराष्ट्र	1200	2178884.99
दिल्ली	426	743527.76
पश्चिम बंगाल	888	534000.09
तमिलनाडु	357	432422.94
आंध्र प्रदेश	569	316213.92
गुजरात	288	295846.43
कर्नाटक	307	284923.33
तेलंगाना	114	280801.20
नई दिल्ली	116	199773.27
पंजाब	293	168012.85
मध्य प्रदेश	204	112779.52
उत्तर प्रदेश	247	95282.33
केरल	223	81153.61
हरियाणा	89	60988.11
छत्तीसगढ़	102	45324.56
ओडिशा	135	45091.12
उत्तराखंड	60	33751.76
झारखंड	83	33737.46
हैदराबाद	2	17173.52
जम्मू-कश्मीर	56	16443.11
राजस्थान	57	11199.00
छत्तीसगढ़	31	6421.38
हांगकांग	1	5566.45
असम	32	4661.91
हिमाचल प्रदेश	22	4464.00
अंडमान और निकोबार	1	4382.96
बिहार	27	3422.30
गोवा	11	2090.67
उत्तरांचल	4	1027.59
नागालैंड	4	423.00
त्रिपुरा	1	111.91
सिक्किम	1	74.00
अरुणाचल प्रदेश	2	68.84
मेघालय	1	30.00
कुल	5954.0	6020075.89

31 दिसंबर 2015 तक की बैंकवार सूचना. ये ऐसे खाते हैं, जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपये से अधिक का क़र्ज़ है और जिनके ख़िलाफ बैंकों ने सूट फाइल किया है.

बैंकों के नाम	खातों की संख्या	रकम(लाख रुपये में)
वित्तीय संस्था		
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	3	5137.41
स्पेसीफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	90	130686.00
यूटीआई म्यूचुअल फंड	30	28492.52
कुल	123	164315.93
विदेशी बैंक		
एएनजेड बैंक (ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड)	01	3112.00
बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी	03	1850.58
सिटी बैंक एन.ए.	70	133314.46
सीटीबीसी बैंक कॉरपोरेट लिमिटेड	06	7359.65
डॉयचे बैंक	15	21643.44
दोहा बैंक क्यूएससी	12	21018.00
फर्स्टरैंड बैंक लिमिटेड	12	37166.53
जेपी मॉर्गेन चेज बैंक एनए	14	37722.66
जेएससी वीटीबी बैंक	01	722.85
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	140	49011.49
स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लिमिटेड	09	21516.84
दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर. लिमिटेड	18	46758.03
कुल	301	381196.53
राष्ट्रीयकृत बैंक		
इलाहाबाद बैंक	300	647302.34
आंध्रा बैंक	298	530934.00
केनरा बैंक	1220	1001635.95
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	952	771801.28
इंडियन बैंक	44	39444.83
इंडियन ओवरसीज बैंक	206	482929.81
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	515	827313.47
पंजाब एंड सिंध बैंक	60	60155.74
विजया बैंक	112	190665.25
कुल	3707	4552182.67
प्राइवेट सेक्टर बैंक		
एक्सिस बैंक लिमिटेड	356	512148.20
कैथोलिक सीरियन बैंक	31	23043.31
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड	17	12910.24
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	69	45300.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	249	234769.11
आईसीआईसी बैंक लिमिटेड	338	683091.45
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	01	461.25
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	123	140177.53
कर्नाटका बैंक लिमिटेड	61	60679.00
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	33	57634.80
कोटक महिंद्रा बैंक	404	714429.75
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	34	27039.37
दि फेडरल बैंक लिमिटेड	161	172841.63
दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	100	97438.12
दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	30	43267.53
दि रत्नाकर बैंक लिमिटेड	07	7145.00
दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	69	72124.46
यस बैंक	36	29749.00
कुल	2119	2934249.75
स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक		
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	101	198023.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	226	372501.94
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1972	3610528.66
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	125	169493.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	143	332087.00
कुल	2567	4682633.60
कुल	8817	12714578.48

shashishekhar@chauthiduniya.com

नदियों की सफाई का चल रहा है राष्ट्रीय तमाशा

नदी से नाला बनती ब्रज की यमुना

ब्रह्मानंद राजपूत

यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है. आज यह नदी गंगा नदी से भी ज्यादा प्रदूषित है. भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना को गंगा के साथ रखा जाता है. जिस तरह गंगा नदी का सांस्कृतिक इतिहास है उसी प्रकार यमुना नदी का भी सांस्कृतिक इतिहास है. सम्पूर्ण ब्रज क्षेत्र की तो यमुना एक मात्र महत्वपूर्ण नदी है. जहां तक ब्रज संस्कृति का संबध है, यमुना को केवल नदी कहना ही पर्याप्त नहीं है. वस्तुतः यह ब्रज संस्कृति की सहायक, इसकी दीर्घ कालीन परम्परा की प्रेरक और यहां की धार्मिक भावना की प्रमुख आधार रही है. जिस प्रकार ब्रज क्षेत्र में कृष्ण का स्थान है उसी प्रकार ब्रज में यमुना का स्थान है. आज उसी यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है. यह नदी दिल्ली से आगे जाकर मर रही है और एक नाला बनकर रह गई है.

जो लोग यमुना पर लगातार शोध कर रहे हैं उन विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना में प्रदूषण की वजह है औद्योगिक प्रदूषण, बिना ट्रीटमेंट के कारखानों से निकले दूषित पानी को सीधे नदी में गिरा दिया जाना, यमुना किनारे बसी आबादी मल-मूत्र और गंदगी को सीधे नदी में बहा देती है. लेकिन इनमें सबसे खतरनाक है रासायनिक कचरा जो कि यमुना किनारे लगे कारखाने इसमें उड़ेल रहे हैं. आज यमुना का हाल घर में पड़ी बूढ़ी मां की तरह हो गया है जिसे हम प्यार तो करते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं, लेकिन उसकी फिक्र नहीं करते. यमुना का आधार धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक है. इस नदी का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसलिए यमुना को प्रदूषण मुक्त कर उसकी गरिमा लौटने की मुहिम के लिए सभी देशवासियों को आगे आना चाहिए. देश की हर नदी पर व्यवसायिक गतिविधियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कम से कम यमुना और देश की प्रमुख नदियों को इससे मुक्त रखने की जरूरत है.

दिल्ली का वजीराबाद बैराज एक ऐसी जगह है जहां पर यमुना की बदहाली का जवाब मिल

जाएगा. यही वह जगह है जहां से यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती हैं और इसी जगह पर बना बैराज यमुना को आगे बढ़ने से रोक देता है. यहीं तक यमुना नदी बहती है, इसके आगे यमुना नाला बन कर घिसटती है. वजीराबाद के एक ओर यमुना का पानी एकदम साफ और दूसरी तरफ एकदम काला है. इसी जगह से नदी का सारा पानी दिल्ली द्वारा उठा लिया जाता है और जल शोधन संयत्र के लिए भेज दिया जाता है ताकि दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिल सके बस यहीं से इस नदी की बदहाली भी शुरू हो जाती है. दिल्ली में यमुना नदी में 22 किलोमीटर के सफर में ही 18 नाले मिलते हैं तो बाकी जगह का हाल क्या होगा. इसमें सबसे बड़ा योगदान औद्योगिक प्रदूषण का है जो साफ हो ही नहीं रहा. यमुना नदी एक हजार 29 किलोमीटर का जो सफर तय करती है, उसमें दिल्ली से लेकर चंबल तक का जो सात सौ किलोमीटर का सफर है उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली, आगरा और मथुरा का है. दिल्ली के वजीराबाद बैराज से निकलने के बाद यमुना बद से बदतर होती जाती है. इन जगहों के पानी में ऑक्सीजन तो है ही नहीं. चंबल पहुंचकर इस नदी को जीवन दान मिलता है और वह पुनर्जीवित होती है. वह फिर से अपने रूप में वापस आती है.

नदी के साफ रहने के लिए जरूरी है कि उसमें पानी बहने दिया जाए. हर जगह बांध बनाकर उसे रोकने से काम नहीं चलेगा. दिल्ली के आगे जो बह रहा है वह यमुना है ही नहीं. वह तो मल-जल है. पहले मल-जल को नदी में छोड़ दें, फिर उसका उपचार करते रहें तो नदी कभी साफ नहीं हो सकती. यमुना एक्शन प्लान के दो चरणों में इतना पैसा बहाने के बाद भी यदि नदी का हाल वही का वही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि जो कार्य किया गया वह सही नहीं है. इसमें से ज्यादा पैसा यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है. यह जगजाहिर है कि मोदी सरकार ने अपने गठन के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना की शुरूआत की थी. इस योजना के तहत नदी के प्रदूषण को कम करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है. इसमें प्रदूषण को रोकने और नालियों से बहने वाले कचरे के शोधन और उसे नदी से दूसरी ओर मोड़ने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. कचरा और सीवेज परिशोधन के लिए नई तकनीक की व्यवस्था की जा रही है. केंद्र सरकार के गठन के तकरीबन दो साल होने को आए लेकिन अब तक न तो नदियों का प्रदूषण कम हुआ और ना ही नालियों से बहने वाले कचरे के शोधन और उसे नदी से दूसरी ओर मोड़ने जैसे कदम ही उठाए गए, साथ ही कचरा और सीवेज परिशोधन के लिए नई तकनीक की व्यवस्था भी नहीं हो पाई.

मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही नमामि गंगे योजना का लाभ अभी तक यमुना नदी को नहीं मिला है. असल में कहा जाए तो नमामि गंगे का लाभ गंगा को भी नहीं मिला है. कहा जाए तो गंगा की स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के बावजूद नमामि गंगे योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है. जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्री ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2018 तक का समय मांगा है. इतने सालों में गंगा और यमुना साफ नहीं हो पाई तो हमें 2018 तक का भी इंतजार कर लेना चाहिए. असल बात यह है की कालिंदी (यमुना) की हालत सुधारने के लिए प्रयास नहीं किए गए. सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम चलाए गए पर हालात जस के तस रहे. इसके लिए जरूरत है दृढ़ संकल्प की जो कि हर भारतीय के अंदर होना चाहिए, तब हमें करोड़ों रुपये बहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को यमुना को अपनी मां का दर्जा देना होगा, क्योंकि यमुना देश के करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम. लिहाजा, इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए. इसके अलावा लोगों को तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए जब तक यमुना अविरल नहीं हो जाती है. आज जरूरत है यमुनातट पर बसे लोगों को यमुना की दुर्दशा के बारे में बताने और उन्हें जागरूक करने की. तभी हम यमुना की धारा को अविरल, निर्मल तथा आचमन लायक बना सकते हैं और ब्रज को वही पुरानी कालिंदी लौटा सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में कुपोषण भयावह स्तर पर, अधिकांश बच्चियों में ख़ून की कमी

नेता ख़ून पी रहे, प्रजा आंसू

प्रशांत शरण

झारखंड स्थित चाईबासा की अठारह वर्षिया मुनिया की स्थिति देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर नरकंकाल जैसा, वजन 25 किलोग्राम. कुपोषण का शिकार मुनिया की शादी हो गई तो उसका बच्चा भी कुपोषण की चपेट में आ गया. जन्म के समय उसका वजन मात्र डेढ़ किलो ही था. राज्य सरकार कुपोषण दूर करने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं और दावे करती है पर इस राज्य की स्थिति इतनी बदतर है कि कुपोषण के मामले में यह पूरे देश में अव्वल हो गया है. इस राज्य के 56 प्रतिशत से भी अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जबकि 67 प्रतिशत लड़कियां एनेमिक (ख़ून की कमी). दरअसल कुपोषण से लड़ने के लिए बजट में तो हर साल वृद्धि हुई, पर इनको मिलने वाले पोषाहार की अधिकांश राशि राजनेता, अधिकारी और बिचौलिये ही गटक जाते हैं. चौदह वर्षों में कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने 03 हजार 442 करोड़ 54 लाख रुपये खर्च किए पर नतीजा वही सिफर रहा.

ओडिशा के कालाहांडी से भी भयावह स्थिति यहां के कुछ ग्रामीण इलाकों की है. राइट-टू-फूड एक्ट के लागू होने के बाद भी आदिवासी बहुल ग्रामीण इलाकों की स्थिति अत्यंत भयावह है. जहां एक जून के भोजन के लिए भी लोग तरस रहे हैं. लगभग

पोषण पर इतना ख़र्च तो कुपोषण क्यों?

वित्तीय वर्ष	ख़र्च (करोड़ में)
2001 - 02	0.87
2002 -03	2.18
2003 - 04	14.79
2004 - 05	59.67
2005 - 06	140.85
2006 - 07	168.56
2007 - 08	169.65
2008 - 09	188.97
2009 - 10	320.00
2010 - 11	385.00
2011 - 12	357.00
2012 - 13	197.00
2013 - 14	225.00
2014 - 15	472.00
2015 - 16	741.00
कुल	3,442.52 करोड़

30 प्रतिशत आबादी बिना भोजन किए रात को सोने को मजबूर है. घास-पात खाकर लोग जीवन बसर कर रहे हैं जबकि अधिकांश आबादी एक वक्त ही मांड़-भात और नमक के साथ अपना पेट भरने को मजबूर है. किसी तरह जीवन-बसर करने वाले इस राज्य की अधिकांश आबादी कुपोषण के साथ अन्य कई बीमारियों से भी ग्रसित है. एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 23 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जबकि अठारह वर्ष से कम उम्र की 65 लाख लड़कियां में ख़ून की कमी (एनेमिक) है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पदभार ग्रहण करते ही स्वस्थ झारखंड-ख़ुशहाल झारखंड का नारा दिया था. बड़े-बड़े पोस्टर, विज्ञापन एवं कई अभियान चलाए. बजट में भारी वृद्धि हो गई. जहां राज्य के गठन के समय समाज कल्याण विभाग का बजट महज 87 लाख रुपये का था, वहीं साल 2015-16 में 741 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. पर जैसे-जैसे बजट की राशि बढ़ती गई, मर्ज भी बढ़ता चला गया. भ्रष्टाचार के लिए पूरे देश में चर्चित इस राज्य में यह योजना भी भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ गई. कुपोषित बच्चों एवं लड़कियों की स्थिति में तो कोई सुधार नहीं हुआ पर इससे जुड़े नेताओं अधिकारियों और बिचौलियों की वित्तीय स्थिति में जरूर सुधार हो गया.

राज्य के प्रधान महालेखाकार ने भी व्याप्त भ्रष्टाचार पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुपोषण से लड़ने के लिए जो योजना राज्य में चलाई जा रही है, उसमें भारी गड़बड़ी है. राज्य के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां वर्ष के 365 दिनों के बजाय कम ही दिन पोषाहार मुहैया कराया गया. महालेखाकार ने कहा कि कुछ जिलों में तो स्थिति और भी भयावह है. इस बारे में पूछे जाने पर राज्य की समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी भी स्वीकार करती हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है. वे दावा करती हैं कि इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. बिचौलियों से समानों की कालाबाजारी रोकने के लिए अब रेडी टू ईट पोषाहार लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं. कुपोषण पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

झारखंड खनिज संपदाओं से भरा प्रदेश है और इसकी गिनती अमीर राज्य के रूप में होती है पर इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इस अमीर राज्य की अस्सी प्रतिशत आबादी गरीबी से जूझ रही है. कुपोषण गंभीर समस्या का रूप धारण करता जा रहा है. नेशनल फैमिली हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या 23 लाख है. दरअसल आदिवासी और पिछड़ा बहुल इलाका होने के कारण यहां कम उम्र में ही लड़कियां ब्याह दी जाती हैं. परिणाम स्वरूप कम उम्र में ही वे मां बन जाती हैं. कुपोषित मां के बच्चे भी कुपोषित ही पैदा होते हैं. राज्य में हर वर्ष तकरीबन आठ लाख बच्चों का जन्म होता है, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषित ही पैदा होते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 65 लाख है इसमें 67 प्रतिशत लड़कियां एनेमिक हैं. कुपोषण के मामले में भी झारखंड देश में पहला स्थान रखने वाला राज्य बन गया है. राज्य में कुपोषण से निपटने की जिम्मेदारी राज्य के समाज कल्याण विभाग को दी गई है, इससे जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे साल के 365 दिन लोगों को पोषाहार मुहैया कराएं, खासकर गर्भवती महिलाओं को. पर नौकरशाह और संस्थाएं मिलकर पोषक पदार्थों की कालाबाजारी कर रहे हैं. झारखंड में 38 हजार 432 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है. इन केंद्रों पर महिलाओं एवं बालिकाओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है, पर इन केंद्रों को मिलने वाली राशि का भीषण बंदरबांट हो जाता है. यहां रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं. यही कारण है कि हर वर्ष 46 हजार बच्चे अतिकुपोषण का शिकार होने के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं. ■

कुपोषण की समस्या गंभीर - लुईस

राज्य की बाल विकास एवं महिला समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी यह स्वीकार करती हैं कि राज्य में कुपोषण की समस्या गंभीर है. सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं चला रही है और कुछ वर्षों में इस पर काबू पा लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह होना और गर्भधारण करना भी इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है. गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार मुहैया कराया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के टीकों के साथ ही विटामिन के ड्रॉप्स भी अस्पतालों में मुफ्त दिए जा रहे हैं. हर पंचायत में कुपोषण सखी एवं सहिया की मदद से गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषक तत्वों से भरपूर रेडी-टू-ईट भोजन भी कुपोषित बच्चों एवं लड़कियों को उपलब्ध कराए जा रहा है.

राज्य में कुपोषण की भयावह स्थिति के बारे में पूछने पर वे कहती हैं कि राज्य सरकार इस पर गंभीर है. संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है. लोग साक्षर एवं जागरूक होंगे, तो इस पर अपने-आप काबू पाया जा सकेगा. सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से भी शिक्षा केन्द्रों पर मिड-डे-मील का वितरण कर बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराकर उन्हें स्वस्थ बनाया जा रहा है. खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी इसका एक हिस्सा है. स्कूल एवं पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता कैंप लगाकर बच्चों एवं लड़कियों को विटामिन एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ मुहैया कराए जा रहे हैं. भ्रष्टाचार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी है और इस संबंध में जांच कराई जा रही है. महालेखाकार की टिप्पणी के संबंध में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो, इसकी निगरानी के लिए भी कमिटी बनाई गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कुंभ की शिविर परंपरा में पहली बार प्रवेश कर रहे संत कबीर, मूल गादी का ऐतिहासिक फ़ैसला

सिंहस्थ में कबीरस्थ...

दीनबंधु कबीर

feedback@chauthiduniya.com

देस मालवा गहर गंभीर, डग-डग रोटी पग-पग नीर
कहे कबीर घरहीं मन मानां, गूंगे का गुड़ गूंगी जाणा

संत कबीर ने मालवा (मध्य प्रदेश) को आत्मा का प्रदेश कहा था. कबीर पंथ पहली बार कुंभ में अपनी भागीदारी करने जा रहा है. यह एक ऐतिहासिक पहल है. कुंभ में पहली बार शामिल होने की शुरुआत करने के लिए कबीर की मूल गादी वाराणसी के मुख्य महंत विचारक संतश्री विवेक दास आचार्य ने उस मालवा की धरती को ही चुना, जिसे कबीर ने भक्ति और आत्मा का प्रदेश कहा था. विवेक दास आचार्य कहते हैं कि कुंभ में शरीक होने की परंपरा में हम शामिल ज़रूर हो रहे हैं, पर कबीर ने जिस तरह रूढ़ियों-कुरीतियों पर प्रहार किया था, हम वही संदेश शिविरों के ज़रिये प्रसारित करेंगे. यह एक अभियान की तरह होगा. रूढ़िवादियों के मेले में कबीर की भाषा, वाणी और दर्शन के बारे में श्रद्धालुओं को अवगत कराया जाएगा.

22 अप्रैल से 21 मई तक एक माह चलने वाले शिविर में विवेक दास आचार्य के रोज़ाना प्रवचन का इंतजाम भी किया जा रहा है. कबीर के भजन गाने वालों की 25 टीमें शिविर में लगातार अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी. इसके अलावा रूढ़ियों के ख़िलाफ़ नाटकों और कबीर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा. कबीर पर आधारित फोटो प्रदर्शनी और पुस्तकों के लिए अलग से स्टॉल बनाए जा रहे हैं. कबीर की कर्मस्थली वाराणसी में मूल गादी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जाएगा. वाराणसी में नीरू के टीले (कबीर का जन्म स्थल) पर बन रही कबीर की हाईटेक कुटिया, संग्रहालय एवं स्मारक की झांकियां भी दिखाई जाएंगी.

कबीर ने मालवा को आत्मा का प्रदेश क्यों कहा था? यह पूछने पर विवेक दास ने कबीर से जुड़ी एक प्रेरक कथा सुनाई. राजा भर्तृहरि (भरथरी) पिंगला से बहुत प्रेम करते थे. पिंगला पर उनका सर्वस्व न्यौछावर रहता था. एक बार शिकार में हिरण मारने पर गुरु गोरखनाथ उनसे बहुत नाराज़ हुए. गोरखनाथ ने भरथरी से कहा कि मारने का हक़ उसे है, जो ज़िंदा भी कर दे. भरथरी ने गोरखनाथ को चुनौती दी. गोरखनाथ ने शर्त रखी कि भरथरी संन्यास ले लें, तो वह हिरण को ज़िंदा कर देंगे. भरथरी ने शर्त मान ली.

तीन एकड़ में स्थापित हो रहे कबीर शिविर को तीन हिस्सों में बांटा जा रहा है. एक हिस्सा सभागार, दूसरा प्रदर्शनी और तीसरा भोजन-आवास के लिए निर्धारित है. कबीर के करघे से प्रेरित डिजाइन वाला मुख्य प्रवेश द्वार बन रहा है. विवेक दास आचार्य ने चौथी दुनिया को बताया कि उज्जैन के गिरिधर मालवीय, इंदौर के सुरेश पटेल एवं डॉ. ताराचंद डोडवे, गुजरात के संत विक्रम दास समेत बड़ी तादाद में कबीर पंथी साधु शिविर के प्रबंधन में दिन-रात लगे हैं. उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में शामिल होने के फ़ैसले के बारे में उन्होंने कहा कि मालवा से शुरुआत इसलिए की जा रही है, क्योंकि कबीर ने उसे भक्ति का प्रदेश कहा था. इसके अलावा कुंभ आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक आस्था और विश्वास के प्रदर्शन का मेला होता है, जहां देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं. इसलिए किसी संदेश या सिद्धांत को सबके सामने रखने के लिए कुंभ से बेहतर कोई आयोजन नहीं हो सकता. कबीर चौरा मूल गादी द्वारा न सिर्फ़ वाराणसी, बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और कबीर का संदेश फैलाया जा रहा है. संत विवेक दास ने कहा कि कुंभ मेले में अन्य कबीर पंथी धाराओं के शिविर लगते रहे हैं, लेकिन मूल गादी वाराणसी की छावनी पहली बार लगने जा रही है. आचार्य ने कहा कि मूल गादी वाराणसी की सक्रिय शाखा गुजरात के जंबूसर में है, जिसकी देखरेख युवा महंत विक्रम दास करते हैं. उन्हें सिंहस्थ कुंभ के संयोजन का भी दायित्व दिया गया है.

कबीर ने मालवा को आत्मा का प्रदेश क्यों कहा था? यह पूछने पर विवेक दास ने कबीर से जुड़ी एक प्रेरक कथा सुनाई. राजा भर्तृहरि (भरथरी) पिंगला से बहुत प्रेम करते थे. पिंगला पर उनका सर्वस्व न्यौछावर रहता था. एक बार शिकार में हिरण मारने पर गुरु गोरखनाथ उनसे बहुत नाराज़ हुए. गोरखनाथ ने भरथरी से कहा कि मारने का हक़ उसे है, जो ज़िंदा भी कर दे. भरथरी ने गोरखनाथ को चुनौती दी. गोरखनाथ ने शर्त रखी कि भरथरी संन्यास ले लें, तो वह हिरण को ज़िंदा कर देंगे. भरथरी ने शर्त मान ली. गुरु ने मरे हुए हिरण को ज़िंदा कर दिया, लेकिन भरथरी को संन्यास की दीक्षा देने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि संन्यास के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है. गुरु ने भरथरी को अमरफल खाने को दिया. कहा कि इसे खाने से वह और सौंदर्यवान-देदिप्यमान हो जाएंगे. राजा ने वह फल पिंगला को दे दिया. पिंगला ने उसे एक सैनिक को दे दिया, जिससे वह गुपचुप प्रेम करती थी. सैनिक ने वह फल एक वेश्या को दिया, जिसके पास वह जाता रहता था. वेश्या ने सोचा कि देदिप्यमान होने की सबसे अधिक ज़रूरत राजा को है, जो पूरी प्रजा की देखभाल के लिए हमेशा चिंतित रहता है. वेश्या ने वह फल राजा को दे दिया.

फल के वापस लौट पर भरथरी के मन में वैराग्य का स्वाभाविक भाव जागा और तब गुरु गोरखनाथ ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी. उसके बाद भरथरी के भाई विक्रमादित्य राजा बने और चक्रवर्ती सम्राट बने. विक्रमादित्य अकेले ऐसे राजा हैं, जिनकी प्रशंसा कबीर ने अपने दोहों में की और मालवा को आत्मा का प्रदेश कहा. विक्रमादित्य अपने भाई भरथरी को मनाने चुनार (उत्तर प्रदेश) भी गए, जहां वह समाधि में रत थे, लेकिन भरथरी वापस नहीं लौटे. विक्रमादित्य ने चुनार में दुर्ग और भरथरी के समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण कराया. विवेक दास आचार्य ने कहा कि मालवा की इसी ऐतिहासिकता और उसके प्रति कबीर के भाव को आदर देते हुए मूल गादी ने सिंहस्थ कुंभ में शिविर लगाने का फ़ैसला लिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

अधूरी तैयारियों से लोगों में असंतोष

सोरिन शर्मा

उज्जैन में आगामी 22 अप्रैल से सिंहस्थ कुंभ शुरू हो रहा है. पिछले पांच वर्षों से सिंहस्थ की तैयारियां चल रही हैं, जो पूरी होने का नाम नहीं लेतीं. क्षिप्रा नदी प्रदूषित होने के कारण अभी तक नर्मदा का जल उसमें नहीं आ सका है. पिछले सिंहस्थ के दौरान क्षिप्रा में टैंकरों से पानी डालना पड़ा था. साधु-संत अभी से बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं, लेकिन अव्यवस्था के चलते उनमें असंतोष गहराता जा रहा है. सिंहस्थ के लिए राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से अपने वार्षिक बजट में प्रावधान करती आ रही है. बजट में निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए धनराशि तो आवंटित कर दी जाती है, लेकिन अभी भी कई कार्य अधूरे पड़े हैं. यूं तो उज्जैन शहर के विकास के लिए सामान्य बजट का प्रावधान रहता है, लेकिन एक सिंहस्थ के बाद दूसरे सिंहस्थ की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं. उज्जैन में बड़े निर्माण कार्यों के ठेके पिछले पांच वर्षों से चल रहे हैं. अधिकांश ठेके एक बड़ी कंपनी ने हथिया लिए थे, लेकिन उसने समय से कार्य शुरू नहीं किए. आधे कार्य तो पिछले वर्ष तक शुरू नहीं हो सके, जो बाद में अन्य कंपनियों एवं ठेकेदारों को देने पड़े.

मुख्यमंत्री के बेहद क़रीबी माने जाने वाले शख़्स की उक्त कंपनी के चलते अन्य ठेकेदारों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली. नतीजतन, कई निर्माण कार्य रोक दिए गए. सड़कें तक आपाधापी में बनवानी पड़ीं, क्योंकि उनका निर्माण समय पर शुरू नहीं किया गया. आज भी स्थिति यह है कि शहर की अनेक सड़कें जर्जर हालत में हैं. कई संस्थाओं एवं विपक्ष की ओर से निर्माण-विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें की गईं, लेकिन शासन-प्रशासन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया. यही स्थिति घाटों की मरम्मत-पुनर्निर्माण और उन्हें सजाने-संवारने की रही. घाटों पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, फिर भी उनकी स्थिति में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ. साधु-संतों का कहना है कि ऐसा लगता ही नहीं कि यहां सिंहस्थ शुरू होने वाला है.

सिंहस्थ मेले के लिए भूमि आवंटन को लेकर भी असंतोष की स्थिति बनी हुई है. गुप्तेश्वर मंदिर के पुजारी सात्विकानंद सिंहस्थ में ब्रह्म गायत्री, लक्ष्मी नारायण एवं शिव-पार्वती के विशेष अनुष्ठान के लिए भूमि मांग रहे हैं. राम स्नेही संप्रदाय सिंथल-खेड़ापा के साधु-संतों ने प्रभारी मंत्री का घेराव कर आवंटित भूमि पर उनके कार्यों में बाधा पहुचाने की शिकायत की. संतों का कहना है कि उन्हें नवंबर में ही भूमि आवंटित कर दी गई थी, बावजूद इसके उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है. दूसरी तरफ़ महानिर्वाणी अखाड़े ने सिंहस्थ के बहिष्कार की चेतावनी दी है. अखाड़े के संतों ने मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्र सौंप कर मेला प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया. तीनों वैष्णव अणि अखाड़ों के 50 से अधिक संतों ने भी अव्यवस्था के ख़िलाफ़ विरोध दर्ज कराया है. प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक़, सिंहस्थ के लिए राज्य सरकार तीन हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने अब तक एक पैसा नहीं दिया.

क्षिप्रा का प्रदूषण भी विरोध का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. सिंहस्थ का स्नान क्षिप्रा के भूगर्भीय जल से कराने और नदी के सीमांकन-शुद्धिकरण की मांग को लेकर डटे निर्मोही अणि अखाड़े के संत गणेश दास ने मनरेगा एवं ओजोनेशन योजना के लिए स्वीकृत नौ करोड़ रुपये से त्रिवेणी से क्षिप्रा बैराज तक 100-100 फीट की दूरी पर गहरे कुएं खोदे जाने की मांग की. सिंहस्थ के लिए राज्य परिवहन विभाग ने 50 लाख रुपये का बजट तैयार किया है, लेकिन अब तक उसे स्वीकृति नहीं मिली. दूसरी तरफ़ रेलवे का पायलट प्रोजेक्ट भी अधूरा पड़ा है. सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन, वाटर वेंडिंग मशीन एवं मल्टी आउटलेट यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई गई थी. सभी काम पायलट प्रोजेक्ट के तहत होने थे, मगर सिंहस्थ से पहले ही सभी

योजनाएं बेपटरी होती नज़र आ रही हैं. सिंहस्थ कुंभ में क़रीब पांच करोड़ श्रद्धालुओं के पहुचने की संभावना है. क़रीब पाच लाख से अधिक यात्री रोज ट्रेनों से सफर करेंगे. ऐसे में रेलवे पर व्यवस्था का दारोमदार अधिक है. उज्जैन के मुख्य रेलवे स्टेशन की हालत भी नहीं सुधरी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सिंहस्थ की पूरी कमान अपने पास रखी है और सभी अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री निवास से दिए जाते हैं. प्रभारी मंत्री के रूप में भूपेंद्र सिंह को तैनात किया गया है, जो मुख्यमंत्री के विश्वस्त मंत्रियों में शामिल हैं, लेकिन प्रशासन पर उनकी पकड़ काफ़ी ढीली है. सिंहस्थ कुंभ का काम मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैंस देख रहे हैं. सिंहस्थ मेला प्रभारी के रूप में एक तरफ़ मुख्यमंत्री कार्यालय केविश्वस्त अधिकारी नीरज वशिष्ठ को तैनात किया गया, तो दूसरी तरफ़ इंदौर नगर निगम के आयुक्त मनीष सिंह भी अतिरिक्त प्रभारी बनाए गए हैं. मेला प्राधिकरण केअध्यक्ष के रूप में माखन सिंह चौहान को नियुक्त तो किया गया है, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है. कुल मिलाकर सरकार उज्जैन सिंहस्थ से राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयां और धार्मिक पर्यटन को विश्व में स्थान मिलने का ख़्वाब तो देख रही है, लेकिन उसे अपेक्षित भव्यता प्रदान करने में नाकाम साबित हो रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कबीर को ज़िंदा रखेगी आधुनिक तकनीक

संत कबीर की कर्मभूमि, साधना पीठ और उपदेश स्थली कबीर चौरा मठ (मूल गादी) में बन रही हाईटेक झोपड़ी के बारे में विवेक दास आचार्य ने कहा कि इस कार्य में लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे. कबीर की झोपड़ी को हाईटेक बनाने का विचार नीदरलैंड का संग्रहालय देखने के बाद आया. झोपड़ी को जीवंत बनाने के लिए नीदरलैंड संग्रहालय से भी सहयोग मांगा गया है. निर्माण में नीदरलैंड और जर्मनी के उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा. मठ परिसर में 15 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी दो झोपड़ियां बनाई जाएंगी. एक में कबीर द्वारा संचालित करघा रहेगा और दूसरे में आवास. झोपड़ियों की परिक्रमा कर लोग कबीर की जीवनी से स्वचालित तरीकेसे रूबरू होंगे. परिसर में घुसते ही मुगलकालीन खिड़कियां स्वत: खुल जाएंगी. अंदर करघा चलने की आवाज़ सुनाई देगी. मंडप में प्रवेश करते ही स्वागत का स्वर गूंजेगा और 15 मिनट कबीर वाणी सुनाई जाएगी. इसी स्थली पर 60 फुट ऊंचा कांस्य एवं मीरजापुरी पत्थरों का स्तूप भी बनेगा. अभी मूल गादी में कबीर केतमाम वृत्तांत मूर्तियों के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं. कबीर की झोपड़ी के सामने 40 फुट का स्तंभ होगा, जो धातु का होगा और उसमें सात रंग का कपड़ा लगा होगा. यह रात में रंग-बिरंगी छटा बिखेरेगा. इसे बनाने का काम मुंबई में चल रहा है. यह कबीर के करघे का प्रतीक होगा. कबीर मठ को हाईटेक बनाने के प्रोजेक्ट पर चार करोड़ 66 लाख रुपये की लागत आएगी. विवेक दास आचार्य कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ़ से आर्थिक सहायता की घोषणा हो चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार भी इस कार्य में अवश्य मदद करेगी. ■

जीवन चलने का नाम

मणिपुर की इन विधवाओं के हौसले को सलाम

एस. बिजेन सिंह

मरने वाला कभी अकेला नहीं मरता. उसके साथ मरती हैं कई और ज़िंदगियां. ताउम्र, तिल-तिल कर. हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर की उन विधवाओं की, जिनके पति पुलिस-सेना और चरमपंथी संगठनों के बीच जारी जंग का शिकार बन गए. मणिपुर, जिसकी आबादी महज 27 लाख है, में ऐसी विधवाएं आपको हर जगह मिल जाएंगी. अब तक आपने वृंदावन या बनारस में विधवाओं का जमघट देखा होगा, लेकिन वृंदावन की विधवाओं और मणिपुर की विधवाओं में एक बुनियादी फ़र्क़ है. वृंदावन आने वाली विधवाओं का मामला जहां धार्मिक है, वहीं मणिपुर की विधवाओं की कहानी हमारी व्यवस्था, पुलिस, सरकार एवं समाज की संवेदनहीनता और नाकामी की कहानी है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 20 हज़ार ऐसी विधवाएं हैं, जिन्होंने अपना पति सशस्त्र संघर्ष के चलते गंवा दिया. असल आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है. अकेले 2007 से 2015 के बीच राज्य में 3,867 हिंसक घटनाएं हुईं, जिनमें 1,205 चरमपंथी और 486 आम नागरिक मारे गए. अब जरा सोचिए, ये विधवाएं, जिन्होंने अपना पति खो दिया, कैसे अपना भरण-पोषण करती होंगी? क्या उन्हें विधवा पेंशन या अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि इस तरह मरने वाले शख्स के परिवार को आम तौर पर कोई शासकीय सहायता तब तक नहीं मिलती, जब तक अदालत में साबित न हो जाए कि वह चरमपंथी नहीं था. सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसी विधवाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना है या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है? क़ाबिले ग़ौर बात यह है कि सरकार की तमाम उपेक्षा के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसी विधवा महिलाएं वक्त की चुनौती स्वीकार करते हुए न सिर्फ़ अपना और परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं, बल्कि बच्चों को पढ़ा भी रही हैं. इसके लिए उन्होंने हथियार बनाया अपने हुनर को, अपनी मेहनत को. वे आज बुनाई, कढ़ाई के अलावा खेती-बाड़ी में अपना पसीना बहा रही हैं. और संदेश दे रही हैं कि अगर हौसला हो, तो कठिन से कठिन हालात का मुक़ाबला भी हंसते-हंसते किया जा सकता है.

जीवनयापन करने के लिए एक छोटी-सी दुकान में खाने-पीने का सामान और पान बेचती इदिना वाइखोम

हमने मणिपुर के क़रीब तीन सौ गांवों में जाकर विधवा महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया. दु:ख की बात यह है कि हमें सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता. अच्छी बात यह है कि मणिपुर की महिलाएं स्वभावत: आत्मनिर्भर होती हैं. उन्हें बुनाई की कला बचपन से आती है. जिनके पास थोड़ी-बहुत ज़मीन है, वे सब्जी वगैरह उगाकर पैसा कमा लेती हैं. हमने मणिपुर में 37 बुनाई सेंटर बनाए हैं, जहां उक्त विधवा महिलाएं अपने द्वारा बनाई गई वस्तुएं लाती हैं, जिन्हें हम दिल्ली और अन्य शहरों में बिक्री के लिए भेज देते हैं. मणिपुर की उक्त विधवा महिलाएं सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, संघर्ष करके आगे बढ़ना उनकी खासियत है.

-बीनालक्ष्मी नेप्रम,
मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क.

पूर्वी इंफाल के थोंगजु निवासी नामैराकपम जिलागमबी देवी ने सशस्त्र संघर्ष के चलते अपना पति गंवा दिया. वह आज बुनाई का काम करती हैं. तीन बच्चों की मां नामैराकपम जिलागमबी देवी को मणिपुरी शॉल और खुदै मतेक (मणिपुरी पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र) बनाने में महारथ हासिल है. अपनी अल्प आय से वह न सिर्फ़ परिवार चलाती हैं, बल्कि उनके तीनों बच्चे पढ़ने भी जाते हैं. इसी तरह लाइश्रम मेमचा (45) थऊबाल ज़िले के लांगमैडोंग मनिंग लैकाइ की रहने वाली हैं. मेमचा पति की मौत के बाद बुनाई का काम करने लगीं. वह वांगखै फी (मणिपुरी महिलाओं द्वारा शादी में पहना जाने वाला वस्त्र) बनाती हैं. वांगखै फी के एक पीस की लागत चार से पांच हज़ार रुपये आती है. मेमचा पिछले 20 वर्षों से यह काम कर रही हैं. वह अपने सात वर्षीय बेटे के साथ रहती हैं. मेमचा अपने वांगखै फी के लिए खासी शोहरत हासिल कर चुकी हैं. वह ऑर्डर मिलने पर ग्राहकों की मांग के अनुसार वस्त्रों में डिजाइन भी करती हैं.

चांदेल ज़िले के कांगशांग गांव निवासी मोनिंगसान को गुज़रे 14 वर्ष हो गए. पति की मौत के बाद तोनतांगा तुंगफेर ने परिवार की ज़िम्मेदारी संभाली. मोनिंगसान के निधन के वक्त उनकी बेटी महज डेढ़ वर्ष की थी, जिसे पालने के लिए तोनतांगा तुंगफेर ने जो भी काम मिला, उसे किया. तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली. इलाके में जीवनयापन का एकमात्र ज़रिया मौसमी खेती है. तोनतांगा दिल की मरीज होने के बावजूद जमकर मेहनत करती हैं. वह खेती-बाड़ी, मज़दूरी, बुनाई यानी जो भी काम मिलता है, करती हैं. वह अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं.

इस हिंसा की वजह क्या है

पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में देश आज़ाद होने से लेकर अब तक सशस्त्र विद्रोह चल रहा है. राजधानी इंफाल डिस्टर्ब एरिया घोषित है. पूर्वोत्तर में लागू ऑर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफ्सपा) 1958 के तहत सेना को किसी भी शख्स को शक के आधार पर गिरफ्तार करने या गोली मारने का अधिकार हासिल है. सेना यह काम बेहिचक अंजाम देती है. दूसरी तरफ़ राज्य में 37 चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं, जो खुद को भारत से अलग मानते हुए सशस्त्र युद्ध कर रहे हैं. पुलिस-सेना और चरमपंथी संगठनों के बीच जारी इस जंग में निर्दोष आम नागरिक पिस रहे हैं. चरमपंथी भी आम मणिपुरी लोगों से वसूली करते हैं, उन्हें धमकाते हैं और उनकी हत्या तक कर देते हैं. ■

इदिना वाइखोम ने आख़िरी बार पति आनंद निंथौजम को तब देखा था, जब वह सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले थे. शाम को इदिना को पता चला कि मुठभेड़ में आनंद और एक अन्य शख्स को मार दिया गया. इदिना अब एक छोटी-सी दुकान में खाने-पीने की चीजें और पान आदि बेचती हैं. उसी अल्प आय से उनका जीवनयापन होता है. 43 वर्षीय रमथारमावी चूड़ाचांदपुर ज़िले के मॉलवाइफै गांव में अपने घर के बाहर बैठी शाम का खाना पका रही थीं. उनके पास तीन बेटे और बेटी भी बैठे थे. बड़े बेटे की उम्र 21 वर्ष और बेटी की उम्र 13 वर्ष थी. रमथारमावी को अचानक स्थानीय ग्राम परिषद अध्यक्ष ने बुलाया और बताया कि उनके पति, जो इंफाल स्थित रिम्स हॉस्पिटल में चपरासी थे, की लाश हॉस्पिटल के शवगृह से मिली है. रमथारमावी के पति हॉस्पिटल में अनुबंध पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें पेंशन का हक़दार नहीं माना गया. सगे-संबंधी भी नहीं थे, जो रमथारवामी को मदद करते. रमथारवामी बुनाई का काम करती हैं. वह फनेक (मणिपुरी महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला कपड़ा) बनाती हैं. वह एक महीने में दो फनेक बना पाती हैं, जिसकी लागत प्रति पीस दो हज़ार रुपये आती है. रमथारवामी सुबह चार बजे उठकर काम में जुट जाती हैं. वह अपने काम से बहुत खुश हैं. रमथारवामी शादी से पहले भी फनेक बनाती थीं.

मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क की संस्थापक बीनालक्ष्मी नेप्रम का मानना है कि हिंसा में मारे गए लोगों का सरकारी आंकड़ा कम करके दिखाया गया है. नेप्रम का कहना है कि बड़ी संख्या में मौतों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है. मात्र दो फ़ीसद विधवाओं को सरकारी मदद मिल पाती है. नेप्रम कहती हैं कि ज़्यादातर मामले फर्जी मुठभेड़ के हैं. मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क फर्जी मुठभेड़ में पति खो चुकी महिलाओं की मदद के लिए 2004 में शुरू किया गया था. नेटवर्क की को-ऑर्डिनेटर रीना मुतुम के मुताबिक, नेटवर्क में पांच हज़ार से ज़्यादा महिलाएं शामिल की गई हैं, जिनमें वे महिलाएं भी हैं, जिनके पति मुठभेड़ में मारे गए. जो घटना नेटवर्क की स्थापना की वजह बनी, वह थी 24 दिसंबर, 2004 को 27 वर्षीय बुद्धि नामक युवक की हत्या. बुद्धि एक कार बैट्री वर्कशॉप में काम करता था. हथियारों से लैस तीन लोगों ने उसे उठाकर वर्कशॉप से कुछ दूरी पर मार गिराया. बुद्धि की पत्नी रेबिका अखाम आज तक समझ नहीं सकीं कि उनके पति को क्यों मारा गया. बीनालक्ष्मी ने रेबिका को 4,500 रुपये की आर्थिक मदद के साथ-साथ एक सिलाई मशीन भी दी.

अपनी बेटी को पालने के लिए बुनाई का कार्य करतीं रमथारमावी

नेटवर्क अब तक पांच हज़ार से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुलवा चुका है. मणिपुर की इन विधवाओं को बुनाई का धागा और सब्जी बीज खरीदने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है. नेटवर्क हैंडलूम-हैंडिक्राफ्ट से संबंधित सारे संसाधन मुहैया कराता है. 300 से ज़्यादा गांवों में सक्रिय यह नेटवर्क इन विधवाओं द्वारा बनाए गए कपड़े और सामान बाज़ार तक पहुंचाता है, जिससे उनकी सही क़ीमत मिल सके. पिछले दिनों कंट्रोल ऑर्म्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया और मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट और नैचर बाज़ार में फनेक, कुकी शॉल, खमथंग शॉल, सिल्क दुपट्टा और पारंपरिक वस्त्र लैरूम की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की थी. ■

sbijensngh@gmail.com

करघे पर बुनाई का प्रशिक्षण लेती मणिपुर वुमेन गन सर्वाइवर नेटवर्क से जुड़ी विधवाएं

शत्रु संपदा क़ानून में पिस रहे बांग्लादेशी हिंदू

भारत और नेपाल के बाद हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी बांग्लादेश में है. नेपाल में क़रीब ढाई करोड़ हिंदू हैं, वहीं बांग्लादेश में क़रीब डेढ़ करोड़. 1947 में विभाजन के वक्त पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हिंदुओं की आबादी 28 फ़ीसद थी. 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 1981 में वहां पहली जनगणना हुई, जिसमें हिंदुओं की आबादी महज 12 फ़ीसद रह गई, जो 2011 की जनगणना में घटकर नौ फ़ीसद रह गई.

पापड़ बना रही हिंदू महिलाएं

मौजूदा जातीय संसद में हिंदू सांसद

	सांसद	निर्वाचन क्षेत्र	पार्टी
1.	रमेश चंद्र सेन	ठाकुरगांव (01)	बांग्लादेश अवामी लीग
2.	मनोरंजन साहिल गोपाल	दिनाजपुर (01)	बांग्लादेश अवामी लीग
3.	टीपू मुंशी	रंगपुर (04)	बांग्लादेश अवामी लीग
4.	साधन चंद्र मजूमदार	नौगांव (01)	बांग्लादेश अवामी लीग
5.	रंजीत कुमार रॉय	जैसोर (04)	बांग्लादेश अवामी लीग
6.	स्वप्न भट्टाचार्य	जैसोर (05)	निर्दलीय
7.	वीरेन सिकंदर	मागुरा (02)	बांग्लादेश अवामी लीग
8.	पंचानन विश्वास	खुलना (02)	बांग्लादेश अवामी लीग
9.	नारायण चंद्र चंदा	खुलना (05)	बांग्लादेश अवामी लीग
10.	धीरेंद्र देवनाथ शंभु	बारगुना (01)	बांग्लादेश अवामी लीग
11.	पंकज नाथ	बारिसाल (04)	बांग्लादेश अवामी लीग
12.	अनुपम शाहजहां जॉय	टांगिल (08)	बांग्लादेश अवामी लीग
13.	प्रमोद मानकिन	मैमन सिंह	बांग्लादेश अवामी लीग
14.	छवि विश्वास	नेत्रोकोना (01)	बांग्लादेश अवामी लीग
15.	सुकुमार रंजन घोष	मुंशीगंज (01)	बांग्लादेश अवामी लीग
16.	मृणाल कांति दास	मुंशीगंज (03)	बांग्लादेश अवामी लीग
17.	सुरजजीत सेनगुप्ता	सुनामगंज (02)	बांग्लादेश अवामी लीग
18.	डॉ. दीपू मोनी	चांदपुर (03)	बांग्लादेश अवामी लीग
19.	वीर बहादुर सिंह	बंदरवन	बांग्लादेश अवामी लीग

अभिषेक रंजन सिंह

बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं की जान-माल की सुरक्षा से संबंधित ख़बरें भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं. यह सच है कि बांग्लादेश में आएदिन हिंदुओं पर हमले होते हैं और उनकी संपत्तियों एवं धर्मस्थलों को कट्टरपंथी तत्वों द्वारा नुक़सान पहुंचाया जाता है, लेकिन इस आधार पर यह मान लेना कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए एक कत्लगाह बन गया है, ग़लत है. पिछले महीने जब मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में था, तो स्थानीय अख़बारों-समाचार चैनलों में एक हिंदू पुजारी की हत्या से जुड़ी ख़बरें दो-तीन दिनों तक प्रमुखता से प्रकाशित-प्रसारित हुईं. घटना के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने ढाका की सड़कों पर मार्च निकाला. स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने सक्रियता दिखाई और दो दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बांग्लादेश में हिंदुओं के ख़िलाफ़ होने वाली यह पहली और अंतिम घटना नहीं है. पिछले वर्ष ढाका में कट्टरपंथियों ने कुछ हिंदू ब्लॉगरों की हत्या कर दी थी. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दावा करने वाली शेख हसीना सरकार भी इन हालिया घटनाओं के बाद सवालों के घेरे में है. ज़्यादातर भारतीयों का मानना है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की दशा पाकिस्तान जैसी है, लेकिन यह हक़ीक़त नहीं है. बांग्लादेश जाने से पहले खुद मेरे ज़ेहन में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल थे, लेकिन वहां के विभिन्न शहरों-गांवों में घूमने और लोगों से मिलने के बाद बहुत कुछ खुलासा हुआ.

बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में सहायक सचिव वारिस हसैन के अनुसार, कुछ घटनाओं के आधार पर यह मान लेना कि यहां हिंदुओं के साथ जुल्म होता है या उनके साथ ग़ैर बराबरी की जाती है आदि एकतरफ़ा बातें हैं. बांग्लादेश की राजनीति, शिक्षा, प्रशासन एवं फिल्म-संगीत जगत में हिंदुओं की अच्छी-खासी भागीदारी है. बांग्लादेश की 350 सदस्यीय दसवीं जातीय संसद में 19 सांसद हिंदू हैं. यह संख्या पिछले कई वर्षों के मुक़ाबले अधिक है. प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार में शामिल मंत्रियों के निजी सचिवों में क़रीब 40 फ़ीसद हिंदू हैं, सिविल सेवाओं में 40 फ़ीसद अधिकारी हिंदू हैं और स्कूल-कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में 20 से 25 फ़ीसद शिक्षक-शिक्षेत्तर कर्मचारी हिंदू हैं. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा भी हिंदू हैं. बेशक, बांग्लादेश एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन वहां हिंदुओं के प्रति नफरत और ग़ैर बराबरी का कोई भाव नहीं है. इस बार संसद भवन में सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्री-सांसद शामिल हुए. बांग्लादेश में दुर्गा पूजा, होली एवं दीवाली धूमधाम से मनाई जाती है. सिर्फ़ ढाका में कई स्थानों पर दुर्गा पूजा होती है. सरकार ने हिंदुओं के कई महत्वपूर्ण त्योहारों पर सरकारी अवकाश घोषित कर रखा है. सामाजिक कार्यकर्ता आशमा रहमान के मुताबिक, विश्वविद्यालय में उनके ज़्यादातर दोस्त हिंदू थे. बांग्लादेश में भूमिहीनों की लड़ाई लड़ रहे सुबल सरकार के मुताबिक, हिंदुओं पर ज़्यादातर हमले संपत्ति के लालच में किए जाते हैं. बावजूद इसके अल्पसंख्यक समुदाय को देश की न्याय पालिका पर भरोसा है.

राजधानी ढाका से क़रीब 250 किलोमीटर दूर स्थित नौगांव (पूर्व में राजशाही) ज़िले में एक गांव है पतिसर, जिसकी आबादी क़रीब छह हज़ार है, जिनमें चालीस-पचास परिवार हिंदुओं के हैं. पतिसर निवासी 60 वर्षीय रंजीत साहा के पास खेती योग्य पांच बीघा ज़मीन है. उनके मुताबिक, बंटवारे से पहले गांव में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी, लेकिन 1947 के बाद संपन्न हिंदू भारत चले गए. उसके बाद 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान भी कई हिंदू परिवार भारत चले गए. रंजीत के अनुसार, यहां के हिंदू परिवार शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. हिंदुओं के पूजा-पाठ एवं अन्य धार्मिक आयोजनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. एक चबूतरे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां कभी काली मंदिर था, जो कई वर्ष पहले गिर गया. क्या उसे मुसलमानों ने गिराया? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नहीं, काफी पुराना होने की वजह से गिर गया. रंजीत मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए अवामी लीग के स्थानीय सांसद इसराफिल आलम से मिलना चाहते हैं. थोड़ी दूर पर रवींद्र नाथ टैगोर के बेटे के नाम पर एक सरकारी स्कूल है, जहां छात्र-छात्राओं की खासी संख्या देखने को मिली. भारत या अन्य देशों में बैठकर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति भले भयावह दिखती हो, लेकिन सच्चाई इसके उलट है. राजनीति, उद्योग, शिक्षा, शासन-प्रशासन में हिंदुओं की जो हिस्सेदारी है, उसके बारे में कभी कोई ख़बर भारत में नहीं दिखाई जाती.

फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी क़रीब नौ फ़ीसद है. हालांकि, 1951 के बाद हर वर्ष हिंदुओं की संख्या में गिरावट आई है. पहली जनगणना (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) के समय बांग्लादेश में मुसलमानों की कुल आबादी तीन करोड़ 22 लाख थी, जबकि हिंदुओं की 92,39,000. मौजूदा समय में हिंदुओं की आबादी महज एक करोड़ 22 लाख है, जबकि मुसलमानों की 12 करोड़ 63 लाख. बांग्लादेश में बौद्ध आबादी में भी काफी कमी आई है. 2013 में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता दिलावर हुसैन को 1971 के युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी. इस फ़ैसले के बाद जमात-ए-इस्लामी समर्थकों ने अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया. ग़ौरतलब है कि 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुक्ति युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याओं और बलात्कार के मामले में दिलावर को दोषी पाया गया था. अमेरिका निवासी बांग्लादेशी मूल के एक प्रोफेसर ने अपनी किताब गॉड विलिंग: द पॉलिटिक्स ऑफ इस्लामिज्म इन बांग्लादेश में उल्लेख किया है कि बीते 25 वर्षों में बांग्लादेश से 53 लाख हिंदू पलायन कर गए. दरअसल, बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी जैसी कुछ ऐसी कट्टरपंथी पार्टियां हैं, जो देश को पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाना चाहती हैं. बांग्लादेश पहले एक धर्मनिरपेक्ष देश था, लेकिन 1977 में संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया और 1988 में बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया. प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग को अल्पसंख्यकों के लिए उदार माना जाता है. मौजूदा संसद में 19 सांसद हिंदू हैं, जिनमें 18 अवामी लीग से हैं. बांग्लादेश में लागू शत्रु संपत्ति क़ानून को लेकर भी हिंदुओं में

गांव पातेसर (नौगांव) में रंजीत साहा अपने परिवार के साथ

नाराज़गी है. उनका मानना है कि यह क़ानून हिंदुओं को उनकी अचल संपत्तियों से बेदख़ल करने का ज़रिया है. पिछले कुछ वर्षों में शत्रु संपत्ति अधिनियम के चलते लाखों हिंदुओं को अपनी संपत्तियों से हाथ धोना पड़ा.

एक अनुमान के मुताबिक, इस अधिनियम के तहत हिंदुओं के स्वामित्व वाली लगभग 20 लाख एकड़ भूमि हड़प ली गई, जो बांग्लादेश की कुल भूमि का पांच फ़ीसद है और हिंदुओं के स्वामित्व वाली भूमि का लगभग 45 फ़ीसद. शत्रु संपत्ति अधिनियम के शिकार बौद्ध समुदाय के लोग भी हुए. चिटगांव डिवीजन के तीन ज़िलों बंदरबन, खग्राछारी एवं रंगमती में बौद्ध समुदाय की 22 फ़ीसद भूमि छीन ली गई. इन इलाकों में 1978 में बौद्धों के पास 83 फ़ीसद भूमि थी, जो 2009 में घटकर 41 फ़ीसद रह गई. बांग्लादेश में शत्रु संपदा अधिनियम के अलावा वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट भी है. इन दोनों क़ानूनों के तहत किसी भी नागरिक को देश का दुश्मन घोषित करके उसकी संपत्ति हड़प ली जाती है. इन क़ानूनों के शिकार क़रीब 10 लाख हिंदुओं के मुक़दमे अदालत में लंबित हैं. सुबल सरकार के अनुसार, शत्रु संपदा अधिनियम उन तत्वों के लिए हथियार बन गया है, जिनकी नज़र अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर है. सरकार को इस क़ानून पर विचार करना चाहिए, वरना वह दिन दूर नहीं, जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पूरी तरह भूमिहीन हो जाएंगे. यह क़ानून 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने बनाया था. 1965 की लड़ाई के बाद जो लोग पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) छोड़कर भारत चले गए, उनकी अचल संपत्ति सरकार ने शत्रु संपदा घोषित कर दी.

1971 के मुक्ति युद्ध के समय भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं ने भारत में बसने का फ़ैसला किया. ऐसा नहीं था कि उनके परिवार के सभी लोग भारत में बस गए. उनमें से कई लोगों के पिता-भाई वहीं रह गए. बांग्लादेश में रहने वाले इन पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनकी संपत्तियां बाप-दादा के नाम पर हैं और अगर परिवार के कुछ लोग भारत चले गए, तो उन्हें उनकी संपत्ति से बेदख़ल क्यों किया जा रहा है? सवाल यह है कि 1965 में जब शत्रु संपदा विधेयक लागू हुआ था, उस वक्त तो पाकिस्तान था. लेकिन, 1971 के मुक्ति युद्ध के समय भारत गए लोगों की संपत्तियां शत्रु संपदा अधिनियम और वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में क्यों शामिल की गईं? क्या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की ऐतिहासिक मदद और हज़ारों भारतीय सैनिकों की कुर्बानी का यही प्रतिफल है? बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस (रिटायर्ड) सिकंदर मकबूल हक़ के मुताबिक, ज़िला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में शत्रु संपदा अधिनियम से जुड़े लाखों मामले लंबित हैं. निश्चित रूप से इस क़ानून की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यह उन तत्वों के लिए मुफीद हो गया है, जो अल्पसंख्यक समुदायों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं. दरअसल, शत्रु संपदा अधिनियम न सिर्फ़ बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक समस्या है, बल्कि यह क़ानून भारत में भी लागू है. भारत में 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए लोगों की संपत्तियां शत्रु संपदा घोषित कर दी गई हैं. पुरानी दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई एवं कोलकाता में हज़ारों ऐसी अचल संपत्तियां हैं, जिन्हें भारत सरकार ने शत्रु संपदा घोषित कर रखा है. इसके लिए बाकायदा एक कस्टोडियन बनाया गया है. भारत में शत्रु संपत्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विवाद राजा महमूदाबाद से संबंधित है. हालांकि, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुक़ाबले इस मामले में भारत सरकार और अदालतों का रवैया बेहतर है. भारत में इस क़ानून की लगातार समीक्षाएं हुईं और महत्वपूर्ण संशोधन भी. बांग्लादेश में भी शत्रु संपदा अधिनियम और वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन की पहल हुई है, लेकिन वह नाकाफी है.

2003 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट में अहम बदलाव करने का फ़ैसला किया, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं को उसका पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका. बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस (रिटायर्ड) मोहम्मद गुलाम रब्बानी डिप्रिवेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश लिविंग विथ वेस्टेड प्रॉपर्टी नामक किताब की भूमिका में लिखते हैं, शत्रु संपदा अधिनियम की वजह से बांग्लादेशी हिंदू कितने परेशान हैं, इस बात का अनुभव मुझे तब हुआ, जब मैं 1969 में ढाका हाईकोर्ट में वकालत कर रहा था. इस सिलसिले में नौगांव निवासी एक हिंदू परिवार का केस मेरे समक्ष आया, जो तीन भाइयों से जुड़ा था. 1952 में एक भाई भारत चला गया. बाकी दो भाई नौगांव में अपने पैतृक गांव में रह गए. स्थानीय प्रशासन ने भारत गए व्यक्ति के हिस्से वाली ज़मीन शत्रु संपदा घोषित कर अपने कब्जे में ले ली. अधिकारियों ने उसके भाइयों की कोई दलील नहीं सुनी. नतीजतन, उन्होंने हाईकोर्ट में केस दायर करने का फ़ैसला किया. मुझे खुशी है कि उस मामले में न्याय की जीत हुई और उस हिंदू परिवार को उनकी ज़मीन वापस मिल गई. दूसरा वाकया बोगरा ज़िले से संबंधित था. एक हिंदू कारोबारी की चावल और सरसों तेल की मिलें थीं, जो 1962 में भारत में बस गए, लेकिन उनके दोनों सगे भतीजों ने बोगरा में रहने का फ़ैसला किया. ज़िला प्रशासन ने उक्त मिलों को शत्रु संपदा घोषित कर उन्हें कब्जा लिया. पीड़ित पक्ष ने मेरी सलाह पर हाईकोर्ट में मुक़दमा किया और अंततः उन्हें जीत हासिल हुई. जस्टिस रब्बानी के मुताबिक, जहां इस तरह के लाखों मुक़दमे अदालत में लंबित हों, वहां चंद मामलों में जीत का कोई महत्व नहीं है. सरकार और न्याय पालिका को इस क़ानून की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ़ अमानवीय है, बल्कि असंवैधानिक भी है.

भारत और नेपाल के बाद हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी बांग्लादेश में है. नेपाल में क़रीब ढाई करोड़ हिंदू हैं, वहीं बांग्लादेश में क़रीब डेढ़ करोड़. 1947 में विभाजन के वक्त पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हिंदुओं की आबादी 28 फ़ीसद थी. 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 1981 में वहां पहली जनगणना हुई, जिसमें हिंदुओं की आबादी महज 12 फ़ीसद रह गई, जो 2011 की जनगणना में घटकर नौ फ़ीसद रह गई. 1947 के बाद से बांग्लादेश में इस्लामीकरण के नाम पर क़रीब 30 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया. 2013 और 2014 में बांग्लादेश के विभिन्न ज़िलों में क़रीब चार दर्जन मंदिरों और सैकड़ों हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई. इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी की नीतियों के चलते कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिला. जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में ईश निंदा क़ानून लागू करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक प्रयास कर रही है. कुछ वर्ष पहले इसे लेकर राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी. ईशनिंदा क़ानून वही काला क़ानून है, जो पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक़ ने लागू किया था. पाकिस्तान में इस क़ानून के चलते अल्पसंख्यकों को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, यह पूरी दुनिया को मालूम है. पाकिस्तान में इसी क़ानून की मुखालफत करने की वजह से कुछ वर्ष पहले पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज भट्टी की हत्या कर दी गई थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

राजनीति संविधान सम्मत होनी चाहिए

आख़िरकार भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविक राजनीति करने का फ़ैसला कर लिया है. उसके तमाम आदर्शवाद और कांग्रेस विरोधी विचार अब ख़त्म हो गए हैं. पहले अरुणाचल प्रदेश में और अब उत्तराखंड में पार्टी वही नीति अपना रही है कि पैसा देकर दो-चार विधायकों को इधर-उधर से इकट्ठा कर लो, मंत्री पद का लालच दे दो और काम पूरा हो गया. दरअसल, अब पार्टी विथ डिफरेंस पूरी तरह ख़त्म हो गई है. वेंकैया नायडू ने अपने बयान में यह दावा किया है कि कांग्रेस दलबदल की जननी है. तो अब सवाल यह उठता है और जैसा कि मैंने अपने ट्वीट में कहा था कि बेचारी भाजपा केवल कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को आगाह करते हुए कहा है कि विभिन्न विषयों पर हर एक सदस्य को हर जगह बोलना आवश्यक नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी सदस्यों को अपना ध्यान अपने क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रखना चाहिए. दरअसल, यह एक ऐसी सलाह है, जिसके आने में थोड़ी देर हो गई है. विभिन्न योगियों और साध्वियों आदि के ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयानों से देश का वातावरण पहले से ही ख़राब हो चुका है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री की हिदायत के बाद ऐसे लोग अपने बयानों-भाषणों में संयम बरतेंगे. ज़ाहिर है कि प्रधानमंत्री ने अभी भी जेएनयू प्रकरण पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. दरअसल, मोदी को छात्र समुदाय को यह यकीन दिलाना चाहिए था कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी मिलेगी. अरुण जेटली कह रहे हैं कि देश में अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, लेकिन भारत की बर्बादी के लिए नहीं. यह मेरी समझ से बाहर है कि कोई भाषण देकर भारत को कैसे बर्बाद कर सकता है? सरकार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा, सभी इस मामले को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दे रहे हैं. भारत कोई शीशे का गिलास नहीं है कि कोई इसे ज़मीन पर गिरा दे और इसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएं. भारत एक बहुत विशाल देश है और मैं नहीं समझता कि कोई इसे तोड़ सकता है. यहां तक कि अगर माओवादी अपनी पूरी ताकत लगा लें, तब भी यह संभव नहीं है. कम से कम छात्र तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, वे महज अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं. आप जितना अधिक उन्हें खामोश करने की कोशिश करेंगे, वे उतने ही बड़े नेता बनकर उभरेंगे. सरकार की ग़लतियों से एक नेता पैदा हो गया. दरअसल, कन्हैया एक ऐसा नेता बन गया, जिसके बारे में खुद उसने भी नहीं सोचा होगा. लिहाज़ा मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री के मशविरे पर उनकी पार्टी के लोग अमल करेंगे. यह एक सराहनीय क़दम है. कुछ देर हो गई है, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा क़दम है.

दूसरा मुद्दा यह कि आख़िरकार भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविक राजनीति करने का फ़ैसला कर लिया है. उसके तमाम आदर्शवाद और कांग्रेस विरोधी विचार अब ख़त्म हो गए हैं. पहले अरुणाचल प्रदेश में और अब उत्तराखंड में पार्टी वही नीति अपना रही है कि पैसा देकर दो-चार विधायकों को इधर-उधर से इकट्ठा कर लो, मंत्री पद का लालच दे दो और काम पूरा हो गया. दरअसल, अब पार्टी विथ डिफरेंस पूरी तरह ख़त्म हो गई है. वेंकैया नायडू ने अपने बयान में यह दावा किया है कि कांग्रेस दलबदल की जननी है. तो अब सवाल यह उठता है और जैसा कि मैंने अपने ट्वीट में कहा था कि बेचारी भाजपा केवल कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रही है. दरअसल, उन्हें कहना यह चाहिए था कि अगर कांग्रेस टूट रही है, तो विधानसभा भंग होने दीजिए और नए सिरे से चुनाव होने दीजिए, हम सरकार नहीं बनाएंगे. वैसे मुझे अभी भी मालूम नहीं है कि उत्तराखंड में क्या होगा? लेकिन, इससे एक अच्छी बात यह निकल कर सामने आई कि भाजपा को अब यह एहसास हो गया है कि भारतीय चुनाव राष्ट्रपति शैली के चुनाव की तरह नहीं जीते जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने मोदी की छवि पर 2014 का आम चुनाव जीता था. अब यह मुमकिन नहीं है, जैसा कि दिल्ली और बिहार के चुनाव परिणामों से ज़ाहिर हो गया है तथा जैसा अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों के परिणाम ज़ाहिर करेंगे. देश में राजनीति वैसे ही चलनी चाहिए, जिस तरह संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, न उससे कम और न उससे अधिक. संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में कुछ दलगत सहमति बनी और इस आधार पर सदन में कुछ काम हुआ. बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जिसमें केवल वित्तीय विधेयक पारित होने हैं, कोई बड़ा विधेयक नहीं है. जीएसटी अब भी एक बड़ी समस्या है. अगर इस पर भी सहमति बनती है, तो बहुत अच्छा. वरना कुछ समय के लिए इसे ठंडे बस्ते में रख देने में कोई बुराई नहीं है.

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आदि पर बहुत चर्चा हो रही है और जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, अगर वैसा हुआ, तो वह एक ख़तरनाक स्थिति होगी. मुझे संदेह है कि भारत इसे दुरुस्त करने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है. दरअसल, हम केवल इस क्षेत्र में हो रहे अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके परिणाम साझा कर सकते हैं.

इसके अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी है. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आदि पर बहुत चर्चा हो रही है और जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, अगर वैसा हुआ, तो वह एक ख़तरनाक स्थिति होगी. मुझे संदेह है कि भारत इसे दुरुस्त करने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है. दरअसल, हम केवल इस क्षेत्र में हो रहे अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके परिणाम साझा कर सकते हैं. दिल्ली में आरके पचौरी की संस्था एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस संबंध में अच्छा काम कर रही है. आरके पचौरी ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी है. हमें आशा करनी चाहिए कि दूसरे लोग भी इस क्षेत्र में शोध करेंगे और उसके परिणाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

राष्ट्र निर्माण के लिए युवा आगे आएं

युवा क्रांति के ध्वज वाहक होते हैं, युवाओं का जोश समय की धारा बदल सकता है. भारत के युवा जाति और धर्म-पंथ के भेद नज़रअंदाज़ कर आतंकवाद, अशिक्षा, ग़रीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ें, तभी देश का विकास संभव है. यदि देश का युवा न जागा, तो भ्रष्ट नेता-अफसर देश को बेच खाएंगे.

–राज किशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

अफसपा की समीक्षा हो

स्टोरी-कब ख़त्म होगा रिहाई-गिरफ्तारी का सिलसिला (अंक 21-27 मार्च, 2016) पढ़कर मालूम हुआ कि एक महिला 15 वर्षों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग को लेकर अनशन पर है. जब यह स्टोरी पढ़ी, तो मैं काफी सोच में पड़ गया कि शर्मिला इरोम के संघर्ष के बारे में कितने लोग जानते होंगे? सरकार को शर्मिला की मांग पर विचार करना चाहिए और अफसपा की समीक्षा होनी चाहिए कि अब वास्तव में उसकी ज़रूरत है भी या नहीं?

–विनोद गुप्ता, *द्वारका, नई दिल्ली.*

किसानों की सुध कब लेगी सरकार

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. जब तोप मुक़ाबिल हो-माल्या की फरारी के लिए ज़िम्मेदार कौन (अंक 21-27 मार्च, 2016) पढ़ा. संतोष भारतीय जी ने बिल्कुल सही कहा कि सबने मिलकर विजय माल्या को देश से बाहर जाने में मदद की. एक उद्योगपति हज़ारों करोड़ रुपये लेकर विदेश भाग जाता है, सरकार कुछ नहीं करती. लेकिन, 25 हज़ार रुपये का कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर एक किसान आत्महत्या कर लेता है. अमीर और अमीर हो रहा है, ग़रीब की चिंता सरकार को है नहीं. हज़ारों करोड़ रुपये का घोटाला करके कुछ लोग पूंजीपति बन बैठे हैं, लेकिन ग़रीब किसान आत्महत्या कर रहा है.

–संजय पासवान, *बक्सर, बिहार.*

छात्र आंदोलन हुआ बेअसर

कवर स्टोरी-बस कमी है एक जेपी की (अंक 21-27 मार्च, 2016) ने काफी प्रभावित किया. एक आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए हुआ था और दूसरा 1975 में जेपी का आंदोलन, जिसमें छात्रों की अहम भूमिका थी और जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी. लेकिन, हाल में जो छात्र आंदोलन हुए, वे काफी फीके नज़र आए.

–विकास तिवारी, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

मुद्दों से मत भटकिए

स्तंभ-तय करिए, किस रास्ते जाएगा देश (अंक 21-27 मार्च, 2016) में कमल मोरारका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देश में अगर कृषि होगी, तो ग्रामीण क्षेत्र में सुधार होगा. कृषि पर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. हर आदमी रोहित वेमुला और कन्हैया पर बात-बहस कर रहा है, कोई भी विकास के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है.

–संतोष सिंह, *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

एक निवेदन

मैं आपकी चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. कृपया शिक्षा और नौकरी से संबंधित सूचनाएं-जानकारियां भी प्रकाशित करिए, जिससे छात्रों का भला हो.

–भुनेश्वर प्रसाद, *बलिया, उत्तर प्रदेश.*

नीतीश कुमार की नेपाल यात्रा

रिपोर्ट-नीतीश की नेपाल यात्रा से उम्मीदें (अंक 21-27 मार्च, 2016) पढ़ी. यह अच्छी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और गया से काठमांडू के बीच हवाई सेवा शुरू करने पर ज़ोर दिया. पहले भी पटना और काठमांडू के बीच नियमित हवाई सेवा उपलब्ध थी, जो क़रीब चार दशक पूर्व बंद कर दी गई, जबकि बिहार से नेपाल जाने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी-खासी है. नीतीश कुमार की सलाह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सूबे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय खिड़की खुलेगी.

–कमल सिन्हा, *मुंगेर, बिहार.*

खेल पर सियासत

रिपोर्ट-सियासत की भेंट चढ़ गया भारत-पाक मैच (अंक 21-27 मार्च, 2016) पढ़कर खासा दुःख हुआ कि खेल को खेल की भावना से न देखकर लोग अपनी रोटियां सेंकने लगते हैं. हिमाचल के धर्मशाला में होने वाले इस मैच को लेकर जितनी राजनीति की गई, उससे किसी को फ़ायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन सूबे के पर्यटन व्यवसाय को जबदस्त आर्थिक नुक़सान पहुंचा और हिमाचल की साख पर सवाल भी खड़ा हो गया.

–राजकुमार, *पालम कॉलोनी, नई दिल्ली.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

शब्दों को उनके वास्तविक महत्व से जानिए

> प्रश्न शब्दों का है. दबाव डालकर हर एक से भारत माता की जय बुलवाने की बात कहना एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है. दूसरा वर्ग है, जो यह कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे. यह बहुत छोटी और सतही राजनीतिक लड़ाई है. इस लड़ाई ने आज़ादी के आंदोलन के दो नारों को उनकी उस गरिमा से नीचे गिराने का काम किया है, जो उन्हें आज़ादी के आंदोलन में मिली थी. आज़ादी के आंदोलन में और भी नारे थे, इंकलाब–ज़िंदाबाद था, जयहिंद था, पर...

शब्दों की लड़ाई पहले भी होती थी, लेकिन जिस तरह आज शब्दों को लेकर लोगों का विश्वास, लोगों की समझ और लोगों का व्यक्तित्व तय किया जा रहा है, वैसा संभवत: पहले कभी नहीं हुआ. अंग्रेजों के जमाने में लड़ाई बहुत साफ़ थी. एक तरफ़ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ़ भारत के लोग थे और देश की ताकतों में से बहुत सारी ताकतें अंग्रेजों के पक्ष में थीं. वे अंग्रेजी हुक्मरानों के साथ मिलते–जुलते थे. वैसे ही शब्द, वैसा ही पहनावा अख्तियार करते थे, जो अंग्रेजों को पसंद था. दूसरी तरफ़ वे लोग थे, जो उनसे लड़ाई लड़ रहे थे. उनकी भाषा, उनका पहनावा और उनके प्रतीक देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सिपाहियों से मिलते–जुलते थे. अपने आप लोग यह तय करते थे कि वे अंग्रेजों के पक्ष में हैं या हिंदुस्तानियों के. मसलन, जब विदेशी कपड़ों की होली जली, तब बहुत सारे लोगों ने चौराहे पर जाकर विदेशी वस्त्रों की होली नहीं जलाई, बल्कि अपने मोहल्ले में ही आग जलाकर, विदेशी रूमाल जलाकर अपना समर्थन आज़ादी के आंदोलन को दिया.

आज़ादी के आंदोलन में जिन नारों का इस्तेमाल होता था, उनमें सबसे प्रमुख वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा था. और, तीसरा उस समय राष्ट्रगान बन चुका था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. अंग्रेजों के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई में बहुतों ने विद्रोह किया, जिनमें साधु–संन्यासी भी शामिल थे, जिस पर बंकिम चंद ने आनंद मठ लिखा. उन साधु– संन्यासियों के अंग्रेजों के प्रति विद्रोह और आज़ादी के आंदोलन को समर्थन का सबसे प्रमुख नारा वंदे मातरम था. सामान्य तौर पर पूरे हिंदुस्तान में भारत माता की जय अंग्रेजों से लड़ने का सबसे शक्तिशाली नारा था. बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता की तस्वीर और भारत का नक्शा, यह चित्र सारे देश में प्रचलित था तथा उसे आज़ाद कराने की कसम बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो आज़ादी के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे, खा रहे थे. ये दो पवित्र नारे हमारी आज़ादी की विरासत की धरोहर हैं.

लेकिन, आज 2016 में आज़ादी के ये दो नारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक के तौर पर सामने आ गए हैं. जो लोग इस बारीकी को नहीं समझते हैं, उन्होंने भी यह स्थिति लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है. 70 के दशक में कम्युनिस्टों या वामपंथी विचारधारा से लड़ने के लिए तत्कालीन जनसंघ से जुड़े संगठनों ने एक नारा ईजाद किया था, लाल गुलामी छोड़कर, बोलो वंदे मातरम. आज अपनी विचारधारा को राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबोकर भारत माता की जय सारे देश में गूंज रहा है. और, विचारधारा विशेष यह प्रचारित कर रही है कि अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं, तो आप उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो जाते हैं, जैसे आपने एक समय मिस्डकॉल देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन गए थे. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि दुनिया में

> हम यह साफ़ तौर पर मानते हैं कि देश के समझदार लोगों को खड़े होकर आज़ादी के आंदोलन का पर्याय रहे शब्दों की इज्जत और महत्व उन सबको समझाना और बताना चाहिए, जो इनसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल, वे कभी राष्ट्रभक्त तो हो ही नहीं सकते. यहां पर भारत सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है. भारत सरकार आज़ादी के आंदोलन का इतिहास कभी पूरे तौर पर देश की जनता के सामने ला ही नहीं पाई.

सबसे अधिक सदस्य संख्या वाली पार्टी भाजपा है, जिसके 11 करोड़ सदस्य हैं. हालांकि, 11 करोड़ सदस्य बनने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बुरी तरह दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, बिहार में चुनाव हार चुकी है और अब उसके सामने असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश हैं. देखना है, सबसे बड़ी पार्टी यहां पर क्या कमाल दिखाती है.

लेकिन, प्रश्न शब्दों का है. दबाव डालकर हर एक से भारत माता की जय बुलवाने की बात कहना एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है. दूसरा वर्ग है, जो यह कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे. यह बहुत छोटी और सतही राजनीतिक लड़ाई है. इस लड़ाई ने आज़ादी के आंदोलन के दो नारों को उनकी उस गरिमा से नीचे गिराने का काम किया है, जो उन्हें आज़ादी के आंदोलन में मिली थी. आज़ादी के आंदोलन में और भी नारे थे, इंकलाब– ज़िंदाबाद था, जयहिंद था, पर अचानक राष्ट्रप्रेम और देशप्रेम का पर्याय ये दो नारे बना दिए गए हैं. यहीं भारत की आज़ादी के आंदोलन का महत्व ख़त्म करने की गंध आ रही है. आज़ादी के आंदोलन में क्या हम उन वर्गों का योगदान नकारना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज़ादी आई या हम उन सारे शब्दों को भोथरा करना चाहते हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के पर्याय बन गए थे. सिर्फ़ एक शब्द को राष्ट्रप्रेम से जोड़ना और जो उसे न बोले, दूसरा शब्द बोले, वह राष्ट्रद्रोही! यह मानसिकता देश की अक्षुण्ण एकता को तोड़ने की बहुत ही घटिया कोशिश है.

हम यह साफ़ तौर पर मानते हैं कि देश के समझदार लोगों को खड़े होकर आज़ादी के आंदोलन का पर्याय रहे शब्दों की इज्जत और महत्व उन सबको समझाना और बताना चाहिए, जो इनसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल, वे कभी राष्ट्रभक्त तो हो ही नहीं सकते. यहां पर भारत सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है. भारत सरकार आज़ादी के आंदोलन का इतिहास कभी पूरे तौर पर देश की जनता के सामने ला ही नहीं पाई. आज़ादी का आंदोलन या आज़ादी के बाद समस्याओं के विरुद्ध चले विभिन्न संघर्ष और आंदोलन भारत के विकास की सीढ़ियां हैं, जिनसे गुज़र कर आज भारत वहां पहुंचा है, जहां उसके सामने निराशा भी है और आशा भी.

इसलिए हमारा अनुरोध है कि हमें शब्दों को उनके उसी महत्व से जानना चाहिए, जिस संदर्भ में उनका इस्तेमाल होता है. भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब–ज़िंदाबाद और जयहिंद, ये ऐसे शब्द हैं, जो बराबर महत्व के हैं और जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने में अद्भुत सहयोग किया. अगर आज इन शब्दों की पुनर्प्रतिष्ठा में देश असफल रहता है, तो यह मानना चाहिए कि हम न अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञ हैं, न आज़ादी के लिए लड़ने वालों के प्रति कृतज्ञ हैं और न आज़ादी के प्रति कृतज्ञ हैं. बल्कि, हम एक नकली सोच का गुब्बारा देखकर यह मान बैठे हैं कि सच्चाई यही है. जबकि सच्चाई कुछ और है, जिसे तलाशने वाले आज खामोश बैठे हैं. देखते हैं, यह खामोशी कब तक कायम रहती है. ■

editor@chauthiduniya.com

क्रोनी समाजवाद सुरक्षित है

मेघनाद देसाई

ब्राजील के पूर्व समाजवादी राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भ्रष्टाचार के एक मामले में फंसे हुए हैं. उनके बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाली डिल्मा राउसेफ को संसद में महाभियोग का सामना करना है. मामला ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी राष्ट्रीयकृत पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोब्रास के नियंत्रण का है. यह मंत्रालय लूला के कार्यकाल में राउसेफ के पास था. राउसेफ पर आरोप है कि उन्होंने पेट्रोब्रास के अधिकारियों को कंपनी से दो बिलियन डॉलर निकालने की अनुमति दी और उन पर कार्रवाई नहीं होने दी. लूला को जांच के दायरे से बाहर रखने के लिए राउसेफ ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था. लाखों लोगों ने इसके विरोध में मार्च निकाला. अब अदालत ने यह फ़ैसला दिया है कि लूला की नियुक्ति अवैध थी. ब्राजील के व्यापार जगत में खुशी है कि राउसेफ की छुट्टी हो सकती है और अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सकती है.

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एक बड़ी धनराशि एनपीए (गैर निष्पादित ऋण) की श्रेणी में आ गई है. विजय माल्या (कई अन्य कर्जदारों समेत) 7,000 करोड़ रुपये के अपने बकाया ऋण के कारण सुर्खियों में हैं. हालांकि, मुद्दा उक्त बैंकों के अधिकारियों का आचरण होना चाहिए, जिन्होंने ऋण मंज़ूर करते समय यह जांच नहीं की कि माल्या से जो सिक्योरिटी ली गई है, वह उनकी है या नहीं. ऐसा लगता है कि किसी ने भी उन डमी कंपनियों की जांच करने की कोशिश नहीं की, जो माल्या ने अपने ऋणों का भुगतान अपनी जेब से न करने के लिए खुल–वाई थीं. उधर एयर इंडिया को 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई करदाताओं की जेब से होनी है. हालांकि, देश के अधिकतर करदाताओं के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपने लिए पॉकेट वाले कोट–पैंट बनवा सकें. दरअसल, भारत में भ्रष्टाचार का एक लंबा इतिहास रहा है. इस भ्रष्टाचार में राष्ट्रीयकृत कंपनियों का भरपूर सहयोग रहा है. फिरोज गांधी ने क्रोनी सोशलिज्म की यह बीमारी 1950 के दशक में ही उज़ागर कर दी थी, जब एलआईसी के साथ मुंधरा का सौदा हुआ था. अभी भी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की निजी क्षेत्र पर नैतिक श्रेष्ठता बरकरार है, जबकि सच्चाई यह है कि इसके द्वारा लंबे समय से करदाताओं का पैसा सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के दोस्तों की जेब में जा रहा है.

> माल्या प्रकरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आख़िरी मामला होना चाहिए, जो एनडीए सरकार को प्रेरित करे कि वह बैंकों का प्रबंधन अनुशासित करे. बैंकों को एकीकृत करके फिर से उनका निजीकरण हो. इसके बाद बैंक अपनी अक्षमता के चलते कम से कम ग़रीब किसानों–मज़दूरों पर बोझ तो नहीं डालेंगे. लेकिन अफ़सोस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा! अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करदाताओं का पैसा बर्बाद करने के लिए दंडित करने की बात की जाती है, तो वामपंथी उनकी अक्षमता के बचाव में मोर्चा खोल देंगे.

इंदिरा गांधी द्वारा भारत के बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फ़ैसला राजनीतिक था. यह बात इंदिरा गांधी ने आईजी पटेल को बताई थी, जिन्होंने इस बिल का मसौदा तैयार करने में मदद की थी. ज़ाहिर है कि बहाना ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार को बनाया गया था. लेकिन जैसा कि हालिया घटनाएं ज़ाहिर करती हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नई सदी के दूसरे दशक तक भी वित्तीय सेवाओं को समावेशी बनाने में असफल रहे हैं यानी राष्ट्रीयकरण के 40 वर्षों बाद भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है. दरअसल, बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बनाने का असल उद्देश्य राजनीतिक दलों, मुख्य रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को ऋण दिलाने के लिए था. ये ऐसे ऋण थे, जिनके चुकाए जाने की संभावनाएं बहुत कम थीं. ये ऋण बैंकों के क्लासिक एनपीए थे. यह बात आज से 10 वर्ष पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रिटायर्ड चेयरमैन ने मुझे बताई थी.

माल्या प्रकरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आख़िरी मामला होना चाहिए, जो एनडीए सरकार को प्रेरित करे कि वह बैंकों का प्रबंधन अनुशासित करे. बैंकों को एकीकृत करके फिर से उनका निजीकरण हो. इसके बाद बैंक अपनी अक्षमता के चलते कम से कम ग़रीब किसानों–मज़दूरों पर बोझ तो नहीं डालेंगे. लेकिन अफ़सोस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा! अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करदाताओं का पैसा बर्बाद करने के लिए दंडित करने की बात की जाती है, तो वामपंथी उनकी अक्षमता के बचाव में मोर्चा खोल देंगे. दरअसल, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे, क्रोनी समाजवाद सुरक्षित रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

The Most Cost Effective Builder in India

4 से 50 लाख तक में घर

Customer Care : 080 10 222222

www.vastuvihar.org

मोदी-नीतीश को साथ लाएगा विकास गठबंधन

सरोज सिंह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले कई वर्षों से विपरीत ध्रुवों पर रही है. कई बार तो हालात इस कदर कटु हो गए कि दोनों ही शिष्ट राजनीति क्या सामान्य शिष्टाचार की सीमा भी लांघ गए. लेकिन प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा के दौरान पुराने जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था. जून 2013 में एनडीए से अलग होने और महा-गठबंधन की जीत के बाद नीतीश कुमार सरकार के कामकाज के भाजपा और उसके सहयोगी दल कटु आलोचक ही नहीं रहे हैं बल्कि इसे जंगलराज-2 की संज्ञा भी देते रहे हैं. दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी केंद्र की मोदी सरकार की बिहार नीति को सूबे के प्रति उसका सौतेला व्यवहार मानते रहे हैं. वह बिहार के लिए घोषित पैकेज के संबंध में केंद्र की निष्ठा पर बराबर सवाल उठाते रहे हैं और इस घोषणा को छलावा साबित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते. उन्होंने हाल ही में वर्ष 2016-17 के लिए पेश आम और रेल बजट में बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया था. लेकिन छौकिया की सभा में उन्होंने इन मसलों की कोई चर्चा नहीं की. यहां तक कि लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने संबोधन में जिक्र नहीं किया. इसके बाद नीतीश के इस सद्भाव का प्रत्युत्तर नरेन्द्र मोदी ने अपने लिहाज से दिया. उन्होंने बिहार के विकास के लिए हर संभव सहायता देने का वादा किया और गांवों में बिजली पहुंचाने के बिहार सरकार के काम की सराहना करते हुए कहा कि गांवों तक बिजली पहुंचाने के काम में नीतीश कुमार की सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है. केंद्र और राज्य तय कर लें तो अगले दो साल में सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव बिहार को ही मिलेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लगभग दो साल के कार्यकाल में बिहार का विकास उनकी प्राथमिकता में रहा है. पूर्वी भारत के विकास के बगैर भारत का विकास असंभव है और बिहार की तरक्की के बगैर पूर्वी भारत का आगे बढ़ना नामुमकिन. कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही हेलीकॉप्टर से छौकिया पहुंचे थे. इसके बाद दोनों मंच पर अगल-बगल बैठे और लगातार बातचीत करते रहे. ऐसे में दोनों के बीच बढ़ती करीबी को लेकर सवाल उठने लाजिमी हैं, कि क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अनायास ही सम्मान दे रहे हैं?

बिहार की राजनीति के दोनों धुरे मोदी-नीतीश के बीच की करीबी का जवाब खोज रहे हैं. छौकिया के आयोजन के ठीक अगले दिन गंडक नदी पर गोपालगंज-बेतिया को जोड़नेवाले नए सेतु के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार ने राजनीतिक दलों को याद दिलाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए वह लंबे अर्से से लड़ रहे हैं. मनमोहन सिंह की सरकार पर उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन सफलता नहीं मिली. यदि राज्य के सभी दल इस आंदोलन में शामिल होंगे तो यह मांग पूरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद संसद में यह मसला उठाएं. उन्होंने इस तरह की और भी बातें की पर केंद्र के प्रति उनका सुर नरम ही रहा. भाजपा के सुर भी नीतीश कुमार को लेकर नर्म हो रहे हैं. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जैसे अनेक नेताओं द्वारा दिए गए बयान इस बात की तसदीक करते हैं. ये सभी नेता नीतीश के बारे में सकारात्मक बयान दे रहे हैं. ऐसा ही कुछ बदलाव जदयू के नेताओं के वक्तव्यों में भी दिखाई पड़ रहा है. प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जदयू नेता के सी त्यागी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जब बतौर प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो ज्यादा ईमानदार होते हैं.

इस स्थिति पर महा-गठबंधन के अन्य दोनों दल राजद और कांग्रेस खामोश हैं. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री की यात्रा को विफल बताया, क्योंकि उनकी इस यात्रा से बिहार को कुछ नहीं मिला. राजद सुप्रीमो फिलहाल मौन हैं. कांग्रेस की ओर से भी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है. लेकिन कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने इतना ही कहा कि इतने दिनों तक सरकार चलाने के बावजूद नरेन्द्र मोदी नकारात्मकता से पीड़ित ही रहे. महा-गठबंधन के इन दोनों दलों में जदयू के प्रति संशय का माहौल है. दोनों ही दल स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझ रहे हैं. खामोशी तो एनडीए में भी है, हर कोई हवा का रुख भांपने में लगा है. रामविलास पासवान चकित हैं कि हाजीपुर में मंच पर उनकी मौजूदगी के बावजूद नीतीश कुमार को इतनी तरजीह आखिर कैसे और क्यों मिल गई! पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को भी नीतीश कुमार को इतना मान दिया जाना रास नहीं आएगा. इस नए राजनीतिक माहौल के साइड-इफेक्ट दिखने लगे हैं. अब तक खामोश रहे राजद और कांग्रेस के विधायक विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करने लगे हैं. बिहार की राजनीति के इस नए अध्याय का उपसंहार कब और किस तरह लिखा जाएगा फिलहाल यह कहना कठिन है. कुछ लोग इसे तात्कालिक शिष्टाचार बता रहे हैं, तो कुछ इसके अगले डेढ़-दो साल तक चलने की उम्मीद जता रहे हैं. सबका मानना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब आते-आते हिन्दी पट्टी की भावी राजनीति साफ हो जाएगी. इसके साथ-साथ मोदी-नीतीश के बीच के रिश्ते का आधार भी साफ हो जाएगा. हालांकि, हाजीपुर का यह राजनीतिक नवाचार बिहार के सत्तारूढ़ महा-गठबंधन के लिए गांठ तो बन रहा है और लोगों को भी साफ-साफ नजर आने लगा है. अब देखना है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस गांठ को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाते हैं जिससे महा-गठबंधन सरकार में शामिल दलों के बीच बढ़ रही दूरियों का आभास जनता को न हो.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधानसभा में लगातार हो रहा हंगामा

कैसे बचेगी साख

सरोज सिंह

ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ जाएगा. होली के अवकाश के पहले की कार्यवाही तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है. बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सबको उम्मीद थी कि इस बार बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सूबे के गंभीर विषयों पर गहन बहस होगी और बहुत सारी समस्याओं का हल निकलेगा. लेकिन हुआ ठीक इसके उलट. कभी शहाबुद्दीन के नाम पर, तो कभी देख लेने वाली भाषा के नाम पर, तो कभी कीमती उपहार के नाम पर सदन की कार्यवाही बाधित होती रही. और इस हंगामे के बीच सूबे के असली मसले कहीं पीछे छूट गए. विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करना तो अब आम बात हो गई है. इसका असर यह हो रहा है कि विधानसभा से सरोकार रखने वाले लोग विधानसभा के सत्र को बहुत ही हल्के में लेने लगे हैं. ऐसे में लोगों की यह राय बनती जा रही है कि विधानसभा में हंगामे और बहिष्कार के अलावा और कुछ नहीं हुआ होगा.

आम जनता के बीच बन रही इस तरह की धारणा से ऐसा नहीं है कि माननीय सदस्य चिंतित नहीं हैं लेकिन दलीय बंधन और कुछ न करने की प्रवृत्ति ने हालात को अब बेहद सोचनीय बना दिया है. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सदन में हो रहे इस तरह के हंगामे पर कहते हैं कि सच में ऐसा कतई अच्छा नहीं लगता. हमने शुरू में ही विधायकों से अपील की थी कि वे सदन के अंदर संयमित रहें और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलने दें. लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है. सदन के अंदर बेवजह हंगामा हो रहा है. सदस्य वेल में आ रहे हैं और सदन का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है. हमारी कोशिश है कि सदन शांति से चले और अधिक से अधिक जनहित के मुद्दे उठें, लेकिन सर्फ राजनीतिक कारणों से हंगामा करना उचित नहीं है. विपक्ष को लगता है की हंगामा करके वह सरकार को घेर सकता है लेकिन हकीकत में यह तो सरकार को बचने का अवसर देना है. चौधरी कहते हैं कि हंगामा करके सरकार को नहीं घेरा जा सकता. सरकार तभी आपके घेरे में आएगी जब सदन में चर्चा हो, बहस हो. हम विपक्ष के पक्ष में हैं यदि वह सदन चलाने में सहयोग करे तो हम नियमों में ढील देकर भी उन्हें उनकी बात रखने का अवसर देंगे. लेकिन वह हंगामा करेंगे, वेल में आएंगे तो सरकार कैसे घिरेगी. मैं तो आज भी कह रहा हूं विपक्ष सदन में चर्चा करे सरकार को घेरे, विधानसभा अध्यक्ष उनके साथ रहेगा.

विधानसभा में लगातार हो रहे हंगामे पर संसदीय कार्यमंत्री की राय अलग है. उनका आरोप है कि जब विपक्ष की सदन चलाने में दिलचस्पी ही नहीं है तो सदन चलेगा कैसे. श्रवण कुमार कहते हैं कि बगैर किसी मुद्दे के वे सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं यह उचित नहीं है. जनता के बीच इसका गलत संदेश जा रहा है. वे सदन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं. इनके लिए नियम-कानून कोई मायने नहीं रखते. सदन की अपनी नियमावली है और इसमे तमाम पहलुओं की पूरी चर्चा की गई है. सब कुछ जानकर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है. इसके कारण प्रश्नकाल बाधित हो रहा है जिसमें जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं. जनहित के सवाल पर सरकार को जवाब देना होता है लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है. गंभीर से गंभीर विषयों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है. मंत्री तैयारी करके आते हैं लेकिन सवाल ही नहीं हो रहे हैं. सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरु होती है विपक्षी सदस्य वेल में आकर हंगामा करते हैं. लेकिन विपक्ष के नेता की राय है कि सरकार जनता के मुद्दे पर बहस ही नहीं कराना चाहती है. सरकार की दिलचस्पी सदन चलाने में नहीं दिखती इसलिए तो वह जनहित के मुद्दों पर बहस से भागती है. हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है. हम जो सवाल उठाते हैं उसका जवाब नहीं मिलता. विरोध करो तो कहते हैं कि हंगामा कर रहे हैं. हमने नीतीश निश्चय पर जितने सवाल किए, उनमें से किसी एक का जवाब मिला क्या? फिर विपक्ष का क्या मतलब रह जाता है. हम सरकार के प्रवचन सुनने आए हैं या उसकी कमियां उजागर करने. अपराध, कानून-व्यवस्था, धान खरीद जैसे विषयों पर सरकार भाग रही है. मामले को दूसरा रूप देने के लिए सत्तधारी विधायक गाली-गलौज पर उतर आए हैं. सदन में जिस भाषा का वे प्रयोग कर रहे हैं उससे हैरत होती है. चर्चा विभागीय बजट पर होती है और सत्ताधारी दल के विधायक प्रधानमंत्री के कान पकड़ने की बात करते हैं. फिलहाल बजट सत्र का होली में अवकाश हो चुका है. उम्मीद की जानी चाहिए कि होली के बाद जब सदन चलेगा तो स्थितियां बदलेंगी और होली के पहले जैसी नौबत नहीं आएगी. चूंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों की है इसलिए आशा की जानी चाहिए कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्य होली के बाद संयम बरतेंगे और जनता के मुद्दों पर सदन में गंभीर बहस करेंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

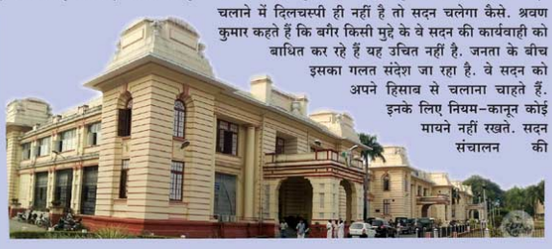

नीतीश कुमार के प्रयास भी बेकार

नीतीश कुमार जब बिहार विधान परिषद की आचार समिति के प्रमुख थे तब उन्होंने माननीयों के आचार व्यवहार तय करने के लिए कुछ प्रमुख अनुशंसाएं की थीं, मौजूदा हालात में इनका कोई मतलब नहीं रह गया है.

- प्रश्नकाल बाधित न करें.
- कोई सदस्य बोल रहा हो तो बाधा न डालें.
- बिना प्रमाण के आरोप न लगाएं.
- सदन में बिल्ला न लगाएं, न दिखाएं, झंडा-बैनर-पोस्टर या अन्य प्रदर्शन सामग्री लेकर सदन में न आएं.
- इशारों में व्यंग्य न करें, धमकी न दें.
- माइक न तोड़ें, वेल में नहीं आएं, दस्तावेज़ों को न फाड़ें.
- भाषण देने के तुरंत बाद सदन से बाहर न जाएं.
- सदन में मोबाइल,कैसेट, टेप रिकॉर्डर लेकर न आएं.
- सभापति के आसन के पास न जाएं. सभापति आसन पर खड़े हों तो कोई अन्य सदस्य खड़ा न रहे.
- सदन में सूचना के तहत उठाए जाने वाले किसी भी विषय को सभापति द्वारा स्वीकृत किए जाने के पूर्व मीडिया के माध्यम से प्रचारित न करें.
- प्रमाण के तौर पर रखे जाने वाले दस्तावेज या पत्र के बारे में सभापति से पूर्व अनुमति लें.
- अदालत में विचाराधीन मसलों को न उठाएं.

CRM
TMT BAR

ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178

भूकम्प रोधी
जंग रोधी

Fe-500

मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश

Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

चंपारण सत्याग्रह

शताब्दी वर्ष पर याद आए गांधी

राकेश कुमार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों के लिए केवल ब्रांड एंबेसडर बनकर रह गए हैं. गांधी, गांधीवाद और उनके आदर्शों की चर्चा के बगैर किसी नेता या पार्टी का एजेंडा पूरा नहीं होता. लेकिन विडंबना है कि राष्ट्रीय त्यौहारों, भाषणों, उनके जन्मदिवस-पुण्यतिथि के अलावा बापू किसी को याद नहीं आते. लेकिन एक बार फिर देश के नेताओं को बापू की याद आने लगी है, इसका कारण भी महत्वपूर्ण है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता. मौका है चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का. बिहार के चंपारण में ही गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था. यह भारत में गांधीजी के नेतृत्व में हुआ पहला आंदोलन था. 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए 15 अप्रैल 1917 चंपारण पहुंचे थे. चंपारण में उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों (निलहों) पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया. उस दौरान अंग्रेजों ने यहां नील की खेती के लिए तीन कठिया प्रणाली लागू की थी. किसानों को अपनी खेती के बीस कट्ठे में से तीन कट्ठे में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी.

दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित 31 वें कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल कई कांग्रेसी नेताओं से मिले. उन्होंने सभी बड़े नेताओं को चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों-मज़दूरों की बदहाली और नील कंपनियों की दलाली के बारे में अवगत कराया. राजकुमार शुक्ल स्वयं एक जमींदार थे और उनके मुख से किसानों मज़दूरों की बदहाली का विवरण ने गांधीजी को प्रभावित किया था. अंततः जब शुक्ल जी ने पिपरा और तुरकौलिया में किसानों-मज़दूरों द्वारा किए गए अहिंसक असहयोग के बारे में बताया तो महात्मा गांधी तत्काल चंपारण चलने के लिए राजी हो गए.

शताब्दी समारोह की तैयारी में केंद्र और राज्य सरकार जुटी हुई है. सरकारी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विगत दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है. दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी सत्याग्रह शताब्दी वर्ष से संबंधित कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार करने में जुटी है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंपारण आगमन की संभावना भी जताई जा रही है. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है. लेकिन इन सभी आयोजनों को मौसमी ही कहा जाएगा. सरकार को गांधी जी की कितनी याद है और तथाकथित गांधीवादी नेताओं में बापू को लेकर कितनी संवेदना है इसका सहज अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई दशकों बाद भी आज तक गांधी सर्किट का निर्माण नहीं हो सका है. इतना ही नहीं, चंपारण गांधी की कर्मभूमि के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है लेकिन आज तक बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा जारी दर्शनीय और पौराणिक स्थलों की सूची में भी चंपारण का नाम नहीं है जहां गांधी संग्रहालय और सत्य स्तंभ स्थित है. दूसरे शब्दों में कहें तो चंपारण को एक नीति के तहत उपेक्षित रखा गया है. इस संदर्भ में गांधी स्मारक समिति के पूर्व सचिव व वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडेय ने बताया कि मोतिहारी के गांधी स्मारक को पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए उन्होंने तीन बार व्यक्तिगत तौर पर पर्यटन विकास विभाग को आवेदन दिया और पूर्ण जानकारी दी थी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो सका. यहां तक कि गांधी जी के प्रथम बुनियादी विद्यालय भितिहरवा आश्रम और लखनसेन को भी दर्शनीय स्थलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है.

नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति देखने के लिए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे गांधी जी 16 अप्रैल को जसौली पट्टी गांव के लिए रवाना हुए. जब वह चन्द्रहिया पहुंचे थे तब उन्हें जिलाधिकारी डब्ल्यू बी हेकॉक का फरमान मिला कि पहली गाड़ी से वह जिला छोड़कर चले जाएं. गांधी जी वापस लौट आए और आदेश की अवहेलना करने की सूचना पत्र द्वारा जिलाधिकारी हेकॉक को दी. 18 अप्रैल को गांधीजी मोतिहारी के अनुमंडल पदाधिकारी की अदालत में उपस्थित हुए और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का कारण बताते हुए ऐतिहासिक वक्तव्य दिया. उसी स्थल पर आज गांधी स्तंभ बनाया गया है. बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री केदार पांडेय इस गांधी स्मारक स्तंभ के प्रथम अध्यक्ष थे. पूरे भारत में ऐसा स्तंभ केवल दो जगहों पर है. पहला मोतिहारी में और दूसरा कर्नाटक के बेलगाम में. चुनार के बलुआ पत्थर से बना यह स्तंभ 48 फीट ऊंचा है. जब गांधी जी चंपारण आए थे उस वक्त उनकी उम्र 48 वर्ष थी. यह उसे दर्शाता है. मोतिहारी के अलावा भारतवर्ष में अन्य छह जगहों पर मुंबई, पटना, मद्रास, कर्नाटक, दिल्ली, साबरमती में गांधी स्मारक है. समय के साथ गांधीवादियों की भी तीन श्रेणियां हो गई हैं. पहली, सरकारी संस्थान व सरकारी लोग जहां से होकर ही गांधीवाद और गांधी से जुड़े स्थलों के विकास का मार्ग गुजरता है. यह महकमा अपने काम के प्रति कितना समर्पित और संवेदनशील है इस बात का सहज तरीके से अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दशकों बाद भी गांधी सर्किट का निर्माण नहीं हो सका है. गांधीवादियों का दूसरा वर्ग गांधी आश्रमों के मठाधीशों का है जहां गांधीवादी विचारों को ध्वस्त होते देखा जा सकता है. अब तो ऐसे आश्रमों को वंशानुगत आधार पर संचालित किया जा रहा है. तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो बिना किसी सरकारी सहयोग से अपने बलबूते पर गांधी के विचारों का प्रचार-प्रसार करने में लगे हैं. सरकारें भी अपने हिसाब से ही गांधी को विचारों को आगे बढाती हैं. किसी सरकार ने स्वराज का नारा दिया तो किसी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति को आगे बढ़ाने की बात कहीं. कभी स्वछता तो कभी साक्षरता के नारे लगाए गए. सभी ने अपने-अपने तरीके से अपने हक में गांधी के विचारों को अपनाया. अपने जीवन पर सत्य का प्रयोग करने वाले गांधी जी के सत्य के सिद्धांत को ही भुला दिया गया. बहरहाल चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर एक बार फिर गांधी की सुध सरकारों को आई है, देखते हैं कि सरकारें गांधीजी के सिद्धान्तों को कितना आत्मसात कर पाती हैं और कितनी दूर तक उन्हें लेकर चल पाती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

गया

माओवादियों के ख़िलाफ़ खड़े हुए पर अब शुरू कर दी लेवी वसूली

चौथी दुनिया ब्यूरो

नक्सलियों के खिलाफ खड़े हुए संगठन रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेंटर ने भी अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है. पिछले एक दशक से गया जिले का नक्सल प्रभावित क्षेत्र शेरघाटी अनुमंडल में सक्रिय आरसीसी अब मगध प्रमंडल के अन्य क्षेत्रों में भी अपने संगठन को विस्तारित और मजबूत करने में जुट गया है. अपने गठन के शुरूआती दिनों में आरसीसी ने नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का ऐलान किया था. इस वजह से आरसीसी को आम लोगों के साथ-साथ पुलिस महकमे का भी संरक्षण मिलना शुरू हुआ था. इसका प्रतिफल यह हुआ कि बहुत सारे नक्सली पकड़े गए और कई मुठभेड़ में मारे गए. शुरूआती दिनों में नक्सलियों के पकड़े जाने या मुठभेड़ में मारे जाने के बाद गया जिले में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा(माओवादी) के साथ-साथ उसके सहयोगी संगठनों में भी खलबली मच गई. माओवादियों ने इस मामले पर गुप्त बैठक कर विचार-विमर्श करने के बाद अपने शीर्ष नेतृत्व को सूचना दी कि नक्सलियों के पकड़े या मारे जाने में आरसीसी प्रमुख विनोद मरांडी तथा उनके सहयोगियों का हाथ है. इसके बाद से ही भाकपा(माओवादी) ने अपने निशाने पर आरसीसी व इसके प्रमुख विनोद मरांडी को ले लिया. इसके बाद से आरसीसी एवं माओवादियों के बीच कई संघर्ष हुए. जिसमें दोनों ओर से लोगों को काफी क्षति उठानी पड़ी. इस दौरान आरसीसी प्रमुख विनोद मरांडी को अपरोक्ष रूप से पुलिस का संरक्षण मिलने की बात कही जाती रही. लेकिन बाद के वर्षों में आरसीसी ने अपनी धाक जमाने तथा लोगों में दहशत पैदा करने के लिए कुछ ऐसी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे पुलिस के सामने कानून व्यवस्था कायम रखने में परेशानी उत्पन्न होने लगी. तब पुलिस तथा प्रशासन ने आरसीसी को ही प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया.

वहीं दूसरी ओर आरसीसी प्रमुख विनोद मरांडी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए वह सब काम शुरू कर दिए जो कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा(माओवादी) की ओर से किए जाते हैं. आरसीसी ने भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ठेकेदारों से लेवी वसूलने, विकास कार्यों में हिस्सेदारी तथा सरकारी कर्मियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया. आरसीसी के कार्यकलापों से पुलिस प्रशासन के लोग जब परेशान हो गए तो पुलिस की ओर से भी आरसीसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई. जिसमें दर्जनों आरसीसी के हार्डकोर पकड़े गए. लेकिन इसके प्रमुख विनोद मरांडी को नहीं पकड़ा जा सका. विनोद मरांडी गया जिले के गुरारू थाना क्षेत्र के डिहा गांव का निवासी है. विनोद पहले भाकपा (माओवादी) का सब-जोनल कमांडर हुआ करता था. किसी बात को लेकर अपने संगठन में विनोद का विवाद हो गया. जिसके कारण वह अपने एक अन्य सहयोगी विकास यादव के साथ भाकपा(माओवादी) से अलग हो गया. अलग होने के कुछ दिनों बाद ही इन दोनों ने मिलकर रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेंटर (आरसीसी)का गठन किया और नक्सलियों से मिलते-जुलते एजेंडे पर काम करना शुरू किया. माओवादियों से अलग होने के कारण ही पुलिस ने इसे अपना गुप्तचर बना लिया. इसके कारण माओवादियों ने 6-7 साल पहले विनोद मरांडी के डिहा स्थित घर को डायनामाइट से उड़ा दिया. इस घटना के बाद से आरसीसी तथा भाकपा माओवादियों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर संघर्ष तेज हो गया. लोगों का आरोप यह था कि आरसीसी प्रमुख विनोद को एक जाति विशेष के लोगों का खुला समर्थन प्राप्त है.

23 फरवरी 2016 को गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र से उत्तम नामक एक युवक की गिरफ्तारी हुई, जो गया शहर में रहकर आरसीसी की गतिविधियों को संचालित करता था. उसकी निशानदेही पर गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो आरसीसी के हार्डकोर थे. पिछले महीने गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल में आरसीसी की ओर से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मध्यान भोजन प्रभारी, विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों तथा अन्य लोगों से खुलेआम लेवी की मांग की जा रही थी. एक तरह से इस संगठन ने पुलिस को खुली चुनौती दे रखी थी. गिरफ्तार किए लोगों में उत्तम कुमार बड़की निवासी करासन इमामगंज, मंटू सिंह पथरा निवासी इमामगंज, राकेश कुमार घोड़ाघा डोभी, बबलू उर्फ अमीत रहमानी निवासी नारायणपुर, इमामगंज के अलावा झारखंड के प्रतापपुर के रहने वाले अशोक महता चन्द्री और जोरी निवासी संदीप पासवान शामिल हैं. इन सभी ने मिलकर अपने आधार क्षेत्र में शिक्षा विभाग और ठेकेदारों को टारगेट कर रखा था. आरसीसी की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेवी के लिए धमकी दी जा रही थी. आरसीसी की योजना में गुरूआ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जान से मारने की योजना बनाई जा चुकी थी. इसके अलावा कई ठेकेदार भी आरसीसी के निशाने पर थे. जिले में संचालित राईस मील, ईंट-भट्टा मालिकों तथा कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भी लेवी के लिए निशाने पर रखा गया था. उक्त बातों को बताते हुए आरसीसी के गिरफ्तार सदस्यों ने बताया कि ये लोग कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. आरसीसी अपने पांव पसारकर अपने आधार क्षेत्र का विस्तार मगध प्रमंडल के सभी जिलो में करने के साथ-साथ झारखंड के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता रहा है. लेकिन इसी बीच आधा दर्जन आरसीसी सदस्यों को पकड़े जाने के बाद से आरसीसी कुछ कमजोर हो गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलबर्गा:9343834519

शाहजहांपुर के गांधी आदर्श कुष्ठ आश्रम को नष्ट कर रहा भ्रष्टाचार का कोढ़

भू-माफ़ियाओं ने कुष्ठ रोगियों को खदेड़ भगाया

ज़रीफ़ मलिक आबन्द

शाहजहांपुर में एक वक्त वह भी था जब उसके पास अपना कारखाना था जिसमें वह कालीन व कपड़ों की बुनाई कर हजारों रुपये कमाया करते थे. उसकी कमाई से उन लोगों ने खेती योग्य भूमि खरीदी मगर इसे प्रशासनिक उपेक्षा ही कहा जाएगा कि दबंगों ने समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति यानी कुष्ठ रोगियों को मारपीट कर खदेड़ दिया. लाखों की कीमत की मशीनें ही नहीं, भारी-भरकम भवन के खिड़की पल्ले तक चोरी कर लिए गए और उन बेचारों का यह कारखाना धीरे-धीरे ढहते हुए आज अपनी वीरानगी पर स्वयं आंसू बहा रहा है. शहर शाहजहांपुर से सटे निगोही मार्ग पर एक गांव है सतवां बुजुर्ग. इस मार्ग पर साल में तीन बार अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों की गाड़ियां जरूर आती हैं. बस कहने को 26 जनवरी, 15 अगस्त, 02 अक्टूबर को सरकारी कार्यक्रम के अनुसार अधिकारी आदर्श गांधी कुष्ठ आश्रम में झंडारोहण करने व कुष्ठ रोगियों को फल दवाईयां बांटने जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि अधिकारी जाते हैं नेहरू कुष्ठ आश्रम. आखिर गांधी आश्रम है कहां? शायद इस बात की जानकारी वर्तमान जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को भी नहीं है. जबकि आदर्श गांधी कुष्ठ स्वरोजगार आश्रम वहीं कुछ दूरी पर स्थित है. दो एकड़ से अधिक भूमि पर खड़े लंबे चौड़े खंडहर बताते हैं कि यहां कभी कोई आश्रम था. 22 सितम्बर 1976 को इस भवन का उद्घाटन तत्कालीन स्वायत्त व कारागार राज्यमंत्री श्रीकृष्ण गोयल ने किया था. दूसरा भवन 1980 में बना जिसकी आधारशिला रोटरी क्लब स्कॉटलैंड के जिलाधीश श्यामलाल ने रखी. भवनों पर लगे पत्थरों पर लिखी इबारत

इसकी विशालता का बखान करती है. झाड़-झंखाड़ से घिरे इन भवनों में एक दशक पूर्व ही लगी बड़ी-बड़ी मशीनों व करघों पर कालीन व वस्त्रों का निर्माण होता था. वे मशीनें आज नदारत हैं. यही नहीं, अलग-अलग बने आधा दर्जन से अधिक लंबे चौड़े भवन जिनमें कारखाने व कुष्ठ रोगियों के निवास हुआ करते थे, उनके खिड़की दरवाजे तक उखाड़ कर चोर ले गए. वहीं समीप स्थित नेहरू कुष्ठ आश्रम में बसने वाले राजाराम बताते हैं कि हम लोगन की बहुत खराब स्थिति है. मात्र वर्ष में तीन दिन अधिकारी आते हैं. उनके रहने की थोड़ी बहुत व्यवस्था तो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कर दी गई, मगर हम लोगों को खाने के लिए भीख मांगने के अलावा और कोई उपाय सूझता ही नहीं है. बता दें कि

कुष्ठ रोगियों को बसाने का बीड़ा उठाया तो मिल रही हैं धमकियां

चार दशक पूर्व जिले के कुष्ठ रोगियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निर्मित कराए गए गांधी आदर्श कुष्ठ आश्रम की वीरानगी को खत्म करने के लिए कुछ दिनों से स्वयं को आश्रम की सचिव बताने वाली कुमारी महक ने फिलहाल जयपुर से यहां आकर अपना बसेरा बनाया हुआ है. उन्होंने बताया कि उनके दादा नजीर आलम द्वारा बनाई गई सोसायटी के जरिए अथक प्रयासों के बाद इसका निर्माण कराया गया था. जब वह बड़ी हुईं तो उन्होंने अपने अन्य आश्रमों के साथ ही इस आश्रम की दुर्दशा को दूर करने का बीड़ा भी उठाया. जिसके चलते गणतंत्र दिवस पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने यहां पहुंचकर उन्हें शासन-प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया. नगर विधायक सुरेश कुमार खन्ना ने भी उन्हें भविष्य में आश्रम के लिए सोलर लाईटें स्थापित कराए जाने का भरोसा दिया. इसके इतर आश्रम की सचिव इस बात से बेहद परेशान और चिंतित दिखाई दीं कि उन्हें इस आश्रम को दोबारा संचालित करने की प्रक्रिया में आए दिन जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. कारण पूछने पर बताती हैं कि आश्रम की बेशकीमती संपत्ति पर दबंग भू-माफियाओं की नजरें गड़ी हुई हैं. उनकी मांग है कि आश्रम में एक पुलिस चौकी स्थापित कराई जाए. आश्रम की स्थापना के बारे में वह बताती हैं कि वर्ष 1976 में तत्कालीन राज्यमंत्री श्रीकृष्ण गोयल ने इसका शिलान्यास किया था. जिसकी पुष्टि वर्तमान में वहां स्थापित एक शिलापट से की जा सकती है. बाद में यहां लगभग 40 कुष्ठ रोगी हथकरघा, दरी कालीन आदि निर्मित कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे. लेकिन बेसहारा कुष्ठ रोगियों की इस संपत्ति पर कुछ दबंग भू-माफियाओं की नजर पड़ी. माफियाओं ने रात में कई बार आश्रम में निरीह कुष्ठ रोगियों पर हमले कराए. यहां तीन बार डकैती भी पड़ी. थक हारकर एक-एक करके यहां से सभी कुष्ठ रोगी अन्यत्र पलायन कर गए. जंगल के बीच खंडहरनुमा इस दयनीय आश्रम में रात्रि के वक्त आश्रम की सचिव अकेली रहती हैं. वे कहती हैं कि ऊपर वाले के भरोसे मैं यहां कुष्ठ रोगियों को दोबारा बसाने का संकल्प ले चुकी हूं और इससे मैं पीछे नहीं हटूंगी. ■

कुछ वर्ष पूर्व भी गांधी कुष्ठ आश्रम की हालत को लेकर आवाज उठाई गई थी लेकिन आज तक इसकी सुध नहीं ली गई. अब देखना है कि वर्तमान जिला प्रशासन इस आश्रम के प्रति क्या कार्रवाई करता है, ताकि एक बार फिर कुष्ठ रोगी पूर्व की भांति पुनः अपने बसेरे में रहकर रोजमर्रा के कार्यों को अंजाम देते हुए स्वावलंबी बन सकें.■

समाजवादी सरकार के प्रदेश में शिक्षा का बुरा हाल

नेता मालामाल, शिक्षा फटेहाल

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जो कुछ भी प्रयास कर रहे हों और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हों, लेकिन उनकी पकड़ से मुक्त अफसरशाही के कारण प्रदेश की शिक्षा बदहाल हो गई है. भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, नेता और दलालों का गठजोड़ शिक्षा को दीमक की तरह चाट रहा है. आज राज्य व केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाएं फेल हो रही हैं.

विगत दिनों माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले में बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार और बदलाव लाने के लिए मंत्रियों और अफसरों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का आदेश सुनाया था. लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं उसके हिसाब से तो न्यायालय का यह आदेश रही की टोकरी में जा चुका है. प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री, विधायक या अफसर ने अब तक अपने बच्चों को बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं की है. अब खबर है कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जा रही है.

प्रदेश में बेसिक शिक्षा की हालत बेहद खस्ता है. इसकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है. इन स्कूलों की हालत को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 2015 को मंत्रियों और अधिकारियों को भी इन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का आदेश सुनाया था. प्रदेश में अधिकतर प्राथमिक स्कूलों की हालत बेहद दयनीय है. ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है. आज की तारीख में प्रदेश के स्कूलों में कोई भी शिक्षक समय पर नहीं आता. मिड-डे-मील जैसी तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में भयंकर रूप से डूबी हैं. अदालत के आदेश के छह माह बीत जाने के बाद भी सरकार हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर पाई है. वास्तविकता यह है कि सरकार इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में ही नहीं है. जबकि अदालत का यह फैसला व्यापक जनहित में था, जिससे सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सके और समाज में बराबरी का वातावरण पैदा किया जा सके. बेहतर स्कूलों और शिक्षण से ही हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं. लेकिन प्रदेश के नेताओं और अफसरों को यह बात अच्छी नहीं लगी होगी और वे असहज महसूस कर रहे होंगे. जबकि यदि इस आदेश को लागू करके समाज में एक नया वातावरण पैदा किया जा सकता था.

प्रदेश में बेसिक शिक्षा की हालत बेहद खस्ता है. इसकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है. इन स्कूलों की हालत को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 2015 को मंत्रियों और अधिकारियों को भी इन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का आदेश सुनाया था. प्रदेश में अधिकतर प्राथमिक स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है. ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है. आज की तारीख में प्रदेश के स्कूलों में कोई भी शिक्षक समय पर नहीं आता.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का सीधा अर्थ यही है कि सरकार, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों की मंशा कतई नहीं है कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं. यदि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते तो इन स्कूलों की बेहतरी के लिए और अधिक प्रयास किए जाते. फिलहाल अफसर और मंत्री इन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने से से कन्नी काट रहे हैं और सरकारी स्कूलों का बुरा हाल बरकरार है.

सीएजी की कई रिपोर्टें बता रही हैं कि प्रदेश में शिक्षा के नाम पर किस प्रकार धन का बेतहाशा दुरुपयोग हुआ है. फिर वह शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण में करोड़ों रुपये खा जाने का मामला हो या फिर मिड-डे-मील में स्वास्थ्य व स्वच्छता की अनदेखी कर धन हड़पने का मामला. हर जगह हेराफेरी का गोरखधंधा सामने आ रहा है. समाजवादी सरकार अपने चार साल पूरे होने का जश्न मना रही है तो नेता, नौकरशाह और दलाल सरकारी धन समेटने में लगे हैं. सीएजी की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उच्च, बेसिक, माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितताओं, लालफीताशाही और काम की निगरानी में विफलता के कारण करोड़ों रुपये का अपव्यय हुआ है. यह हाल पूरे प्रदेश का है. लखनऊ विश्वविद्यालय में नए परिसर में पर्यावरण विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान आदि के कोर्स संचालित करने के लिए विज्ञान संकाय भवन निर्माण के लिए अक्टूबर 2007 में 8.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे. भवन का निर्माण कार्य सितंबर 2010 तक पूरा होना था, लेकिन वह नवंबर 2015 तक नहीं बन सका और 8.92 करोड़ रुपये खर्च भी हो गए. सीएजी की रिपोर्ट खुलासा कर रही है कि मिड-डे-मील के बावजूद छात्रों का नामांकन लगातार घट गया है. बच्चों के भोजन में पोषक तत्वों की कमी के अध्ययन के लिए बेसलाइन कार्य तक नहीं किया गया. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि बच्चों को 200 दिन भोजन अवश्य दिया जाए लेकिन केवल 2010-15 के मध्य औसतन 102 दिन ही मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया गया. 62

प्रतिशत स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण के दस्तावेज तक नहीं थे. 43 प्रतिशत स्कूलों में वजन नापने की मशीन नहीं मिली. 64 प्रतिशत स्कूलों में बॉडीमास इंडेक्स नहीं था. 32 प्रतिशत स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया. धन होने के बाद भी 21 प्रतिशत स्कूलों में रसोई सह-भंडार गृह नहीं थे. 42 प्रतिशत स्कूलों के पास भोजन पकाने के लिये रसोई गैस कनेक्शन तक नहीं है. इतना धन आवंटन होने के बावजूद 34 प्रतिशत स्कूलों में जल निकासी और 21 प्रतिशत में हवा और 16 प्रतिशत में रोशनी का इंतजाम तक नहीं है. आखिर समाजवादी सरकार विकास में जिस प्रकार से धन की कमी का रोना रो रही है, उसका वाजिब जवाब तो उसे ही देना होगा. अन्यथा चुनाव में जनता अपना जवाब तो सुना ही देगी. आखिर इस धन की बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी सरकार ने पूरे किए चार साल

सपा को सर्वे से मलाल

चौथी दुनिया ब्यूरो

मार्च 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई समाजवादी सरकार ने अपने चार साल पूरे कर लिए. समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने अपनी वंशवादी परम्परा को कायम रखते हुए अपने बेटे अखिलेश यादव को प्रदेश की कमान सौंपी थी. उस समय आम जनमानस में अखिलेश को लेकर कई प्रकार की बातें चल रही थीं, लेकिन अब अखिलेश अपना बड़ा कद बना कर आगे बढ़ रहे हैं. समाजवादी सरकार ने अपने चार साल के विकास कार्यक्रमों को काफी तेजी से लागू करने का एक ईमानदार प्रयास किया लेकिन यह प्रयास क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को कामयाबी दे पाएगा. यह सवाल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तिर रहा है. उधर समाजवादी सरकार के चार साल पूरे होने पर जहां सरकार व पार्टी संगठन द्वारा सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए समाजवादी विकास दिवस समारोहों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है, वहीं एक चुनावी सर्वेक्षण ने समाजवादियों के माथे पर बल ला दिया है. एबीपी न्यूज के सर्वे में आगामी चुनावों में बसपा की सत्ता में वापसी के संकेत मिल रहे हैं तथा भारतीय जनता पार्टी दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में सामने आ रही है. वहीं समाजवादी पार्टी के 80 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाने की संभावना बन रही है. वैसे भी आजकल आम जनता के बीच सरकार की जो छवि बन रही है, उसके कारण आगामी चुनाव में सपा को आघात लग सकता है. जिसके कारण सपा मुखिया मुलायम सिंह व सरकारी महकमा सतर्क हो गया है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि इस रिपोर्ट ने सही समय पर जगा दिया है. अखिलेश मानते हैं कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने के लिए यह रिपोर्ट तैयार कराई है. मुख्यमंत्री ने आईएएस वीक के दौरान अपनी चिंता से अधिकारियों को भी अवगत कराया. अधिकारियों से कहा कि वे किसी तरह की गलतफहमी न रखें, अगली सरकार भी सपा की ही होगी. उन्होंने अधिकारियों को यह कह कर सतर्क किया कि हमें सब पता है कौन क्या कर रहा है?

चुनावी सर्वे पर अखिलेश ने बसपा-भाजपा को चुनौती दी है कि वे काम से तुलना कर लें. सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए मायावती को लोगों की पहली पसंद बताया गया है. हालांकि मायावती को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मात्र एक फीसदी आगे बताया गया है. सर्वे के मुताबिक मायावती 31 फीसदी और अखिलेश 30 फीसदी लोगों के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं. सर्वे में 63 फीसदी से ज्यादा लोगों ने अखिलेश सरकार के चार साल के कार्यकाल में हुए कामकाज को अच्छा या औसत बताया है. जबकि 36 फीसदी लोगों ने इसे ख़राब या बेहद ख़राब बताया है. ज्यादातर लोगों को प्रदेश की कानून व्यवस्था से परेशानी है.

कुल मिलाकर लब्बोलुबाव यह निकल कर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो कुछ भी काम किया उनमें से कुछ को छोड़कर ज़मीन पर कम दिखा. लखनऊ में मेट्रो रेल के निर्माण में तेजी से काम हो रहा है, यह लोगों को दिख रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग बनकर तैयार हो गया है. युवाओं को आकर्षित करने के लिए लैपटॉप वितरण का काम किया गया लेकिन हाईस्कूल पास करने वाले छात्रों के लिए किया जा रहा टैबलेट वितरण का काम अधूरा ही रह गया. दूसरी ओर बेरोजगारी भत्ता पहले शुरू तो कर दिया गया लेकिन बाद में बेरोजगारी भत्ते के लिए जो मारामारी देखी गई उससे सरकार को इस योजना को वापस लेना पड़ा था, जिससे सरकार की साख में कुछ सीमा तक गिरावट भी दर्ज की गई थी. चार साल पहले माना जा रहा था कि समाजवादी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय राजनीति करने और किसी प्रकार से स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए अखिलेश को प्रदेश की कमान सौंपी थी. लेकिन 2014 में मोदी लहर ने उनके सपने को तहस-नहस कर दिया. फिलहाल सपा मुखिया मुलायम सिंह के प्रधानमंत्री बनने की संभावना तो समाप्त हो ही चुकी है और यदि 2017 में सपा की पराजय हुई तो फिर यादवों की राजनीति काफी लंबे समय तक समाप्त हो जाएगी. लेकिन लोकसभा चुनावों में पराजय के बाद हालात बदले और दबंगई तथा हनक के बल पर पंचायत चुनावों से लेकर विधान परिषद के चुनावों तक सपा ने विजय की एक नई परिभाषा भी लिख डाली.

प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में कई विभागों ने सराहनीय प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर कुछ मामले आगे बढ़ते-बढ़ते बीच में ही हांफने लग गए. जिसमें प्रदेश का शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है. समाजवादी सरकार ने लगातार दो साल तक युवा और किसान पर आधारित बजट पेश किया और किसानों तथा युवाओं के लिए कई योजनाएं पेश की. लेकिन प्रदेश का किसान तमाम योजनाओं के बाद भी बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं. एक तो मौसम की मार किसानों पर पड़ रही है, वहीं सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से किसान अलग से परेशान हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री रोज-रोज केवल केंद्र सरकार से सहायता और अतिरिक्त धन की मांग ही करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें जो दिया उसकी कभी भी दिल खोलकर तारीफ नहीं की. केंद्र-राज्य के बीच टकराव भी होते रहे लेकिन इस बीच कुछ न कुछ सौगातें भी केंद्र से मिलती रहीं.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक नई कार्य संस्कृति के सृजन का कार्य तो किया है. लेकिन विभिन्न मंत्रालयों के लिए सीएजी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उससे गलत संदेश जा रहा है कि प्रदेश का कोई भी विभाग घोटालों से बचा नहीं रह गया है. हर विभाग में वित्तीय अनियमितताओं का घालमेल है. समाजवादी सरकार ने प्रतिभाशाली साहित्यकारों, विचारकों, खिलाड़ियों, व्यापारियों, अधिवक्ताओं को सम्मान भी दिया है. समाज के कल्याण के लिए समाजवादी पेंशन योजना प्रारंभ की गई, लेकिन उसका लाभ कितने लोगों को मिला है यह तो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा. दूसरी ओर कन्या विद्या धन योजना प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में रही.

प्रदेश में बढ़ते अपराध समाजवादी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं. महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लगाने व उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1090 योजना शुरू की गई, इससे छात्राओं व महिलाओं को कुछ सहायता भी मिली, लेकिन अधिकांश महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और उनके साथ घटित कई वीभत्स घटनाओं पर अभी तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई है. इसमें सर्वाधिक चर्चित राजधानी लखनऊ के पास मोहनलालगंज की दर्दनाक घटना शामिल है. इसी प्रकार की तमाम घटनायें हुईं जिनका कोई तार्किक जवाब सरकार के पास नहीं है. अपराधी तत्व मस्त घूम रहे हैं. समाजवादी कार्यकर्ताओं की दबंगई से भी प्रदेश की जनता हलकान रही है. पुलिस पर भी बदमाश हमले कर रहे हैं. एक प्रकार से समाजवादी सरकार में सबसे बड़ी जो कमजोरी बार-बार उजागर होती है, वह है प्रदेश में हर प्रकार के अपराधों में बेतहाशा वृद्धि का होना. दूसरी ओर समाजवादी सरकार में एक बार फिर मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला. हर घटना का अनावरण समाजवादी चश्मे से किया गया. जिसके कारण प्रदेश का बहुसंख्यक समाज कुछ हद तक समाजवादी सरकार से दूर हट रहा है और प्रदेश की जनता को एक बार फिर तानाशाह मायावती ही याद आ रही हैं. यही कारण है कि आज की तारीख में बसपा नेता मायावती अतिउत्साहित हैं.

समाजवादी सरकार को सबसे बड़ा झटका न्यायपालिका की ओर से भी लगा. सरकार को न्यायपालिका से सबसे बड़ा झटका शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में लगा. फिलहाल शिक्षामित्रों के मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है. अदालतों में सरकार की नाकामी के चलते राज्य सरकार को चार साल में तीन बार महाधिवक्ता बदलने पड़ गए. ऐसा नहीं है कि समाजवादी सरकार में सारे काम खराब ही हुए हों, कुछ काम अच्छे भी हुए हैं. क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी के तहत एक ही दिन में 10 लाख पौधे लगाने का काम समाजवादी सरकार में संपन्न हुआ और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया. प्रदेश में पढ़ें बेटियां और बढ़ें बेटियां योजना भी लागू की गई है. किसानों का विकास करने के लिए प्रदेश में जनेश्वर मिश्र ग्रामीण योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, किसानों के लिए योजना का सफल संचालन किया जा रहा है, लेकिन किसान फिर भी बदहाल ही नजर आ रहा है. बुजुर्गों को तीर्थयात्रा करवाने की पहल भी समाजवादी सरकार की ओर से कि गई है. जो कि जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. समाजवादी सरकार में पर्यटन और सिनेमा जगत को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए. सपा सरकार में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर जमकर मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल भी खेला गया. प्रशासन के क्षेत्र में समाजवादी सरकार ने यादव फार्मूले को पूरी तरह से लागू कर दिया है.

विगत चुनाव प्रचार के दौरान सामजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि वह बसपा सरकार में बनवाए गए स्मारकों और पार्कों के निर्माण में हुए घोटालों और अनियमितताओं के दोषियों को जेल भेजेगी. लेकिन आज सभी आरोपी मस्ती में घूम रहे हैं. यहां तक कि मायावती सरकार की पूर्ववर्ती सरकार में जो एनआरएचएम घोटाला हुआ था, उसका मुख्य आरोपी एक बार फिर सपा सरकार में सत्ता का सुख भोगने लग गया. आज पूरा विपक्ष समाजवादी सरकार को नाकाम बता रहा है. आज पूरा विपक्ष कह रहा है कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और भ्रमित नौकरशाही अखिलेश सरकार की पूंजी बने हुए हैं. लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने विकास कार्यों और अपनी व्यक्तिगत ईमानदार छवि के कारण प्रदेश में वापसी का सपना संजो रहे हैं, लेकिन वह टेढ़ी खीर नजर आ रही है. अब जनता तो हिसाब लेगी ही, क्योंकि जनता के पैसे से समाजवादियों ने सैफई में फिल्मी कलाकारों के साथ खूब मस्ती की और रामपुर में बरतानी शान-शौकत से जन्मदिन भी मनाए. ■

चुनावी सर्वे पर अखिलेश ने बसपा-भाजपा को चुनौती दी है कि वह काम से तुलना कर लें. सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए मायावती को लोगों की पहली पसंद बताया गया है. हालांकि मायावती को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मात्र एक फीसदी आगे बताया गया है. सर्वे के मुताबिक मायावती 31 फीसदी और अखिलेश 30 फीसदी लोगों के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं. सर्वे में 63 फीसदी से ज्यादा लोगों ने अखिलेश सरकार के चार साल के कार्यकाल में हुए कामकाज को अच्छा या औसत बताया है.

चार साल घोषणाएं ही करते रह गए अखिलेश

राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सपा सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है. अखिलेश यादव पूरे कार्यकाल में घोषणाएं करते रहे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो सका. मायूसी के अलावा किसानों के हाथ और कुछ नहीं लगा. प्राकृतिक आपदा में किसान बर्बाद होता रहा लेकिन सरकार तमाशा देखती रही. गन्ना किसान मिल मालिकों और सरकार के बीच पिसता रह गया. मिल मालिक गन्ना किसानों की मोटी रकम दबाए बैठे हैं. लेकिन सरकार चीनी मिलों को ही राहत पहुंचाने का काम करती रही. गन्ना समर्थन मूल्य में तीन वर्षों में एक पाई तक नहीं बढ़ाई गई और गेहूं पर बोनस देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया. चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार फेल साबित हुई है. महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाओं ने प्रदेश की जनता को स्तब्ध कर दिया है. ■

अभी चुनाव हुए तो किसे कितनी सीट?		उत्तर प्रदेश में सीएम के लिए पहली पसंद कौन?		अभी चुनाव हुए तो किसे कितने वोट?	
सपा	80	मायावती	31 प्रतिशत	एसपी	23 प्रतिशत
बीएसपी	185	अखिलेश	30 प्रतिशत	बीएसपी	31 प्रतिशत
बीजेपी	120	राजनाथ सिंह	18 प्रतिशत	बीजेपी	24 प्रतिशत
कांग्रेस	13	वरुण गांधी	07 प्रतिशत	कांग्रेस	11 प्रतिशत
अन्य	05	स्मृति ईरानी	04 प्रतिशत	अन्य	11 प्रतिशत
कुल	403	प्रियंका गांधी	02 प्रतिशत		

feedback@chauthiduniya.com

हिंदी कहानी : क्यों दूर हुए पाठक

अनंत विजय

चंद दिनों पहले एक कहानीकार मित्र ने पूछा कि आज कैसी कहानी लिखी जानी चाहिए, ताकि पाठकों को पसंद आए? पाठकों को ध्यान में रखकर कहानी की बात पूछी गई, तो मैं चौंका, क्योंकि हिंदी कहानीकारों ने अर्से तक पाठकों की रुचियों का ध्यान ही नहीं रखा. यथार्थ के नाम पर नारेबाजी आदि जैसा कुछ लिखकर उसे कहानी के तौर पर पेश ही नहीं किया, बल्कि अपने कॉमरेड आलोचकों से प्रशंसा भी हासिल की. पाठकों से हिंदी कहानी के दूर होने की यह भी एक वजह है. हिंदी कहानी में आज कई पीढ़ियां सक्रिय हैं. एक छोर पर कृष्णा सोबती हैं, तो दूसरे छोर पर उपासना जैसी एकदम नवोदित लेखिका हैं. इस लिहाज से देखें, तो हिंदी कहानी का परिदृश्य एकदम से भरा-पूरा लगता है. बावजूद इसके, हिंदी कहानी से पाठकों का मोहभंग होने की चर्चा बहुधा होती रहती है. दरअसल, कहानी और हिंदी, दोनों ही उसी शास्त्रीयता का शिकार हो गईं. समय बदल गया, समाज बदल गया, भाषा बदल गई, लोगों का मन-मिजाज बदल गया, लेकिन हिंदी उसकी चाल में नहीं ढल पाई. जब मैं हिंदी के उस चाल में ढलने की बात करता हूं, तो उसकी शुद्धता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता. लेकिन, जिस तरह परंपराएं बदलती हैं, उसी तरह शब्द भी अपना चोला उतार कर नया चोला धारण करते हैं. जैसे सरिता नदी हो गई, जल पानी हो गया, व्योम आकाश हो गया. अब भी हिंदी में एक प्रजाति मौजूद है, जो इसकी शुद्धता और अपनी पुरातनता के साथ मौजूद रहने की जिद पाले बैठी है. वह ग़लत कर रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता. लेकिन, समय के साथ न बदलने की जिद उसे समेटती जा रही है. इसी तरह की कहानी ने आजमाया हुआ सफलता का दर्रा नहीं छोड़ा. जब भी कहानी ने अलग राह बनाई, तो लोगों ने उसे खासा पसंद किया और वह लोकप्रिय भी हुई.

दरअसल, कहानी के साथ दिक्कत यह हुई कि वह प्रेमचंद और रेणु के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई. खासकर बिहार के कहानीकार तो रेणु के ही ढर्रे पर चल रहे हैं. रेणु जिस जमाने में कहानियां लिख रहे थे, वह उस दौर में अपने परिवेश को अपनी रचनाओं में उतार रहे थे. रेणु ने अपने लेखन से कहानी की बनी-बनाई लीक छोड़ी भी थी. रेणु की सफलता के बाद उनका अनुसरण करने वालों को लगा कि कहानी लेखन का यह फॉर्मूला सफल है, तो वे उसी राह पर चल पड़े. रेणु के अनुयायियों की एक बड़ी संख्या हिंदी कहानी में इस वक्त मौजूद हैं. उक्त अनुयायियों की भाषा रेणु के जमाने की है. उनके पात्र लगभग वही भाषा बोलते हैं, जो रेणु के पात्र बोलते थे. आलोचकों को भी वही भाषा सुहाती रही, तो कहानीकारों का भी उत्साह बना रहा. लेकिन, वे यह भांप नहीं पाए कि आलोचकों को सुहाती कहानियां उन्हें वृहत्तर पाठक वर्ग से दूर करती चली गईं. अब जमाना श्री जी से फोर जी में जाने को तैयार बैठा है और हिंदी कहानी के नायक-नायिका तार के ज़रिये एक-दूसरे से संवाद करेंगे, तो पाठकों को यह अभिलेखागार की वस्तु लगेगी. अभिलेखागार में रखी वस्तुएं हमें अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करने का अवसर तो देती हैं, लेकिन साथ ही चुनौती भी देती हैं कि हमसे आगे निकल कर दिखाओ. हिंदी कहानी ने उस चुनौती को स्वीकार करने के बजाय उसका अनुसरण करना उचित समझा. हिंदी कहानी को अब यह समझना होगा कि उदारीकरण के दौर के बाद गांव के लोगों की आकांक्षाएं सातवें आसमान पर हैं, जिन्हें इंटरनेट एवं मोबाइल के विस्तार ने और हवा दी है. अब ग्रामीण परिवेश का पाठक अपने आसपास की चीजों के अलावा शहरी जीवन को भी जानना-पढ़ना चाहता है. वह अपनी दिक्कतों और अपने यथार्थ से ऊब चुका है, लिहाजा शहरी कहानियों की ओर जाना चाहता है. लेकिन, हम अब भी उसे गांव की घुट्टी पिलाने पर उतारू हैं. यह बात हिंदी के ज़्यादातर कहानीकार पकड़ नहीं पा रहे हैं. इसे चेतन भगत, रविन्द्र सिंह एवं पंकज दुबे जैसे लेखकों ने पकड़ा और गांव से शहर पहुंचने वालों की कहानी लिखकर शोहरत हासिल की.

बीच में कहानीकारों की एक पीढ़ी आई थी, जिसने अपने नए अंदाज़ से पाठकों को अपनी ओर खींचा था. उसमें मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, संजीव, सृंजय, अरुण प्रकाश, शिवमूर्ति, उदय प्रकाश आदि तो थे ही, संजय खाती ने भी उम्मीद जगाई थी. लेकिन पता नहीं, किन वजहों से उनमें से कई कहानीकारों ने लिखना ही छोड़ दिया. लेकिन, मौजूदा परिवेश में तो उक्त कथाकारों के दौर से भी ईंगो बढ़ गया है. हाल के दिनों में एक बार फिर से कुछ कहानीकारों ने अपनी कहानियों में रेणु की लीक से अलग हटने का साहस दिखाया है. समाज के बदलाव को अपनी कहानियों में पकड़ने की कोशिश की है. इन कहानीकारों में गीताश्री का नाम अग्रणी है. उदय प्रकाश के बाद गीताश्री ने हिंदी कहानी को अपनी रचनाओं के माध्यम से झकझोरा है. प्रार्थना के बाहर और गोरिल्ला प्यार गीताश्री की ऐसी कहानियां हैं, जिन्होंने हिंदी के पाठकों की रुचि के साथ क़दमताल करने की कोशिश की है. जिस तरह उदय प्रकाश ने पीली छतरी वाली लड़की में विश्वविद्यालय की राजनीति को उघाड़ा था, उसी तरह गीताश्री ने प्रार्थना के बाहर में महानगर में अपने सपने पूरे करने वाली लड़की की आज़ादी की ख्वाहिश उकेरी है. इसी तरह अगर देखें, तो गोरिल्ला

प्यार में गीताश्री ने आज की पीढ़ी और समाज में आ रहे बदलाव-बेफिक्री को उजागर किया है. गीताश्री की कहानी में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है, वह हमें हमारी विरासत के साथ-साथ आधुनिक होती हिंदी की याद भी दिलाती है. एक तरफ़ तो उनके पात्र सोशल मीडिया की भाषा में संवाद करते हैं, दूसरी तरफ़ वह बिजली के फूल खिलने जैसे मुहावरे का प्रयोग भी करती हैं, जिसका सबसे पहले प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने किया था. लेकिन, दोनों के संदर्भ अलग हैं और अर्थ भी.

गीताश्री अपनी कहानियों के माध्यम से शहर एवं ग्रामीण, दोनों परिवेश में आवाजाही करती हैं, लेकिन उनकी शहरी कहानियां पाठकों को ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि उनमें बदले हुए समय को पकड़ने की महीन कोशिश दिखाई देती है. इसी तरह अगर हम देखें, तो इंदिरा दांगी की कई कहानियों में भी समाज के बदलते हुए परिवेश को पकड़ने की कोशिश की गई है. इंदिरा दांगी की एक कहानी है शहर की सुबह, जिसमें शहरी जीवन और वहां रहने वालों के मनोविज्ञान का बेहतर चित्रण है. जयश्री राय ने भी अपनी शुरुआती कहानियों से काफी उम्मीदें जगाई थीं. जयश्री राय की भाषा, कहानियों के प्लॉट और नायिकाओं के साहसपूर्ण फ़ैसले आदि पाठकों को आकर्षित कर रहे थे. लेकिन, जयश्री राय ने अपने लिए जो चौहद्दी बनाई, उससे वह बाहर नहीं निकल पा रही हैं. उनमें संभावनाएं हैं, लेकिन सफल कहानियों के फॉर्मूले से बाहर निकल कर आगे बढ़ना होगा. इसी तरह योगिता यादव ने अपनी कहानियों में नए प्रयोग किए हैं, भाषा के स्तर पर भी, कथ्य के स्तर पर भी. योगिता यादव निरंतर लिख रही हैं और हिंदी कहानी को उनसे काफी उम्मीदें हैं. दो और कथाकारों ने अपनी कहानियों से मेरा ध्यान आकृष्ट किया, राकेश तिवारी एवं पंकज सुबीर. मुकुटधारी चूहा राकेश तिवारी की गजब की कहानी है. वह इसके एक पात्र मुक्की के बहाने कथा का ऐसा वितान खड़ा करते हैं कि पाठक चकित रह जाता है. इसी तरह महुआ घटवारिन लिखकर पंकज सुबीर ने हिंदी कहानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, पाठकों के बीच भी उसे खासा पसंद किया गया. ये चंद नाम हैं हिंदी कहानी के, जो अपने समय को पकड़ने में कामयाब हैं. हो सकता है कि ऐसी कहानियां लिखने वाले और भी लेखक होंगे. आवश्यकता इस बात की है कि आलोचकों और कहानी पर लिखने वालों को भी ऐसे कहानीकारों की पहचान कर उत्साहित करना होगा. आलोचकों को भी जंग लगे और भोथरे हो चुके मार्क्सवादी औजार अलग रखकर इन कहानियों पर विचार करना चाहिए. इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आलोचकों को अपने लेखन में प्रगतिशील बेईमानी से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कहानीकारों ने उनकी वाहवाही हासिल करने के लिए ही विषयगत प्रयोग नहीं किए, जिस तरह राजनीति में नरेंद्र मोदी और संघ की आलोचना करते ही सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसी तरह कहानीकारों को भी भोगा हुआ यथार्थ लिखते ही कहानीकार का सर्टिफिकेट मिलता रहा है. कहानी के हित में इससे अलग हटने की ज़रूरत है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

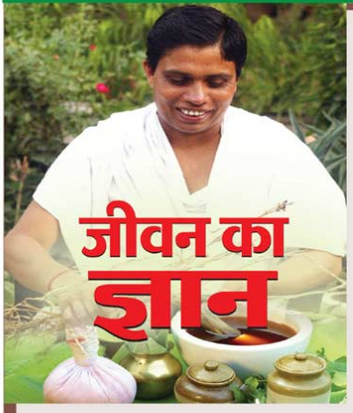

अरबी

परिचय

अरुई मूलतः उष्णकटिबंधीय एशिया में प्राप्त होता है. भारत के लगभग सभी उष्ण भागों में एवं हिमालय के आर्द्र एवं शुष्क भागों में 2500 मी की ऊंचाई तक नदियों एवं तालाबों के किनारे पाई जाती है. शाक के रूप में भारत में सर्वत्र इसकी खेती की जाती है. अरुई संपूर्ण भारतवर्ष में सब्जी के रूप में खाया जाने वाला प्रसिद्ध शाक है. इसकी पत्तियों तथा कन्दों से विविध तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं. यह सुस्वादु तथा वातकारक होता है, इसलिए अरबी से निर्मित व्यंजनों में वात के शमन के लिए अजवायन को डाला जाता है. यह वातकारक होते हुए भी हृदय रोगों में हितकर होता है. यह पौष्टिक तथा बलकारक होता है.

बाह्य स्वरूप

इसका कंदिल बहुवर्षायु शाकीय पौधा होता है. इसके पत्र सरल, आधार पर हृदयाकार, 15–40 सेमी लंबे, गहरे हरित वर्ण के, ऊर्ध्व पृष्ठ चमकरहित, अधःपृष्ठ पाण्डुर अथवा हरे वर्णयुक्त, कदाचित् अत्यधिक चमकीले, कदाचित् कृष्ण वर्ण के होते हैं. इसके फल अंडाकार, अधोमुख शंक्वाकार अथवा दीर्घायत, सस्स तथा बीज खांचेदार, संख्या में अनेक होते हैं. इसके कंद भूमिगत विभिन्न आकार एवं वर्ण के, 1–5 सेंमी लंबे, मध्य में बृहदाकार एवं चारों ओर विभिन्न आकार के होते हैं. इसके पुष्प तथा फल जुलाई से दिसंबर तक आते हैं.

आयुर्वेदीय गुण कर्म एवं प्रभाव

- अरुई गुरु, स्निग्ध तथा कफशामक होती है.
- यह रुचिकारक, विष्टंभी, बलकारक तथा विबंधकारक होती है.
- यह हृदय रोगनाशक है तथा इसे तेल में पकाकर खाने से यह अत्यंत रुचिप्रद होती है.
- इसके पत्रों का एथेनॉल-सार एलोक्सान प्रेरित मधुमेह से ग्रसित चूहों में उच्चरक्तशर्करारोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.
- इसके पत्रों का जलीय एल्कोहॉलिक-सार चिंताहार (Anxiolytic), अवसादरोधी (Anti-depressant) एवं शामक (Sedative) क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग, मात्रा एवं विधि

शिरो रोगः

- **खालित्य–** अरुई के कंद का रस निकालकर सिर पर मालिश करने से बालों का गिरना बंद हो जाता है.
- अरुई कंद स्वरस में छाछ या दही मिलाकर पीने से शिरःशूल का शमन होता है.

नेत्र रोगः

- अरुई के पत्तों तथा कंद से निर्मित शाक का सेवन नेत्र विकारों में हितकर है.

कर्ण रोगः

- **कर्णस्राव–** 1–2 बूंद अरुई पत्र-स्वरस को कान में डालने से कर्णस्राव तथा कर्णशूल में लाभ होता है.

हृदय रोगः

- अरुई पत्रों के डंठल को सुखाकर, उसका यूष बनाकर, उसमें दालचीनी, इलायची तथा अदरख डालकर पीने से यह क्षुधावर्धक और हृद्य होता है.
- **रक्तभाराधिक्य–** अरुई के कंद शाक का सेवन करने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है.

उदर रोगः

- **अतिसार–** अरुई पत्रवृंत का क्वाथ बनाकर 10–15 मिली मात्रा में सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है.
- **विबंध–** अरुई कंद का क्वाथ बनाकर पिलाने से विबंध में लाभ होता है.

त्वचा रोगः

- **व्रण–** अरुई के कोमल पत्तों का रस निकालकर व्रण के ऊपर लगाने से व्रण से रक्त का बहना बंद हो जाता है तथा घाव भी शीघ्र भर जाता है.

सर्वशरीर रोगः

- **सूजन–**अरुई के पत्ते व उसकी डंडियों का रस निकालकर उसमें नमक मिलाकर लेप करने से गांठों व पेशियों की सूजन का शमन होता है.
- ततैया या भिरड़ के दंश स्थान पर अरुई के पत्र स्वरस को लगाने से दंशजन्य वेदना का शमन होता है.
- अरुई के पत्रों तथा कंद का साग बनाकर सेवन करने से अनिद्रा का शमन होता है.
- अरुई के छोटे कंदों को भूनकर भर्ता बनाकर सेवन करने से (यह पौष्टिक होता है) दुर्बलता का शमन होता है.

विष चिकित्साः

- जहरीले जानवरों के डंक (दंश स्थान) पर अरुई की डंडियों का रस लगाने से लाभ होता है.

प्रयोज्यांग : घनकंद एवं पत्र.

मात्रा : कंद स्वरस 5 मिली, क्वाथ 10–15 मिली, पत्र स्वरस 1–2 बूंद (बाह्य प्रयोग) या चिकित्सक के परामर्शानुसार.

विशेष : *अरुई के पत्र तथा कंद में कैल्शियम ऑक्जलेट होता है, जिसके सेवन से गले तथा मुंह में सुई चुभने जैसी वेदना होती है. अतः इसका सेवन पानी में उबालकर, विधिपूर्वक, मात्रानुसार तथा चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार करना चाहिए.*

आचार्य बालकृष्ण

युवा त्वचा का राज है मेडी फेशियल

डॉ. दीपाली भारद्वाज

मेडी फेशियल मूल रूप से औषधीय ज्ञान के संयोजन और मानवीय चेहरे के सौंदर्यीकरण को एक साथ शामिल करता है. मरीज और दोस्त मेरे क्लीनिक मेडी फेशियल को जादुई फेशियल कहते हैं, क्योंकि कुछ ही सेशन के बाद जादुई परिणाम दिखने लगते हैं. वह भी बिना किसी रसायन, ब्लीच, टॉक्सिन या अतिरिक्त फेशियल मसाज के. यह सभी काम मशीनों के द्वारा होते हैं और मेरे क्लीनिक में मेडिकल उपकरणों और सुविधाओं का एक विशाल संसाधन है जिससे कि आप फेशियल के लिए अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं. हमारे पास हाइड्रा फेशियल, ऑक्सीजन फेशियल मौजूद है. साथ ही सीधे त्वचा में विटामीन सी, रलुटैथियोन और अन्य जरूरी एंटी आक्सीडेंट के इस्तेमाल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन उपकरण भी है. मेरे यहां प्लेसेंटा फेशियल भी है. इसमें शीप प्लेसेंटा जैसे उत्पाद भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं. इसके अलावा नया डॉ. ओवैगी फेशियल और कॉस्मेलन फेशियल है जो स्पेन से आता है. मैं खुद एक महिला हूं और इस नाते हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे यहां आपकी त्वचा का बेहतरीन ढंग से ख्याल रखा जाता है. इसमें साइड

इफेक्ट जैसे कोई रसायन, ब्लीच या टॉक्सिन का इस्तेमाल नहीं होता. इसके अलावा नियमित रूप से मेडी फेशियल साल भर स्वस्थ त्वचा और त्वचा की चमक को सुनिश्चित करता है. यह किसी भी प्रकार की त्वचा की समस्याओं को रोकता है. हम स्टेम सेल फेशियल भी करते हैं जिसमें मरीजों का अपने ही खून से फेशियल किया जाता है. यह प्रक्रिया बढ़ती उम्र के साथ त्वचा पर पड़ने वाले असर को रोकता है और लंबे समय तक आपकी त्वचा को युवा बनाए रखता है.

यदि बेहतर देखरेख में यह सब किया जाता है तो शून्य फीसदी साइड इफेक्ट की गुंजाइश रहती है. यहां तक कि मुंहासे से भरे चेहरों में भी हम फेशियल करते हैं और 3–4 सत्र में 80 से 90 प्रतिशत सुधार दिखता है. इसके अलावा सैलून के विपरीत इस फेशियल में कोई भाप, ब्लीच या किसी रसायन का उपयोग नहीं होता. जिससे साइड इफेक्ट का खतरा नहीं रहता है.

इसकी औसत लागत 4000 रुपये है, लेकिन हमारे क्लीनिक में इसकी लागत 3000 से 25000 रुपये तक प्रति सेशन आती है. अब, बजाय सैलून जाकर अपनी जेब कटाने की जगह आप सीधे किसी कॉस्मेटिक त्वचा विशेषज्ञ की क्लीनिक में जाएं और जुटीहीन व चमकदार त्वचा पाएं. ■

(लेखिका दिल्ली में द स्कीन एंड हेयर क्लीनिक चलाती हैं)

साईं वंदना

न्यायकर्ता केवल ईश्वर

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

जो व्यक्ति निरंतर हमारे उत्पीड़न का कारण बनते हैं, क्या उनके दुर्व्यवहार के दंड की कामना करना उचित नहीं है?

हम कौन होते हैं किसी को उसके किए का प्रतिफल देने वाले? यह कार्य तो केवल ईश्वर का है. प्रत्येक व्यक्ति अपने किए को स्वयं भोगेगा. कई बार मनुष्य स्वयं को ही विधाता समझने लगता है. न्यायकर्ता केवल ईश्वर है. हम अपने सीमित ज्ञान के आधार पर सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम भूल जाते हैं कि कभी हमने भी किसी के प्रति अन्याय किया था. कई बार हमें अपने बल एवं सामर्थ्य पर भी अभिमान होने लगता है और हम परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं. अगर शक्ति है तो उसके प्रयोग से स्वयं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए. यदि विजय प्राप्त करनी है, तो उन कारणों पर विजय प्राप्त करो, जिनके कारण हृदय में वैर भाव एवं उद्वेग उत्पन्न होता है. जीवन में कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, धैर्य के साथ परिस्थितियों के आवेग को सहन करना चाहिए. जिसे हम अपना शत्रु समझते हैं, उसके प्रति उदार होने के लिए बहुत आत्मबल की आवश्यकता होती है. आज यदि हम प्रतिक्रिया करके उद्वेग उत्पन्न करने वाले कुछ कारणों से अपने को बचा लेते हैं, तो कल संसार में उद्वेग उत्पन्न करने वाले नए कारण उत्पन्न हो जाएंगे. इस प्रकार हम कारणों के चक्र में कैद होकर रह जाएंगे.

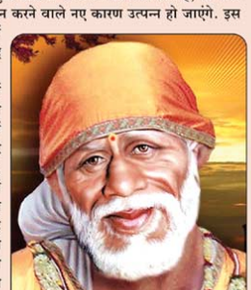

सद्गुरु हमें मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं. वे हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, जहां पहुंचकर स्वयं सभी समस्याओं का अंत हो जाता है और आनंद की धारा प्रवाहित होती है. परंतु हम इस मार्ग की तनिक-सी कंटीली झाड़ियों में अटके हुए हैं और उनके कांटों की चुभन से विकल हो रहे हैं. तनिक सी पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं. चाहते हैं कि सद्गुरु हमें पीड़ा पहुंचाने वाले कांटों को निकालें. अपना तथा सद्गुरु का समय व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं श्रद्धा एवं धीरज के मंत्र को हृदय में धारण करते हुए सद्गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं? हमारे समस्त दुःख-दर्द, धीरे-धीरे स्वतः ही विलुप्त हो जाएंगे. यदि हमारा सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है तो हमें उन्हें अपना कष्ट बतलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी. उन्हें अपने भक्तों के विषय में सब ज्ञात है. भक्तों का भार उठाने के लिए वे सदा तत्पर रहते हैं.

चरम करुणा का ही मूर्त रूप सद्गुरु होते हैं. प्राकृतिक नियम के भीतर रह कर भी कृपास्वरूप उसके परे जा कर प्राणियों के दुःख को अपने ऊ पर झेलते हैं, बदले में स्वयं के लिए बिना कुछ चाहे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और पवित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

टीम इंडिया के पुरुष क्रिकेटरों को एक टेस्ट मैच खेलने की मैच फीस 7 लाख रुपये, एक वनडे खेलने पर 4 लाख और एक टी-20 खेलने पर 2 लाख रुपये मिलते हैं. तो वहीं महिला क्रिकेटरों को एक मैच वनडे या टी-20 मैच खेलने के लिए महज 2500 रुपये ही मिलते हैं.

महिला खिलाड़ियों को किया जाता है नज़रअंदाज़

1973 में पहली बार अस्तित्व में आई विमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बीसीसीआई की मान्यता मिलने और उसके नियंत्रण में आने में 23 साल लंबा वक्त लगा. भारतीय महिला क्रिकेटरों को 2006 में पहली बार बीसीसीआई की संबद्धता मिली. बीसीसीआई का हिस्सा बनने से पहले महिला क्रिकेटरों की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब थी. लेकिन बीसीसीआई से जुड़ने के बाद महिला किक्रेटरों के जीवन में काफी सुधार देखने को मिला है. हालांकि अब भी भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेटरों के लिए बहुत कम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं.

तरुण फोर

आजकल भारत में टी-20 किक्रेट का बुखार लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है. क्योंकि भारत किक्रेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के विश्व कप की पहली बार मेजबानी कर रहा है. लेकिन इस बात से बहुत लोग अंजान थे कि पुरुषों के साथ-साथ भारत की मेजबानी में टी-20 महिला विश्व कप का आयोजन भी हो रहा है. यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम का तीनों फॉर्मेट का कप्तान कौन-कौन से खिलाड़ी हैं तो आपको इसका जवाब देने में एक सकेंड भी नहीं लगेगा. लेकिन यही सवाल महिला किक्रेट टीम के बारे में पूछा जाए तो शायद ही आप इस सवाल एक बार में सही-सही जवाब दे पाएं. इससे जाहिर हो जाता है कि क्रिकेट को धर्म माने जाने वाले इस देश में महिला किक्रेट को कितनी गंभीरता से लिया जाता है. मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी महिला क्रिकेटर सालों से देश की सेवा कर रही हैं. लेकिन आज भी उन्हें वह पहचान नहीं मिल सकी है, जिसकी वे असली हकदार हैं. विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से क्या हारी, लगा मानो कोई बड़ा धमाका हो गया हो. लेकिन दूसरी तरफ उसी दिन महिला टीम बांग्लादेश से मैच जीती थी, तो चारों तरफ ख़ामोशी पसरी थी.

1973 में पहली बार अस्तित्व में आई विमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बीसीसीआई की मान्यता मिलने और उसके नियंत्रण में आने में 23 साल लंबा वक्त लगा. भारतीय महिला क्रिकेटरों को 2006 में पहली बार बीसीसीआई की संबद्धता मिली. बीसीसीआई का हिस्सा बनने से पहले महिला क्रिकेटरों की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब थी. लेकिन बीसीसीआई से जुड़ने के बाद महिला क्रिकेटरों के जीवन में काफी सुधार देखने को मिला है. हालांकि अब भी भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेटरों के लिए बहुत कम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं. साल भर में महिला क्रिकेट टीम बहुत कम मैच खेल पाती हैं.

साल 2015 में बीसीसीआई ने पहली बार 11 महिला क्रिकेटरों को बीसीसीआई के सलाना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया. लेकिन धरती(महिला) और आकाश(पुरुष) के बीच की दूरी अभी भी पूरी नहीं हो सकी है, पुरुष और महिला क्रिकेटरों को मिलने वाले पैसों में जमीन-आसमान का अंतर है. पुरुष क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई का सलाना कॉन्ट्रैक्ट ए, बी और सी कैटेगरी में बंटा है. ए कैटेगरी में शामिल क्रिकेटरों को 1 करोड़ रुपये, बी कैटेगरी के लिए 50 लाख जबकि सी कैटेगरी के लिए 25 लाख रुपये मिलते हैं. तो वहीं महिला क्रिकेटरों के लिए ए और बी कैटिगरी बनाई गई है. इसमें महिलाओं खिलाड़ियों को 15 से 10 लाख रुपये मिलते है. अंतर सिर्फ यहीं नहीं है. टीम इंडिया के पुरुष क्रिकेटरों को एक टेस्ट मैच खेलने की मैच फीस 7 लाख रुपये, एक वनडे खेलने पर 4 लाख और एक टी-20 खेलने पर 2 लाख रुपये मिलते हैं. तो वहीं महिला क्रिकेटरों को एक मैच वनडे या टी-20 मैच खेलने के लिए महज 2500 रुपये ही मिलते हैं. बीसीसीआई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. लेकिन महिलाओं को पैसा देने, उनके लिए नियमित तौर पर मैच कराने में उनकी कभी कोई रूचि नहीं रही. हालांकि पिछले साल बीसीसीआई ने पूर्व महिला क्रिकेटरों को पेंशन देने की घोषणा की थी. जिन महिला क्रिकेटरों ने दस या इससे अधिक टेस्ट मैच खेले उन्हें प्रति माह 22,500 रुपये जबकि पांच से नौ टेस्ट मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ियों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये की धनराशि देने की घोषणा की गई थी. जबकि पुरुष खिलाड़ियों को दुगनी पेंशन मिलेगी. पुरुष और महिला क्रिकेटरों के बीच कमाई की इस खाई के बावजूद बीसीसीआई से जुड़ने से भविष्य में महिला क्रिकेटरों को भी फायदा होने की पूरी संभावना है.

आईसीसी ने वर्ल्ड टी-20 विश्व कप 2016 में महिला क्रिकेट का पहली बार टीवी पर लाइव प्रसारण करने का फैसला किया. टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार महिलाओं के मैचों को टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने महिलाओं के मैचों के टीवी पर लाइव प्रसारण की सिफारिश की थी. इससे पहले खेले गए 4 आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के महिलाओं के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों का ही लाइव प्रसारण होता था. माना जा रहा है कि इससे महिला क्रिकेट को पॉपुलर बनाने में काफी मदद मिलेगी. पुरुष टीम के मुकाबले संक्षिप्त इतिहास के बावजूद महिला टीम ने कुछ ऐसी सफलताएं पाई हैं, जिन पर गर्व किया जा सके. 1976 में महिला टीम ने पटना में वेस्टइंडीज को हराकर पहला टेस्ट जीता था तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में 25 हजार से ज्यादा दर्शक मौजूद थे. 1975 से 1986 तक महिला टीम ने कई अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. लेकिन 1986 से 1991 तक महिला टीम अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से वंचित रही. 1995 में सीमित ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में महिला टीम को पहली बार बड़ी सफलता मिली. न्यूज़ीलैंड में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने एक नई शुरुआत की. इंग्लैंड में महिला क्रिकेट संघ के इंग्लिश व वेल्स क्रिकेट बोर्ड में विलय के बाद 1999 में महिला टीम इंग्लैंड गई और उसका प्रदर्शन काफी शानदार रहा. उसने वन डे सीरिज जीती और टेस्ट सीरिज ड्रा कराई.

भारतीय महिला टीम 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरिज जीतने में कामयाब रही. वन डे क्रिकेट का एशिया कप जीतने का कारनामा अथवा 2005 की विश्व प्रतियोगिता में फाइनल तक की छलांग, किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. मिताली राज का वन डे मैचों में औसत सचिन तेंदुलकर के आसपास रहा है. लेकिन सचिन जितना मान सम्मान और पैसा मिलना तो दूर की बात रही उन्हें अरसे तक उपयुक्त कवरेज तक नहीं मिल पाया, और तो और 2012 में सचिन तेंदुलकर की सिफारिश पर उन्हें एडीडास का अनुबंध मिल पाया. महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है. दिन प्रतिदिन उनके अंदर उत्साह बढ़ रहा है. महिला क्रिकेट टीम की आईसीसी रैंकिंग में वनडे में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर हैं. टेस्ट में दूसरे स्थान पर है. टी-20 में भारत प्रथम स्थान पर है. लेकिन जब भी पुरस्कारों और सम्मान की बात आती है तो महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को नज़र अंदाज़ किया जाता है. पुरुष खिलाड़ियों को तो अकसर पुरस्कार मिलते रहते हैं लेकिन महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को यह मौका नहीं मिलता.■

विश्वकप के प्रदर्शन का स्पॉन्सरशिप पर फर्क़ पड़ेगाः मिताली

क्रिकेट में मुझे मेरे माता-पिता ने डाला था, तो उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफ़ज़ाई की लेकिन दादा-दादी को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था. उन्हें लगता था कि धूप में खेलूंगी तो काली हो जाऊंगी फिर मुझसे शादी कौन करेगा. जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो महिला क्रिकेट के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे. हम जब वह किट बैग के साथ सफ़र करती थी तो लोग पूछते थे कि आप हॉकी के खिलाड़ी हो? कोई यह नहीं सोचता कि हम क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं. महिला खिलाड़ियों में वनडे में 5000 रन पूरे करने वाली मिताली राज दुनिया की दूसरी प्लेयर हैं. मिताली ने कहा कि भारतीय महिला टीम जिस तरह से खेल रही है. उस हिसाब से हम चाहते हैं कि कम से कम सेमीफ़ाइनल तक जगह बनाएं क्योंकि पिछली बार हम सेमीफ़ाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे. इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, वो साल भर बहुत क्रिकेट खेलती हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को हमने पिछले वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेला है. ज़ाहिर है दो साल में हर टीम में बदलाव होते हैं पर हमारी तैयारी भी कम नहीं है. उनका मानना है कि यदि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अच्छा खेलती है तो टीम की ब्रैंडिंग और स्पॉन्सरशिप को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है क्योंकि अभी भी निजी स्तर पर महिला खिलाड़ियों के पास प्रायोजक नहीं हैं.

feedback@chauthiduniya.com

ओलंपिक में हिजाब पहन करेंगी तलवारबाज़ी

इब्तिहाज़ के नाम रिकॉर्ड

- वर्ल्ड चैम्पियनशिप-2015 मॉस्को: ब्रॉन्ज
- वर्ल्ड चैम्पियनशिप-2014 रूस : गोल्ड
- वर्ल्ड चैम्पियनशिप-2013 बुडापोस्ट : ब्रॉन्ज
- वर्ल्ड चैम्पियनशिप-2012 यूक्रेन : ब्रॉन्ज
- वर्ल्ड चैम्पियनशिप-2011 इटली : ब्रॉन्ज

अमेरिकी खिलाड़ी इब्तिहाज़ मुहम्मद ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वह रियो ओलंपिक में हिजाब पहनकर तलवारबाजी करती नज़र आएंगी. ऐसा करने वाली वह अमेरिका की पहली मुस्लिम हैं. 4 दिसंबर, 1985 को न्यू जर्सी में जन्मीं इब्तिहाज़ अफ्रीकी मूल की अमेरिकी हैं. इब्तिहाज़ ने लंदन ओलंपिक में 2012 के लिए भी क्वालिफाई किया था. लेकिन टूर्नामेंट के शुरू होने से एक महीने पहले वह चोटिल हो गई थी. इसी के साथ उनका सपना टूट गया था. इब्तिहाज़ ने 11 साल की उम्र में तलवारबाजी शुरू की थी. रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के बाद इब्तिहाज़ ने कहा कि मैं अमेरिका के लिए ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहती हूं. मैं सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना चाहती हूं. कामयाबी के लिए धर्म या जेंडर मायने नहीं रखता. उन्होंने कहा कि शुरुआती समय मेरे लिए आसान नहीं था. लेकिन अब जब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गई हूं, तो सब कुछ आसान नज़र आ रहा है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये कैसा खिलाड़ी

खिलाड़ी सीरीज़ की नई फिल्म *ये कैसा खिलाड़ी* भी बॉलीवुड की स्टारडम का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. लेकिन फिल्म कितना चलती है ये तो समय ही बताएगा.

अक्षय कुमार को बॉलीवुड में अगर किसी ने शोहरत दिलाई हैं, तो वो है खिलाड़ी सीरीज़ की फिल्में. हिट हो या फ्लॉप, एवरेज हों या ब्लॉकबस्टर, इन खिलाड़ी फिल्मों ने अक्षय कुमार को एक नई पहचान दी. यही कारण था कि कई सालों तक इस सीरीज़ की फिल्में सबका दिल जीतती रहीं. अक्षय कुमार के साथ इस सीरीज़ की आठ फिल्में रिलीज़ हुईं और अब इस सीरीज़ की नौंवी फिल्म भी तैयारी में है. खिलाड़ी सीरीज़ की इस अगली फिल्म का नाम है *ये कैसा खिलाड़ी*. इस बार इस खिलाड़ी सीरीज़ के हीरो अक्षय नहीं बल्कि दीपक डोबरियाल होंगे. अब आप सोचेंगे कि अक्षय की फिल्म में अक्षय नहीं! दरअसल, अक्षय कुमार की यह फिल्म शाहरुख खान की फैन से काफी ज़्यादा इंस्पायर्ड है. दीपक डोबरियाल इस फिल्म में अक्षय कुमार के सबसे बड़े फैन बने हैं. *ये कैसा खिलाड़ी* की शूटिंग आगरा में जल्द ही शुरू होगी और इसमें अक्षय कुमार एक कैमियो रोल भी करने वाले हैं.

दीपक डोबरियाल बॉलीवुड के पप्पीजी, फिल्म में अक्षय कुमार को कॉपी करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं. फिल्म में वो अक्षय की तरह कॉमेडी और स्टंट भी करने वाले हैं.■

कैटरीना को लगा झटका!

एक शैंपू कंपनी अपने विज्ञापन के जरिए रणबीर-कैटरीना के रिश्ते को कैश करना चाहती थी, लेकिन इनके रिश्तों में आई दरार के कारण अब कैटरीना और रणबीर की केमिस्ट्री झूठी नज़र आती. इसलिए कैटरीना को इस डील से हाथ धोना पड़ा.

रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कैटरीना कैफ के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं. पहले तो फितूर फ्लॉप हो गई. इसके बाद अब उनके हाथ से एक ऑफर चला गया है. दरअसल, कैटरीना और रणबीर कपूर, सैफ अली खान और करीना कपूर को एक शैंपू के एड में रिप्लेस करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. शैंपू कंपनी ने कैटरीना कैफ को इस एड से हटाने का फैसला कर लिया है. दरअसल, पहले ये कंपनी रणबीर-कैटरीना के रिश्ते को कैश करना चाहती थी, लेकिन अब उनकी केमिस्ट्री झूठी नज़र आती. ऐसे में कैटरीना कैफ को इस डील से हाथ धोना पड़ा. वहीं शाहरूख की डॉन-3 भी उनके हाथ से निकल चुकी है. फिल्मों के नाम पर उनके पास अब केवल कुछ ही फिल्में रह गई हैं जिनमें जग्गा जासूस व बार-बार देखो शामिल है.■

हॉलीडे का सीक्वल बनेगा

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी सुपरहिट फिल्म हॉलीडे के सीक्वल में काम करते नज़र आएंगे. निर्माता विपुल शाह ने बताया कि हॉलीडे-2 की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और इस बार भी अक्षय इस फिल्म से धमाल मचाएंगे. विपुल ने कहा कि फिलहाल वह अगस्त से अक्षय कुमार के साथ नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग करने जा रहे हैं और इसके बाद ही वह फिल्म हॉलीडे-2 को फ्लोर पर लेकर जाएंगे. उन्होंने बताया कि फिल्म को निर्देशित करने के लिए वह ए.आर. मुरूगोदास के पास ही जाएंगे, क्योंकि फिल्म का पहला भाग उन्होंने ही बनाया था. इस बार भी अक्षय कुमार, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं, छुट्टियों पर आएंगे और एक मिशन पर लग जाएंगे.■

2017 में होगी

अजय-ऋतिक की टक्कर

अजय VS ऋतिक

दो सुपरस्टार फिल्मों का आपस में भिड़ना अब बॉलीवुड का लेटेस्ट फैशन हो चुका है. इस लिस्ट में अब ऋतिक रोशन और अजय देवगन भी शामिल हो चुके हैं. अजय देवगन ने हाल ही में अपनी फिल्म *बादशाहो* की रिलीज़ डेट तय की थी और अब इसी डेट को राकेश रोशन ने भी ऋतिक की आने वाली फिल्म के लिए फाइनल किया है. अजय देवगन की *बादशाहो* की रिलीज़ डेट 26 जनवरी 2017 तय की गई है और इसी दिन ऋतिक रोशन की *काबिल* को भी रिलीज़ करने का मन बना लिया गया है. अजय और ऋतिक दोनों ही अपने दम पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की भीड़ लाने का और फिल्म को हिट कराने का दम रखते है. अब यह तो फिल्म की रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा कि किसमें कितना है दम!

हाल ही में इससे पहले दर्शक 2016 में आई फिल्म *दिलवाले* और *बाज़ीराव मस्तानी* की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर देख चुके हैं. जिसमें फिल्म *दिलवाले* को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. ऐसे में कोई भी अभिनेता तो नहीं चाहेगा कि उसकी फिल्म का हाल *दिलवाले* जैसा हो. अब देखना दिलचस्प होगा कि अजय और ऋतिक की फिल्में आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

सबने चुन ली थी सलमान की दोस्ती : ऐश्वर्या

बॉलीवुड के पुराने पन्ने पलटे जाएं तो सबसे कंट्रोवर्शियल बातें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप से निकलकर आती हैं. यह जोड़ी जब तक बॉलीवुड की पावर कपल थी. सब बढ़िया था, लेकिन इनके ब्रेकअप ने बहुत लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी. उस दौरान बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, प्रीती, रानी, करण, फराह, ऐश्वर्या सबका एक ग्रुप था. लेकिन ब्रेकअप के बाद अचानक से ही सबके सामने एक ही मुश्किल थी कि कौन किसकी तरफ रहना चाहता है. इन सभी स्टारों ने सलमान को चुना. इस बात से ऐश्वर्या राय को बहुत दुख हुआ और उनको काफी नुकसान भी हुआ. काफी समय तक उन्होंने बॉलीवुड में दोस्त बनाए ही नहीं. हालांकि शाहरुख-प्रीती अब फिर एक बार ऐश के दोस्त हैं. लेकिन उस दौरान सलमान की वजह से ऐश्वर्या राय को काफी नुकसान हुआ था. उनके दोस्तों ने उनका साथ तो छोड़ा ही, साथ ही उन्हें काफी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा था. जिनमें दिल ने जिसे अपना कहा, चलते-चलते, वीर ज़ारा, मुन्ना भाई-एमबीबीएस, मैं हूं ना और कल हो ना हो फिल्में शामिल थीं.■

धमाका करने की तैयारी में कपिल शर्मा

> विकास बहल और कपिल शर्मा की फिल्म को लेकर बात चल रही है. यदि सब कुछ सही रहा है तो कुछ ही समय में हम विकास बहल की फिल्म में कपिल शर्मा को देखेंगे.

कपिल शर्मा ने साल 2015 में बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया. अब्बास मस्तान की फिल्म *किस किसको प्यार करूं* 2015 की हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार है और इसका श्रेय कपिल शर्मा की बेहिसाब लोकप्रियता को दिया जा सकता है. अब जब कपिल शर्मा फिल्मों में एंट्री कर ही चुके हैं, तो सिर्फ एक हिट के साथ उनकी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली. विकास बहल और कपिल शर्मा की फिल्म को लेकर बात चल रही है. यदि सब कुछ सही रहा है तो कुछ ही समय में हम विकास बहल की फिल्म में कपिल शर्मा को देखेंगे. वहीं अब्बास मस्तान की फिल्म *किस किसको प्यार करूं-2* की तैयारी भी शुरू हो चुकी है. दर्शकों को इन फिल्मों से काफी उम्मीदे हैं, देखते हैं कपिल शर्मा दोबारा अपने फैंस को खुश कर पाएंगे या नहीं.■

फ्लैशबैक

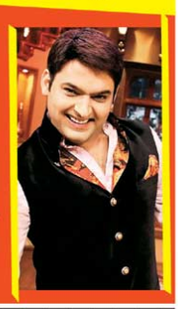

फ़ातिमा से नरगिस बनने की कहानी

भारतीय सिनेमा की सबसे पहली अभिनेत्रियों में नरगिस को याद किया जाता है, अपने सामायिक काल में वह पहली ऐसी अभिनेत्री थीं जो चुनौतीपूर्ण वाली भूमिका करना पसंद करती थीं. उन्होंने कई हिट फिल्में दीं जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया. अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाज़ा जा चुका है. श्री 420 और मदर इंडिया उनकी सबसे सफलतम फिल्में रही हैं.

नरगिस दत्त का जन्म 01 जून, 1929 को कोलकाता में हुआ था. उनका असल नाम फ़ातिमा रशीद था. उनके पिता उत्तमचंद मूलचंद, रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले समृद्ध हिंदू थे तथा माता जद्दनबाई, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थीं. फिल्मी दुनिया में नरगिस की पारी बाल कलाकार के तौर पर शुरू हुई. उनका करियर 1935 में आई फिल्म तलाश-ए-हक नाम की फिल्म से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया.

फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें जल्द ही बेबी नरगिस के नाम से पहचाना जाने लगा. सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में वह महबूब खान की फिल्म तकदीर में मोतीलाल के साथ दिखाई दीं. मदर इंडिया में राधा की भूमिका के लिए नर्गिस को फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कार मिले. इस फिल्म ने उनका जीवन बदल दिया. इसी फिल्म में अभिनेता सुनील दत्त जो की फिल्म में उनके छोटे बेटे का किरदार निभा रहे थे, शूटिंग के दौरान आग से उनकी जान बचाई थी. आगे चलकर नरगिस और सुनील दत्त ने 1958 में विवाह कर लिया. शादी के बाद सुनील दत्त के हर सुख-दुःख में नरगिस ने हमेशा साथ दिया.

पुरस्कार और सम्मान

- फिल्मफेयर पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (1958 मदर इण्डिया)
- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार - सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (1968 रात और दिन)
- अन्य पुरस्कार - कार्लोवी वैरी अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव -सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (1958 मदर इण्डिया)

फिल्मी दुनिया में नरगिस को अपनी मंजिल उस वक्त मिली जब उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्में शुरू की. हिंदी सिनेमा जगत में ये जोड़ी बहुत मशहूर हुई.

दोनों को हिंदी फिल्मों की सर्वकालीन सफल जोड़ियों में से गिना जाता है. दर्शकों ने इस जोड़ी की फिल्मों को खूब पसंद किया. इस जोड़ी की हिट फिल्मों में आग, बरसात, आह, आंवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो शामिल हैं. अभिनय से अलग होने के बाद नरगिस सामजिक कार्य में जुट गईं. उन्होंने पति सुनील दत्त के साथ अजंता कला सांस्कृतिक दल बनाया. यह दल सीमाओं पर जाकर जवानों के मनोरंजन के लिए स्टेज शो करता था. उन्हें राज्यसभा का मनोनीत सदस्य चुना गया. इसी कार्यकाल के दौरान वे गंभीर रूप से बीमार हो गईं और 3 मई 1981 को कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई.

उनकी याद में 1983 में नर्गिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई. इस प्रकार निधन के बाद भी नरगिस लोगों के दिल में बसी हुई हैं. नरगिस हिंदी सिनेमा की पहली महिला कलाकार हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया.■

feedback@chauthiduniya.com